



# Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC  
| SSC | BANK RAILWAY Exam



## WEEKLY CURRENT AFFAIRS

4 - 10 JAN 2026

1ST WEEK OF JANUARY

150+ MCQ  
with detailed  
explanation



- Banking & finance
- National
- International
- Sports





**Ques: How many lenders are live on RBI's Unified Lending Interface (ULI) platform as of December 12, 2025?**

12 दिसंबर 2025 तक RBI के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) प्लेटफॉर्म पर कितने ऋणदाता लाइव हैं?

- A) 52
- B) 58
- C) 60
- D) 64
- E) 70

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- As of December 12, 2025, a total of 64 lenders are onboard the Reserve Bank of India's Unified Lending Interface (ULI) platform.
- 12 दिसंबर 2025 तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) प्लेटफॉर्म पर कुल 64 ऋणदाता शामिल हो चुके हैं।
- These include 41 banks and 23 Non-Banking Financial Companies (NBFCs).
- इनमें 41 बैंक और 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) शामिल हैं।
- Lenders are utilising more than 136 data services through ULI across 12 different types of loan journeys.
- ULI के माध्यम से 12 प्रकार की ऋण प्रक्रियाओं में 136 से अधिक डेटा सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।
- The data services cover authentication and verification, land records from 8 States, satellite data, property search, dairy insights, transliteration, and credit guarantee services.
- डेटा सेवाओं में प्रमाणीकरण व सत्यापन, 8 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड, सैटेलाइट डेटा, संपत्ति खोज, डेयरी इनसाइट्स, ट्रांसलिटिरेशन और क्रेडिट गारंटी सेवाएं शामिल हैं।
- ULI operates on a standardised, protocol-driven, open API-based plug-and-play architecture, eliminating complex one-to-one integrations between lenders and data providers.
- ULI एक मानकीकृत, प्रोटोकॉल-आधारित, ओपन API आधारित प्लग-एंड-प्ले संरचना पर कार्य करता है, जिससे ऋणदाताओं और डेटा प्रदाताओं के बीच जटिल वन-टू-वन इंटीग्रेशन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।



**Ques: Rediff.com India Limited has received final approval from which organisation to operate as a Third-Party Application Provider (TPAP) for its digital payments platform 'RediffPay'?**

रेडिफ.कॉम इंडिया लिमिटेड को 'रेडिफपे' डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी किस संस्था से मिली है?

- A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Ministry of Electronics & IT (MeitY) / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
- C) National Payments Corporation of India (NPCI) / नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
- D) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
- E) Department of Financial Services (DFS) / वित्तीय सेवा विभाग

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Rediff.com India Limited, a subsidiary of Infibeam Avenues Limited, received final approval from the National Payments Corporation of India (NPCI) to operate as a Third-Party Application Provider (TPAP).
- इन्फिबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड की सहायक कंपनी रेडिफ.कॉम इंडिया लिमिटेड को TPAP के रूप में कार्य करने के लिए NPCI से अंतिम मंजूरी प्राप्त हुई।
- Following the approval, the company initiated Closed User Group (CUG) testing of its digital payments platform 'RediffPay'.
- मंजूरी के बाद कंपनी ने अपने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म 'रेडिफपे' का क्लोज़्ड यूज़र ग्रुप (CUG) परीक्षण शुरू किया।
- This testing phase is being conducted ahead of the public launch of RediffPay on the Unified Payments Interface (UPI).
- यह परीक्षण चरण UPI पर रेडिफपे के सार्वजनिक लॉन्च से पहले किया जा रहा है।





**Ques: Which insurance company was penalised ₹1 crore by IRDAI for serious lapses related to claims settlement, policyholder protection, and corporate governance?**

दावों के निपटान, पॉलिसीधारक संरक्षण और कॉरपोरेट गवर्नेंस में गंभीर खामियों के लिए IRDAI ने किस बीमा कंपनी पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया?

- A) Star Health and Allied Insurance / स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस
- B) Care Health Insurance / केयर हेल्थ इंश्योरेंस
- C) HDFC ERGO Health Insurance / एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस
- D) Niva Bupa Health Insurance / निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस
- E) ICICI Lombard Health Insurance / आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) imposed a penalty of ₹1 crore on Care Health Insurance following a remote inspection.
- बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने रिमोट निरीक्षण के बाद केयर हेल्थ इंश्योरेंस पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- The penalty was levied due to serious lapses in claims settlement, policyholder protection, and corporate governance standards.
- यह दंड दावों के निपटान, पॉलिसीधारक संरक्षण और कॉरपोरेट गवर्नेंस में गंभीर खामियों के कारण लगाया गया।
- The charges included failure in grievance redressal, cybersecurity lapses, lack of transparency in claims settlement, reinsurance accounting irregularities, and improper handling of unidentified proposal deposits.
- आरोपों में शिकायत निवारण में विफलता, साइबर सुरक्षा में चूक, दावों के निपटान में पारदर्शिता की कमी, पुनर्बीमा लेखांकन में अनियमितताएँ तथा अज्ञात प्रस्ताव जमा राशि के अनुचित प्रबंधन शामिल थे।





**Ques: As per RBI data, what was the total value of bank frauds reported in the first half of FY26 (H1FY26)?**

RBI के अनुसार FY26 की पहली छमाही (H1FY26) में बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की कुल राशि कितनी थी?

- A) ₹16,569 crore
- B) ₹18,336 crore
- C) ₹21,515 crore
- D) ₹25,000 crore
- E) ₹17,501 crore

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- According to RBI data, banks reported 5,092 fraud cases amounting to ₹21,515 crore during the first half of FY26 (H1FY26).
- RBI के आँकड़ों के अनुसार FY26 की पहली छमाही (H1FY26) में बैंकों ने 5,092 मामलों में ₹21,515 करोड़ की धोखाधड़ी की सूचना दी।
- The largest share of fraud value was related to advances (loans), accounting for ₹17,501 crore across 4,255 cases.
- धोखाधड़ी की सबसे बड़ी राशि ऋण/एडवांस से जुड़ी रही, जिसमें 4,255 मामलों में ₹17,501 करोड़ शामिल थे।
- Other areas of fraud included deposits, foreign exchange transactions, and card/internet-based frauds.
- धोखाधड़ी के अन्य प्रमुख क्षेत्र जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और कार्ड/इंटरनेट आधारित धोखाधड़ी रहे।
- Compared to H1FY25, when frauds worth ₹16,569 crore were reported, the amount increased while the number of cases declined in FY26.
- H1FY25 में ₹16,569 करोड़ की धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई थी, यानी FY26 में राशि बढ़ी लेकिन मामलों की संख्या घटी।
- RBI clarified that the rise in value was mainly due to reclassification and re-reporting of earlier fraud cases.
- RBI के अनुसार राशि में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पुराने मामलों का पुनर्वर्गीकरण और पुनः रिपोर्टिंग है।
- To tackle digital frauds, the AI-driven MuleHunter.ai platform has been implemented in 23 banks as of 17 December 2025 to identify mule accounts.
- डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए AI आधारित MuleHunter.ai प्लेटफॉर्म को 17 दिसंबर 2025 तक 23 बैंकों में लागू किया गया है, जो म्यूल खातों की पहचान में मदद करता है।



**Ques: 'Gaj', the premium metal credit card, has been launched by which bank and is available exclusively for which category of customers?**

'गज' प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है और यह विशेष रूप से किस वर्ग के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है?

- A) HDFC Bank – Mass Retail Customers / एचडीएफसी बैंक – सामान्य ग्राहक
- B) Axis Bank – Corporate Clients / एक्सिस बैंक – कॉर्पोरेट ग्राहक
- C) ICICI Bank – Premium Salary Account Holders / आईसीआईसीआई बैंक – प्रीमियम सैलरी खाताधारक
- D) IDFC First Bank – High-Net-Worth Individuals (HNIs) / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक – उच्च-निवल-मूल्य व्यक्ति (HNIs)
- E) SBI – Wealth Management Clients / एसबीआई – वेल्थ मैनेजमेंट ग्राहक

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- 'Gaj' is a premium metal credit card launched by IDFC First Bank Limited on an invitation-only basis.
- 'गज' एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है, जिसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने केवल आमंत्रण (इनविटेशन-ओनली) के आधार पर लॉन्च किया है।
- The card is available exclusively for High-Net-Worth Individuals (HNIs).
- यह कार्ड विशेष रूप से उच्च-निवल-मूल्य व्यक्तियों (HNIs) के लिए उपलब्ध है।
- The joining fee for the 'Gaj' credit card is ₹12,500 plus applicable GST.
- 'गज' क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग फीस ₹12,500 + लागू जीएसटी है।
- 'Gaj' represents the top tier of IDFC First Bank's premium metal credit card series known as the Ashva–Mayura–Gaj trilogy.
- 'गज' आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्रीमियम मेटल कार्ड श्रृंखला 'अश्व–मयूर–गज' ट्रिलॉजी का शीर्ष स्तर (टॉप टियर) है।

**About IDFC First Bank :**

- Established : 2015
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : V Vaidyanathan
- Tagline : Always You First





**Ques: How much does the Government of India plan to borrow through short-term Treasury Bills (T-Bills) over 12 weeks in Q4 of the current financial year?**

भारत सरकार चालू वित्त वर्ष की Q4 में 12 सप्ताह के दौरान अल्पकालिक ट्रेजरी बिल (T-Bills) के माध्यम से कितनी राशि उधार लेने की योजना बना रही है?

- A) ₹2.47 lakh crore
- B) ₹3.94 lakh crore
- C) ₹3.50 lakh crore
- D) ₹4.10 lakh crore
- E) ₹3.84 lakh crore

**Answer: Option E**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Government of India plans to borrow ₹3.84 lakh crore through short-term Treasury Bills over 12 weeks in Q4 to meet short-term funding requirements.
- भारत सरकार अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए Q4 में 12 सप्ताह के दौरान ₹3.84 लाख करोड़ के ट्रेजरी बिल जारी करेगी।
- Weekly T-Bill auctions will be in the range of ₹29,000 crore to ₹35,000 crore, as per the Finance Ministry.
- वित्त मंत्रालय के अनुसार साप्ताहिक T-Bill नीलामी ₹29,000 करोड़ से ₹35,000 करोड़ के बीच होगी।
- The planned Q4 borrowing is ₹10,000 crore lower than the ₹3.94 lakh crore raised in Q4 of the previous financial year.
- यह उधारी पिछले वित्त वर्ष की Q4 में जुटाए गए ₹3.94 लाख करोड़ से ₹10,000 करोड़ कम है।
- Earlier, the government had announced a Q3 T-Bill auction calendar of ₹2.47 lakh crore, ending on 31 December 2025.
- इससे पहले सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली Q3 T-Bill नीलामी योजना ₹2.47 लाख करोड़ की घोषित की थी।





**Ques: Who published the Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10th Edition), which provides a consolidated and comparable statistical database for Indian States and Union Territories?**

भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए समेकित एवं तुलनात्मक सांख्यिकीय डाटाबेस प्रदान करने वाली Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10वां संस्करण) किसके द्वारा प्रकाशित की गई है?

- A) Ministry of Statistics and Programme Implementation / सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  
B) NITI Aayog / नीति आयोग  
C) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय  
D) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक  
E) National Statistical Office / राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

**Answer:** Option D

**Explanation | व्याख्या:**

- The Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10th Edition) has been published by the Reserve Bank of India (RBI).
- Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10वां संस्करण) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रकाशित की गई है।
- The handbook serves as a consolidated and comparable statistical resource for Indian States and Union Territories, with time-series data available from 1951 onwards.
- यह पुस्तिका भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक समेकित एवं तुलनात्मक सांख्यिकीय संसाधन है, जिसमें 1951 से समय-श्रृंखला डेटा उपलब्ध है।
- It is prepared by the Regional Economy Monitoring Division (REMD) under the Department of Economic and Policy Research (DEPR), using inputs from RBI regional offices and multiple data sources.
- इसे आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) के अंतर्गत क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था निगरानी प्रभाग (REMD) द्वारा RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों और विभिन्न डेटा स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है।
- The 10th edition introduces a new External Sector section and adds 11 new state-wise statistical tables, enhancing analysis of regional trends and disparities.
- 10वें संस्करण में एक नया बाह्य क्षेत्र (External Sector) अनुभाग जोड़ा गया है तथा 11 नए राज्य-वार सांख्यिकीय तालिकाएँ शामिल की गई हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रवृत्तियों और असमानताओं का विश्लेषण बेहतर होता है।





**Ques: According to the Reserve Bank of India (RBI), which digital payment system accounted for the largest share in transaction volume during FY 2024–25?**

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लेन-देन की संख्या के आधार पर किस डिजिटल भुगतान प्रणाली की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही?

- A) RTGS / आरटीजीएस
- B) NEFT / एनईएफटी
- C) IMPS / आईएमपीएस
- D) UPI / यूपीआई
- E) Cheques / चेक

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- According to the RBI report, the share of small-value retail digital payments is increasing rapidly in India.
- RBI रिपोर्ट के अनुसार भारत में छोटे मूल्य के खुदरा डिजिटल भुगतानों की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ रही है।
- During FY 2024–25, digital payments recorded a growth of 17.9 percent in value terms.
- वित्त वर्ष 2024–25 में डिजिटल भुगतानों में मूल्य के आधार पर 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- Digital payments accounted for 97.6 percent of India's total payments in value terms, highlighting their dominance in the payment ecosystem.
- मूल्य के आधार पर भारत के कुल भुगतानों में डिजिटल भुगतानों की हिस्सेदारी 97.6 प्रतिशत रही, जो इनके व्यापक उपयोग को दर्शाता है।
- In volume terms, digital payments witnessed a much higher growth of 35 percent during the year.
- लेन-देन की संख्या के आधार पर डिजिटल भुगतानों में 35 प्रतिशत की तेज़ वृद्धि देखी गई।
- This surge in transaction volumes was mainly driven by the increasing use of digital modes for small-value transactions.
- यह वृद्धि मुख्य रूप से छोटे मूल्य के लेन-देन में डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के कारण हुई।
- UPI emerged as the digital payment system with the largest share in transaction volume, reflecting its widespread adoption for everyday payments.
- UPI लेन-देन की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान माध्यम बनकर उभरा, जो दैनिक भुगतानों में इसके व्यापक उपयोग को दर्शाता है।
- In contrast, RTGS accounted for the largest share in value terms, as it is primarily used for high-value transactions.





**Ques: Under the Regional Connectivity Scheme – UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik), how many routes have been operationalised across India as of 30 November?**

क्षेत्रीय संपर्क योजना – उड़ान (UDAN) के अंतर्गत 30 नवंबर तक पूरे भारत में कितने मार्ग (Routes) परिचालित किए जा चुके हैं?

- A) 512
- B) 589
- C) 651
- D) 702
- E) 725

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Regional Connectivity Scheme – UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) is a flagship initiative of the Government of India aimed at improving regional air connectivity and making air travel affordable.
- क्षेत्रीय संपर्क योजना – उड़ान (UDAN) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाना और हवाई यात्रा को किफायती बनाना है।
- As of 30 November, a total of 651 routes have been operationalised under the UDAN scheme.
- 30 नवंबर तक, UDAN योजना के अंतर्गत कुल 651 मार्ग संचालित किए जा चुके हैं।
- The scheme has connected 93 unserved and underserved airports, along with 15 heliports and 2 water aerodromes.
- इस योजना के तहत 93 गैर-सेवित और अल्प-सेवित हवाई अड्डों, 15 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम को जोड़ा गया है।
- Around 157 lakh passengers have benefited, and about 3.27 lakh UDAN flights have been operated so far.
- अब तक लगभग 157 लाख यात्रियों को लाभ मिला है और 3.27 लाख उड़ान उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं।
- In Uttar Pradesh, UDAN covers 87 routes connecting 12 airports, reflecting strong regional penetration.
- उत्तर प्रदेश में UDAN के तहत 87 मार्गों के माध्यम से 12 हवाई अड्डों को जोड़ा गया है।
- The scheme was launched on 21 October 2016 for a 10-year period and is implemented by the Ministry of Civil Aviation.
- यह योजना 21 अक्टूबर 2016 को 10 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी और इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।





**Ques: Which state has become the first in India to host the Indian Artificial Intelligence Research Organization (IAIRO), approved to be set up at GIFT City?**

भारत का पहला कौन-सा राज्य है जहाँ GIFT City में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन (IAIRO) की स्थापना को मंजूरी दी गई है?

- A) Maharashtra / महाराष्ट्र
- B) Karnataka / कर्नाटक
- C) Telangana / तेलंगाना
- D) Gujarat / गुजरात
- E) Tamil Nadu / तमिलनाडु

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Gujarat Government, led by Chief Minister Bhupendra Patel, granted in-principle approval for setting up the Indian Artificial Intelligence Research Organization (IAIRO) at GIFT City, Gandhinagar.
- मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने गांधीनगर स्थित GIFT City में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन (IAIRO) की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी।
- With this initiative, Gujarat has become the first state in India to host a dedicated AI research organization.
- इस पहल के साथ गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ एक विशेष AI अनुसंधान संस्था स्थापित की जा रही है।
- The IAIRO is scheduled to become operational from 1 January 2026.
- IAIRO का संचालन 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की योजना है।
- The organization will be set up as a non-profit Special Purpose Vehicle (SPV) under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- यह संगठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- IAIRO will be established through a tripartite partnership involving the Gujarat Government, Government of India, and the Indian Pharmaceutical Alliance (IPA).
- IAIRO की स्थापना गुजरात सरकार, भारत सरकार और इंडियन फार्मास्यूटिकल एलायंस (IPA) के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी के माध्यम से की जाएगी।
- The total five-year budget of ₹300 crore will be shared equally (33.33% each) among the three partners, with the IPA contributing ₹25 crore in 2025–26.





**Ques: Where was the maiden flight test of the Pinaka Long Range Guided Rocket (LRGR-120) successfully conducted?**

पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR-120) का प्रथम उड़ान परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक किया गया?

- A) Integrated Test Range, Chandipur / इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर
- B) Pokhran Test Range / पोखरण परीक्षण क्षेत्र
- C) Abdul Kalam Island / अब्दुल कलाम द्वीप
- D) Mahendragiri Test Facility / महेंद्रगिरि परीक्षण केंद्र
- E) Balasore Firing Range / बालासोर फायरिंग रेंज

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- The maiden flight test of the Pinaka Long Range Guided Rocket (LRGR-120) was successfully conducted at the Integrated Test Range (ITR), Chandipur.
- पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR-120) का प्रथम उड़ान परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR), चांदीपुर में सफलतापूर्वक किया गया।
- During the test, the rocket was validated for its maximum strike range of 120 kilometres.
- इस परीक्षण के दौरान रॉकेट की अधिकतम 120 किलोमीटर की मारक क्षमता का सफल सत्यापन किया गया।
- The LRGR-120 has been designed by the Armament Research and Development Establishment (ARDE) in collaboration with the High Energy Materials Research Laboratory (HEMRL), with support from the Defence Research and Development Laboratory (DRDL) and Research Centre Imarat (RCI).
- LRGR-120 को आर्मेमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ARDE) ने हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी (HEMRL) के सहयोग से विकसित किया है, जिसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी (DRDL) और रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) का भी समर्थन रहा है।
- The Pinaka Rocket System is named after "Pinaka", the celestial bow of Lord Shiva.
- पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के दिव्य धनुष 'पिनाका' से लिया गया है।
- The development of the Pinaka system began in the late 1980s by DRDO as an indigenous alternative to the Russian BM-21 'Grad' rocket system.
- पिनाका प्रणाली का विकास DRDO द्वारा 1980 के दशक के उत्तरार्ध में रूसी BM-21 'ग्रेड' प्रणाली के स्वदेशी विकल्प के रूप में शुरू किया गया था।
- The Pinaka Rocket System earned legendary status during the 1999 Kargil War for effectively neutralising enemy positions located on high-altitude mountain tops.
- 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऊँचाई पर स्थित दुश्मन ठिकानों को नष्ट करने में प्रभावी भूमिका निभाने के कारण पिनाका रॉकेट सिस्टम को विशेष पहचान मिली।





**Ques: Which major telecom policy document was released by the Department of Telecommunications (DoT) to manage and allocate radio-frequency spectrum in India with effect from 30 December 2025?**

30 दिसंबर 2025 से प्रभावी भारत में रेडियो-फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और आवंटन के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा कौन-सा प्रमुख नीति दस्तावेज जारी किया गया?

- A) National Digital Communications Policy 2024 / राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2024
- B) Indian Telegraph Spectrum Policy / भारतीय टेलीग्राफ स्पेक्ट्रम नीति
- C) National Broadband Mission Plan / राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन योजना
- D) National Frequency Allocation Plan 2025 / राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025
- E) Spectrum Harmonisation Framework / स्पेक्ट्रम समन्वय ढांचा

**Answer:** Option D

**Explanation | व्याख्या:**

- The Department of Telecommunications (DoT), under the Ministry of Communications, released the National Frequency Allocation Plan 2025 (NFAP-2025) for the management and allocation of radio-frequency spectrum in India.
- संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में रेडियो-फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और आवंटन हेतु राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 (NFAP-2025) जारी की।
- NFAP-2025 formally came into effect on 30 December 2025 and serves as a key reference for spectrum managers, wireless service providers, and telecom equipment manufacturers.
- NFAP-2025 औपचारिक रूप से 30 दिसंबर 2025 से लागू हुई और यह स्पेक्ट्रम प्रबंधकों, वायरलेस ऑपरेटर्स और दूरसंचार उपकरण निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज है।
- The plan supports the expansion of 5G, 6G, satellite services, and future communication needs, in alignment with global standards.
- यह योजना वैश्विक मानकों के अनुरूप 5G, 6G, उपग्रह सेवाओं और भविष्य की संचार आवश्यकताओं के विस्तार को समर्थन देती है।
- NFAP-2025 allocates spectrum for radio communication services across a wide frequency range from 8.3 kHz to 3000 GHz.
- NFAP-2025 के अंतर्गत 8.3 किलोहर्ट्ज़ से 3000 गीगाहर्ट्ज़ तक की आवृत्ति सीमा में विभिन्न रेडियो संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है।
- Key improvements include identification of the 6,425–7,125 MHz band for International Mobile Telecommunications (IMT) and allocation of Ka, Q, and V bands for high-throughput satellite-based services.





**Ques: Who inaugurated and flagged off the inaugural flight of the indigenous next-generation civil helicopter Dhruv-NG in Bengaluru?**

बेंगलुरु में स्वदेशी अगली पीढ़ी के नागरिक हेलीकॉप्टर ध्रुव-NG की उद्घाटन उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई?

- A) Rajnath Singh / राजनाथ सिंह
- B) Jyotiraditya Scindia / ज्योतिरादित्य सिंधिया
- C) Ram Mohan Naidu / राम मोहन नायडू
- D) Nitin Gadkari / नितिन गडकरी
- E) Ashwini Vaishnav / अश्विनी वैष्णव

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister for Civil Aviation, Ram Mohan Naidu, inaugurated and flagged off the inaugural flight of the indigenous next-generation civil helicopter Dhruv-NG at Hindustan Aeronautics Limited (HAL) facilities in Bengaluru, Karnataka.
- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) परिसर में स्वदेशी अगली पीढ़ी के नागरिक हेलीकॉप्टर ध्रुव-NG की पहली उड़ान का उद्घाटन एवं शुभारंभ किया।
- Dhruv-NG has been developed by HAL as an Advanced Light Helicopter (ALH), designed as a light twin-engine, multi-role civil helicopter in the 5.5-tonne class.
- ध्रुव-NG को HAL द्वारा उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) के रूप में विकसित किया गया है, जो 5.5 टन श्रेणी का हल्का, ट्विन-इंजन, बहुउद्देश्यीय नागरिक हेलीकॉप्टर है।
- It is powered by twin Shakti 1H1C engines and can carry up to 14 passengers, with a maximum speed of 285 km/h and a range of 630 km.
- इसमें ट्विन शक्ति 1H1C इंजन लगे हैं, यह अधिकतम 14 यात्रियों को ले जा सकता है, जिसकी अधिकतम गति 285 किमी/घंटा और रेंज 630 किमी है।
- The helicopter features a civil-certified glass cockpit, a service ceiling of 6,000 metres, and a payload capacity of up to 1,000 kg, strengthening India's indigenous civil aviation capabilities.
- यह हेलीकॉप्टर सिविल-प्रमाणित ग्लास कॉकपिट, 6,000 मीटर की सेवा ऊँचाई और 1,000 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता के साथ भारत की स्वदेशी नागरिक उड्डयन क्षमताओं को सशक्त बनाता है।

**About Hindustan Aeronautics Limited :**

- Established : 1964
- HQ : Bengaluru, Karnataka
- CMD : Dr. D.K. Sunil





**Ques : INSV Kaundinya, recently in news, is based on which historical source?**

हाल ही में समाचारों में रहा INSV कौंडिन्य किस ऐतिहासिक स्रोत पर आधारित है?

- A) Ajanta cave paintings / अजंता गुफा चित्रकारी
- B) Konark temple carvings / कोणार्क मंदिर की नक्काशी
- C) Harappan dockyard remains / हड़प्पाकालीन बंदरगाह के अवशेष
- D) Indus Valley seals / सिंधु घाटी की मुहरें
- E) Sun temple manuscripts / सूर्य मंदिर की पांडुलिपियाँ

**Answer: Option A**

**Explanation :**

- INSV Kaundinya is an engineless, indigenously built stitched sailing vessel of the Indian Navy.
- INSV कौंडिन्य भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला, स्वदेशी सिला-जुड़ा नौकायन पोत है।
- The vessel sailed on its maiden overseas voyage from Porbandar (Gujarat) to Muscat (Oman).
- यह पोत पोरबंदर (गुजरात) से मस्कट (ओमान) की अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ।
- The journey covers about 1,400 km and is expected to take around 15 days, using wind and oars for propulsion.
- यह यात्रा लगभग 1,400 किमी की है और हवा व चप्पुओं के सहारे करीब 15 दिन में पूरी होने की उम्मीद है।
- The expedition aims to revive and showcase India's ancient maritime heritage and historic sea routes linking India with Oman.
- इस अभियान का उद्देश्य भारत की प्राचीन समुद्री विरासत और भारत-ओमान के ऐतिहासिक समुद्री मार्गों को पुनर्जीवित व प्रदर्शित करना है।
- The vessel is based on a 5th-century CE ship depicted in Ajanta cave paintings.
- यह पोत अजंता गुफाओं में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी ईस्वी के जहाज़ पर आधारित है।
- INSV Kaundinya was launched in February 2025 at Goa.
- INSV कौंडिन्य को फरवरी 2025 में गोवा में लॉन्च किया गया।
- It was built using ancient stitched-shipbuilding techniques by traditional artisans under master shipwright Babu Sankaran.
- इसे प्राचीन सिले-जुड़े जहाज़ निर्माण तकनीक से मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन के मार्गदर्शन में पारंपरिक कारीगरों ने बनाया।
- The project was undertaken under a tripartite MoU between the Ministry of Culture, Indian Navy and M/s Hodi Innovations.





**Ques: Which ministry is responsible for implementing Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 4.0, under which more than 53 lakh candidates were trained in the last five years?**

पिछले पाँच वर्षों में 53 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है?

- A) Ministry of Skill Development and Entrepreneurship / कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
- B) Ministry of Education / शिक्षा मंत्रालय
- C) Ministry of Labour and Employment / श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- D) Ministry of Social Justice and Empowerment / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- E) Ministry of Youth Affairs and Sports / युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 4.0 is implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 का कार्यान्वयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- Over the last five years, more than 53 lakh candidates have been trained under PMKVY.
- पिछले पाँच वर्षों में, PMKVY के अंतर्गत 53 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।
- Around 70.5% of surveyed candidates were placed in their desired skill sectors, indicating strong placement outcomes.
- सर्वेक्षण किए गए उम्मीदवारों में से लगभग 70.5% को उनकी इच्छित कौशल क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हुआ।
- PMKVY is a flagship skill development scheme of the Government of India, launched in 2015, and implemented by the National Skill Development Corporation (NSDC).
- PMKVY भारत सरकार की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा लागू किया गया।
- The scheme focuses on short-term training, certification, and placement, aiming to upskill and reskill Indian youth for industry-relevant employment, including school dropouts.
- यह योजना अल्पकालिक प्रशिक्षण, प्रमाणन और प्लेसमेंट पर केंद्रित है तथा स्कूल छोड़ चुके युवाओं सहित भारतीय युवाओं को उद्योग-उपयुक्त कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
- Eligibility criteria include: age 14–35 years, Indian nationality, no minimum educational qualification, preference to unemployed/underemployed youth, and mandatory Aadhaar card.





**Ques: What was the theme of the 5th National Conference of Chief Secretaries held in New Delhi?**

नई दिल्ली में आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का विषय क्या था?

- A) Cooperative Federalism for New India / नए भारत के लिए सहकारी संघवाद
- B) Governance Reforms and Digital India / शासन सुधार और डिजिटल इंडिया
- C) Human Capital for Viksit Bharat / विकसित भारत के लिए मानव पूंजी
- D) Inclusive Growth and Social Justice / समावेशी विकास और सामाजिक न्याय
- E) Innovation and Sustainable Development / नवाचार और सतत विकास

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The 5th National Conference of Chief Secretaries was held in New Delhi and was chaired by Prime Minister Narendra Modi.
- 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
- The theme of the conference was “Human Capital for Viksit Bharat”, highlighting the role of human development in achieving the vision of a developed India.
- सम्मेलन का विषय “विकसित भारत के लिए मानव पूंजी” था, जो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मानव संसाधन के महत्व को दर्शाता है।
- Special emphasis was placed on five key areas: early childhood education, schooling, skilling, higher education, and sports & extracurricular activities.
- इसमें पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया: प्रारंभिक बाल शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा तथा खेल एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ।

Genius





**Ques: Which bird species' breeding habitats were approved for protection during the 68th Executive Committee meeting of the National Mission for Clean Ganga (NMCG)?**

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की 68वीं कार्यकारी समिति बैठक में किस पक्षी प्रजाति के प्रजनन स्थलों के संरक्षण को मंजूरी दी गई?

- A) Sarus Crane / सारस क्रेन
- B) Great Indian Bustard / ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
- C) Lesser Flamingo / लेसर फ्लेमिंगो
- D) Black-necked Stork / ब्लैक-नेक्ड स्टॉक
- E) Indian Skimmer / इंडियन स्किमर

Answer: Option E

**Explanation | व्याख्या:**

- The 68th Executive Committee meeting of the National Mission for Clean Ganga (NMCG) was chaired by Director General Shri Rajeev Kumar Mittal and focused on ensuring Aviral (uninterrupted) and Nirmal (unpolluted) flow of the Ganga and its tributaries.
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की 68वीं कार्यकारी समिति बैठक की अध्यक्षता महानिदेशक श्री राजीव कुमार मिश्र ने की, जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों की अविरल और निर्मल धारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
- The committee approved a pioneering project for the protection of breeding habitats of sandbar-nesting birds, specifically the Indian Skimmer.
- समिति ने रेत के टापुओं पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों, विशेष रूप से इंडियन स्किमर, के प्रजनन स्थलों के संरक्षण हेतु एक अग्रणी परियोजना को मंजूरी दी।
- Nest monitoring of the Indian Skimmer will continue in the Chambal and Lower Ganga regions and will be expanded to Bijnor, Narora, and Prayagraj.
- इंडियन स्किमर के घोंसलों की निगरानी चंबल और निचली गंगा क्षेत्रों में जारी रहेगी तथा बिजनौर, नरौरा और प्रयागराज तक इसका विस्तार किया जाएगा।
- This initiative completes NMCG's holistic faunal biodiversity framework by adding avifauna conservation to existing programmes for dolphins, turtles, and muggers.
- यह पहल NMCG के समग्र जीव-जंतु जैव-विविधता संरक्षण ढांचे को पूर्ण करती है, जिसमें डॉल्फिन, कछुए और मगरमच्छ (मगर) के साथ अब पक्षियों को भी शामिल किया गया है।
- Local communities will be trained to minimise human disturbance on sandbars and support awareness and conservation activities.





- स्थानीय समुदायों को रेत के टापुओं पर मानवीय हस्तक्षेप कम करने और जागरूकता व संरक्षण गतिविधियों में सहयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- Under Nature-Based Solutions (NbS), in-situ treatment of drains at Shastri Park, Gaushala, and Kailash Nagar/Ramesh Nagar in Delhi was approved to rejuvenate the Yamuna.
- नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस (NbS) के तहत दिल्ली में शास्त्री पार्क, गौशाला और कैलाश नगर/रमेश नगर नालों के लिए यमुना के पुनर्जीवन हेतु इन-सीटू उपचार को मंजूरी दी गई।
- Raw sewage will be treated on-site using eco-friendly methods such as rock filters, stone masonry, and aquatic plants before entering the Yamuna.
- यमुना में प्रवेश से पहले कच्चे सीवेज का उपचार रॉक फ़िल्टर, पत्थर की चिनाई और जलीय पौधों जैसी पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों से किया जाएगा।
- Revised infrastructure approvals were granted for projects in Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and West Bengal to maintain project momentum.
- परियोजनाओं की गति बनाए रखने हेतु उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को संशोधित स्वीकृति दी गई।
- A master plan was approved to restore the sanctity of the Gomti River's origin at Pilibhit in Uttar Pradesh.
- उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमती नदी के उद्गम स्थल की पवित्रता बहाल करने के लिए एक मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई।

### **About National Mission for Clean Ganga :**

- Launched in : 2011 under the Societies Registration Act 1860
- Flagship Program : Namami Gange (launched in June 2014)
- Parent Ministry : Ministry of Jal Shakti
- implemented by : National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga





**Ques : Who is the author of the political memoir “107 Days”?**

“107 डेज़” नामक राजनीतिक आत्मकथा की लेखिका कौन हैं?

- A) Hillary Clinton / हिलेरी क्लिंटन
- B) Michelle Obama / मिशेल ओबामा
- C) Kamala Harris / कमला हैरिस
- D) Nikki Haley / निक्की हेली
- E) Condoleezza Rice / कॉंडोलीज़ा राइस

**Answer:** Option C

**Explanation :**

- “107 Days” is a political memoir written by Kamala Harris.
- “107 डेज़” कमला हैरिस द्वारा लिखी गई एक राजनीतिक आत्मकथा है।
- The book reflects on the 107-day presidential campaign journey and key political experiences.
- यह पुस्तक 107 दिनों के राष्ट्रपति चुनाव अभियान और महत्वपूर्ण राजनीतिक अनुभवों पर आधारित है।
- Kamala Harris is an American politician and attorney.
- कमला हैरिस एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और वकील हैं।
- She served as the 49th Vice President of the United States from 2021 to 2025.
- उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में 2021 से 2025 तक कार्य किया।
- She served under President Joe Biden.
- उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडन के अधीन कार्य किया।
- Kamala Harris is the first woman, first African-American, and first Asian-American Vice President of the United States.
- कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला, पहली अफ्रीकी-अमेरिकी और पहली एशियाई-अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं।





## Ques Who has been appointed as the Interim Director General (DG) of the National Investigation Agency (NIA)?

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अंतरिम महानिदेशक (DG) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Sadanand Vasant Date / सदानंद वसंत दाते
- B) Rakesh Asthana / राकेश अस्थाना
- C) Ajit Doval / अजीत डोभाल
- D) Alok Verma / आलोक वर्मा
- E) Rakesh Agarwal / राकेश अग्रवाल

**Answer: Option E**

### Explanation | व्याख्या:

- Rakesh Agarwal, who is currently serving as the Special Director General of the National Investigation Agency (NIA), has been appointed as the Interim Director General (DG) of the NIA.
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में वर्तमान में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत राकेश अग्रवाल को NIA का अंतरिम महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है।
- He will hold the additional charge of Director General until a regular DG is appointed or until further orders are issued.
- वह नियमित महानिदेशक की नियुक्ति होने या आगे के आदेश जारी होने तक यह अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
- Rakesh Agarwal has replaced Sadanand Vasant Date in the position of Director General of NIA.
- राकेश अग्रवाल ने इस पद पर सदानंद वसंत दाते का स्थान लिया है।
- NIA, established in 2008, in New Delhi (Delhi), following the 26/11 Mumbai attack in Mumbai, Maharashtra. It is a premier counter-terrorism agency, which investigates terrorism, terror financing, and organized crime affecting national security.
- एनआईए की स्थापना 2008 में नई दिल्ली (दिल्ली) में 26/11 के हमले के बाद हुई थी। यह महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। यह एक प्रमुख आतंकवाद-विरोधी एजेंसी है, जो आतंकवाद, आतंकवाद वित्तपोषण और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले संगठित अपराध की जांच करती है।





Ques: Pandit Deendayal Upadhyaya National Academy of Social Security (PDUNASS) has entered into a strategic partnership with which institution to strengthen ethical governance in EPFO?

पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक््योरिटी (PDUNASS) ने EPFO में नैतिक शासन को मजबूत करने के लिए किस संस्था के साथ रणनीतिक साझेदारी की है?

- A) IC Centre for Governance (ICCFG) / आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस
- B) Indian Institute of Public Administration (IIPA) / भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
- C) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) / लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
- D) National Institute of Financial Management (NIFM) / राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान
- E) Centre for Good Governance (CGG) / सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Pandit Deendayal Upadhyaya National Academy of Social Security (PDUNASS), the apex training institution of the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), has entered into a strategic partnership with the IC Centre for Governance (ICCFG).
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की शीर्ष प्रशिक्षण संस्था पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक््योरिटी (PDUNASS) ने आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस (ICCFG) के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।
- This initiative complements the operational reforms introduced by EPFO in 2025, including the simplified withdrawal framework and the centralized pension payment system.
- यह पहल 2025 में EPFO द्वारा शुरू किए गए परिचालन सुधारों—जैसे सरलीकृत निकासी ढांचा और केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली—को पूरक बनाती है।
- As EPFO increasingly reduces manual processes through automation, the partnership emphasizes the need for higher standards of moral judgment in complex and discretionary cases.
- EPFO में स्वचालन के माध्यम से मैनुअल प्रक्रियाएँ कम होने के साथ-साथ जटिल और विवेकाधीन मामलों में उच्च नैतिक निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया गया है।



- The PDUNASS–ICCFG collaboration aims to ensure that the human element of governance keeps pace with the growing digital systems.
- PDUNASS–ICCFG सहयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन का मानवीय पक्ष डिजिटल प्रणालियों के साथ समान गति से आगे बढ़े।
- PDUNASS is the premier learning and research institute of EPFO under the Ministry of Labour & Employment, Government of India, and plays a key role in capacity building aligned with Labour Codes and Digital India initiatives.
- PDUNASS, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत EPFO की प्रमुख प्रशिक्षण एवं शोध संस्था है, जो श्रम संहिताओं और डिजिटल इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- The IC Centre for Governance (ICCFG) is a reputed non-profit institution dedicated to strengthening ethical governance through executive education and policy dialogue for senior civil servants and PSU leaders.
- आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस (ICCFG) एक प्रतिष्ठित गैर-लाभकारी संस्था है, जो वरिष्ठ सिविल सेवकों और PSU नेतृत्व के लिए कार्यकारी शिक्षा और नीति संवाद के माध्यम से नैतिक शासन को सुदृढ़ करती है।
- ICCfG's "Ethics in Public Governance" modules are widely recognised for their practical relevance and transformative impact on public administration.
- ICCfG के "एथिक्स इन पब्लिक गवर्नेंस" मॉड्यूल अपनी व्यावहारिक उपयोगिता और सार्वजनिक प्रशासन में परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध हैं।

EXAM  
Genius





**Ques: What is the total value of defence contracts signed by the Ministry of Defence for the procurement of CQB Carbines and Heavy Weight Torpedoes?**  
रक्षा मंत्रालय द्वारा CQB कार्बाइन और हेवी वेट टॉरपीडो की खरीद के लिए किए गए रक्षा अनुबंधों का कुल मूल्य कितना है?

- A) ₹3,500 crore
- B) ₹4,200 crore
- C) ₹4,666 crore
- D) ₹5,100 crore
- E) ₹6,000 crore

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Ministry of Defence signed defence contracts worth ₹4,666 crore in New Delhi to strengthen India's military capabilities.
- रक्षा मंत्रालय ने भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में ₹4,666 करोड़ के रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
- A contract worth ₹2,770 crore was signed with Bharat Forge Limited and PLR Systems Private Limited.
- ₹2,770 करोड़ का एक अनुबंध भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया।
- This contract is for the procurement of over 4 lakh Close Quarter Battle (CQB) Carbines.
- यह अनुबंध 4 लाख से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल (CQB) कार्बाइन की खरीद के लिए है।
- The CQB Carbines will be inducted into the Indian Army and Indian Navy, replacing outdated legacy weapons.
- CQB कार्बाइन भारतीय सेना और भारतीय नौसेना को प्रदान की जाएंगी, जिससे पुराने हथियारों को बदला जाएगा।
- Another contract worth ₹1,896 crore was signed with WASS Submarine Systems S.R.L. of Italy.
- ₹1,896 करोड़ का एक अन्य अनुबंध इटली की WASS Submarine Systems S.R.L. के साथ किया गया।





**Ques: Who became the highest wicket-taker in Women's T20 International cricket by claiming her 152nd wicket?**

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 152वां विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनीं?

- A) Deepti Sharma / दीप्ति शर्मा
- B) Ellyse Perry / एलिस पेरी
- C) Jhulan Goswami / झूलन गोस्वामी
- D) Megan Schutt / मेगन शुट
- E) Anisa Mohammed / अनिसा मोहम्मद

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- Indian women's cricket achieved a major milestone as Deepti Sharma became the highest wicket-taker in Women's T20 International cricket.
- भारतीय महिला क्रिकेट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं।
- Deepti Sharma achieved this landmark during the 5th T20I match against Sri Lanka at Thiruvananthapuram.
- दीप्ति शर्मा ने यह उपलब्धि तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए 5वें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हासिल की।
- She claimed her 152nd T20I wicket, surpassing Australia's Megan Schutt, who earlier held the record with 151 wickets.
- उन्होंने अपना 152वां टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की मेगन शुट (151 विकेट) का रिकॉर्ड तोड़ा।
- With this achievement, Deepti Sharma now stands alone at the top of the all-time wicket-takers list in Women's T20Is.
- इस उपलब्धि के साथ दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वकालिक सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं।





**Ques: Who was Bangladesh's first female Prime Minister, who served two terms and was later honoured with the 'Mother of Democracy' award?**

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थीं, जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए और बाद में 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' सम्मान से सम्मानित हुईं?

- A) Sheikh Hasina / शेख हसीना
- B) Rasheda Choudhury / राशिदा चौधरी
- C) Benazir Bhutto / बेनज़ीर भुट्टो
- D) Khaleda Mashraf / खालिदा मशरफ
- E) Begum Khaleda Zia / बेगम खालिदा जिया

**Answer:** Option E

**Explanation | व्याख्या:**

- Former Prime Minister of Bangladesh, Begum Khaleda Zia, chairperson of the Bangladesh Nationalist Party (BNP), passed away at the age of 80 in Dhaka, Bangladesh.
- बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में ढाका में निधन हो गया।
- She served as the Prime Minister of Bangladesh twice — first from 1991 to 1996 and later from 2001 to 2006.
- उन्होंने दो बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया — 1991 से 1996 तक और पुनः 2001 से 2006 तक।
- She joined the Bangladesh Nationalist Party in 1982; the party was founded by Ziaur Rahman.
- उन्होंने 1982 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में प्रवेश किया, जिसकी स्थापना जियाउर रहमान ने की थी।
- In 2022, she was honoured with the 'Mother of Democracy' award by the Canadian Human Rights International Organization (CHRIO).
- वर्ष 2022 में उन्हें कैनेडियन ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन (CHRIO) द्वारा 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- Begum Khaleda Zia was Bangladesh's first female Prime Minister and the second female Prime Minister in the Muslim world after Benazir Bhutto.
- बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और मुस्लिम विश्व में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री थीं।





**Ques: The nationwide campaign “आपकी पूँजी, आपका अधिकार” (Your Money, Your Right) was concluded by which department?**

“आपकी पूँजी, आपका अधिकार” अभियान का समापन किस विभाग द्वारा किया गया?

- A) Department of Economic Affairs (DEA) / आर्थिक कार्य विभाग
- B) Department of Financial Services (DFS) / वित्तीय सेवाएँ विभाग
- C) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
- D) Ministry of Corporate Affairs / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
- E) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Department of Financial Services (DFS) concluded the nationwide campaign “आपकी पूँजी, आपका अधिकार” on January 1, 2026.
- वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) ने “आपकी पूँजी, आपका अधिकार” राष्ट्रीय अभियान का समापन 1 जनवरी 2026 को किया।
- The campaign was launched on October 4, 2025, at Gandhinagar, Gujarat, and concluded on December 31, 2025, spanning three months.
- यह अभियान 4 अक्टूबर 2025 को गांधीनगर, गुजरात में शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ, जिसकी अवधि तीन महीने रही।
- The strategy was built on three pillars: Awareness, Access, and Action, guided by the principle of Antyodaya.
- यह रणनीति तीन स्तंभों—जागरूकता, पहुँच और कार्रवाई—पर आधारित थी, जिसे अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित किया गया।
- The campaign was conducted in phases across 748 districts and helped return around ₹4,200 crore of unclaimed assets to rightful owners or their heirs.
- यह अभियान देश के 748 जिलों में चरणबद्ध रूप से चलाया गया, जिससे लगभग ₹4,200 करोड़ की लावारिस संपत्ति वास्तविक हकदारों या उनके उत्तराधिकारियों को लौटाई गई।
- At the start of the campaign, it was estimated that the Indian financial system held over ₹1.84 lakh crore in unclaimed assets (including bank deposits, insurance, and dividends).
- अभियान की शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में ₹1.84 लाख करोड़ से अधिक की लावारिस संपत्ति (बैंक जमा, बीमा और लाभांश सहित) मौजूद थी।





**Ques: Which institution, in partnership with IDFC First Bank, launched a new cohort under the IGNITE programme to support technology startups?**

IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में IGNITE कार्यक्रम के तहत नए स्टार्ट-अप समूह (कोहोर्ट) की शुरुआत किस संस्था ने की?

- A) Foundation for Innovation and Technology Transfer (FITT), IIT Delhi / फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (FITT), आईआईटी दिल्ली
- B) Indian Institute of Science (IISc) Bengaluru / भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
- C) NITI Aayog / नीति आयोग
- D) Atal Innovation Mission / अटल इनोवेशन मिशन
- E) Startup India / स्टार्टअप इंडिया

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Foundation for Innovation and Technology Transfer (FITT), the technology transfer and incubation arm of IIT Delhi, launched a new cohort of 15 startups under the Innovation Growth & Nurturing Initiative for Technology Entrepreneurs (IGNITE) programme.
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और इनक्यूबेशन इकाई FITT ने IGNITE कार्यक्रम के तहत 15 स्टार्ट-अप्स के नए कोहोर्ट की शुरुआत की।
- The programme has been launched in partnership with IDFC First Bank.
- यह कार्यक्रम IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है।
- IGNITE is being implemented as part of IDFC First Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, in collaboration with FITT.
- IGNITE कार्यक्रम को IDFC फर्स्ट बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल के अंतर्गत FITT के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
- Under the programme, each selected startup receives non-dilutive funding of up to ₹30 lakh.
- इस कार्यक्रम के तहत चयनित प्रत्येक स्टार्ट-अप को ₹30 लाख तक की नॉन-डायल्यूटिव फंडिंग प्रदान की जाती है।
- Mentorship is provided by IIT faculty, industry experts, and CSR leaders from IDFC First Bank.
- IIT के संकाय सदस्यों, उद्योग विशेषज्ञों और IDFC फर्स्ट बैंक के CSR लीडर्स द्वारा मेंटरशिप प्रदान की जाती है।



**Ques: Which two institutions signed a Memorandum of Understanding to implement a nationwide Contact Point Verification system for Informal Micro Enterprises (IMEs)?**

कौन-सी दो संस्थाओं ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (IMEs) के लिए देशव्यापी कॉन्टैक्ट प्वाइंट वेरिफिकेशन प्रणाली लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?

- A) Department of Posts and RBI / डाक विभाग और RBI
- B) Department of Posts and SIDBI / डाक विभाग और SIDBI
- C) SIDBI and NABARD / SIDBI और NABARD
- D) Ministry of MSME and SIDBI / MSME मंत्रालय और SIDBI
- E) India Post Payments Bank and SIDBI / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और SIDBI

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Department of Posts and the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) signed a landmark MoU to implement a nationwide Contact Point Verification system.
- डाक विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने देशव्यापी कॉन्टैक्ट प्वाइंट वेरिफिकेशन प्रणाली लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- The initiative targets Informal Micro Enterprises registered on the Udyam Assist Platform (UAP).
- यह पहल उद्योगम असिस्ट प्लेटफॉर्म (UAP) पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को लक्षित करती है।
- The objective is to provide banks and NBFCs with reliable and verified data, enabling them to extend credit under Priority Sector Lending with greater confidence.
- इसका उद्देश्य बैंकों और NBFCs को विश्वसनीय एवं सत्यापित डेटा उपलब्ध कराना है, जिससे वे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आसानी से ऋण प्रदान कर सकें।
- The app captures geo-tagged photographs of business premises to prevent ghost or fraudulent registrations.
- ऐप व्यवसाय स्थल की जियो-टैग्ड तस्वीरें लेता है, जिससे फर्जी या “घोस्ट” पंजीकरण रोके जा सकें।
- After successful verification, IMEs receive a Udyam Assist Certificate, which is treated at par with regular Udyam Registration for banking purposes.
- सफल सत्यापन के बाद IMEs को उद्योगम असिस्ट प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, जिसे बैंकिंग उद्देश्यों के लिए सामान्य उद्योगम पंजीकरण के समकक्ष माना जाता है।





## About SIDBI :

- Established : 1990
- HQ : Lucknow, Uttar Pradesh
- Chairman & MD : Manoj Mittal



EXAM  
Genius





**Ques: Which country has introduced a new national currency with redesigned banknotes removing portraits of former leaders and undergoing redenomination?**

किस देश ने पूर्व नेताओं के चित्र हटाकर और पुनर्मूल्यांकन (रेडिनोमिनेशन) के साथ नई राष्ट्रीय मुद्रा शुरू की है?

- A) Lebanon / लेबनान
- B) Iraq / इराक
- C) Syria / सीरिया
- D) Jordan / जॉर्डन
- E) Egypt / मिस्र

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Syria has introduced a new national currency with redesigned banknotes.
- सीरिया ने नई डिज़ाइन वाली राष्ट्रीय मुद्रा की शुरुआत की है।
- The new banknotes have completely removed the portraits of ousted leader Bashar al-Assad and his father Hafez al-Assad, which earlier appeared on the 2,000 and 1,000 pound notes.
- नए बैंकनोटों से अपदस्थ नेता बशर अल-असद और उनके पिता हाफ़िज़ अल-असद के चित्र हटा दिए गए हैं, जो पहले क्रमशः 2000 और 1000 पाउंड के नोटों पर थे।
- The redesigned currency now features agricultural and cultural symbols such as roses, wheat, olives, oranges, and mulberries, reflecting Syria's historical heritage.
- नई मुद्रा में गुलाब, गेहूं, जैतून, संतरे और शहतूत जैसे कृषि एवं सांस्कृतिक प्रतीक दर्शाए गए हैं, जो सीरिया की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं।
- The currency has undergone redenomination by removing two zeros to simplify daily transactions.
- दैनिक लेनदेन को सरल बनाने के लिए मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, जिसमें दो शून्य हटाए गए हैं।
- Under the new system, 100 old Syrian pounds are equal to 1 new Syrian pound.
- नई व्यवस्था के अनुसार 100 पुराने सीरियाई पाउंड = 1 नया सीरियाई पाउंड है।
- New denominations include 10, 25, 50, 100, 200, and 500 Syrian pounds.
- नई मुद्रा के मूल्यवर्ग 10, 25, 50, 100, 200 और 500 सीरियाई पाउंड हैं।
- The exchange period began on January 1, 2026, and will continue for 90 days, during which both old and new banknotes will circulate simultaneously.
- विनिमय अवधि 1 जनवरी 2026 से शुरू हुई है और 90 दिनों तक चलेगी, इस दौरान पुराने और नए दोनों नोट साथ-साथ प्रचलन में रहेंगे।



**Ques: Under the RBI's Scale-Based Regulation (SBR) framework for NBFCs, which layer accounts for the largest share of total NBFC assets?**

आरबीआई के स्केल-बेस्ड रेगुलेशन (SBR) ढांचे के तहत एनबीएफसी की कुल परिसंपत्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा किस लेयर का है?

- A) Base Layer (NBFC-BL) / बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल)
- B) Middle Layer (NBFC-ML) / मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल)
- C) Upper Layer (NBFC-UL) / अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल)
- D) Top Layer / टॉप लेयर
- E) All layers have equal share / सभी लेयरों का समान हिस्सा है

Answer: Option B

**Explanation | व्याख्या:**

- The Scale-Based Regulation (SBR) framework for NBFCs was introduced by the RBI in 2022 and classifies NBFCs into layers based on size, risk profile, and systemic importance.
- स्केल-बेस्ड रेगुलेशन (SBR) ढांचा आरबीआई द्वारा 2022 में शुरू किया गया था, जो एनबीएफसी को आकार, जोखिम प्रोफाइल और प्रणालीगत महत्व के आधार पर विभिन्न लेयरों में वर्गीकृत करता है।
- The Middle Layer (NBFC-ML) includes all deposit-taking NBFCs and non-deposit-taking NBFCs with assets of ₹1,000 crore and above.
- मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) में सभी जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी तथा ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक परिसंपत्ति वाली गैर-जमा एनबीएफसी शामिल हैं।
- This layer accounts for the largest share, i.e., 64.6% of total NBFC assets.
- इस लेयर का कुल एनबीएफसी परिसंपत्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा है, जो 64.6% है।
- The Base Layer has a share of 5.2%, while the Upper Layer accounts for 30.2% of total NBFC assets.
- बेस लेयर का हिस्सा 5.2% है, जबकि अपर लेयर का कुल परिसंपत्तियों में 30.2% हिस्सा है।





**Ques: Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL) is India's first NBFC dedicated exclusively to which sector?**

सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) भारत का पहला एनबीएफसी किस क्षेत्र के लिए समर्पित है?

- A) Road Infrastructure / सड़क अवसंरचना
- B) Power & Energy / ऊर्जा एवं विद्युत
- C) Maritime Sector / समुद्री क्षेत्र
- D) Aviation Sector / विमानन क्षेत्र
- E) Railway Infrastructure / रेलवे अवसंरचना

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL) has formally commenced its lending operations, marking a historic milestone.
- सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) ने औपचारिक रूप से अपने ऋण परिचालन की शुरुआत की है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
- It is India's first Non-Banking Financial Company (NBFC) dedicated exclusively to the maritime sector.
- यह भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, जो विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र को समर्पित है।
- SMFCL approved loans worth ₹4,300 crore during its 51st Board Meeting and is targeting a loan book of ₹8,000 crore by the end of the current financial year.
- SMFCL ने अपनी 51वीं बोर्ड बैठक में ₹4,300 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं और चालू वित्त वर्ष के अंत तक ₹8,000 करोड़ के ऋण पोर्टफोलियो का लक्ष्य रखा है।
- The Board has approved an overall borrowing limit of ₹25,000 crore.
- बोर्ड ने कुल ₹25,000 करोड़ की उधारी सीमा को मंजूरी दी है।
- Major beneficiaries include a Greenfield Port Project with an allocation of ₹4,000 crore, Dredging Corporation of India (₹150 crore), and Goa Shipyard (₹110 crore) for indigenous shipbuilding.
- प्रमुख लाभार्थियों में ₹4,000 करोड़ का ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (₹150 करोड़) और स्वदेशी जहाज निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड (₹110 करोड़) शामिल हैं।
- SMFCL is the nodal agency for the Maritime Development Fund (MDF) with a total corpus of ₹25,000 crore, comprising the Maritime Investment Fund (₹20,000 crore) and the Interest Incentivisation Fund (₹5,000 crore).





**Ques: What was the total number of UPI transactions recorded in December 2025, marking an all-time high?**

दिसंबर 2025 में UPI पर दर्ज किए गए कुल लेनदेन की संख्या कितनी थी, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है?

- A) 18.45 billion
- B) 19.80 billion
- C) 20.12 billion
- D) 21.63 billion
- E) 22.90 billion

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- India's home-grown Unified Payments Interface (UPI) recorded an all-time high transaction volume of 21.63 billion transactions in December 2025.
- भारत के स्वदेशी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने दिसंबर 2025 में 21.63 बिलियन लेनदेन के साथ अब तक का सर्वोच्च स्तर दर्ज किया।
- The total transaction value during the month stood at ₹27.97 lakh crore.
- इस महीने के दौरान कुल लेनदेन मूल्य ₹27.97 लाख करोड़ रहा।
- Transaction volumes grew by 29 per cent year-on-year, while transaction value increased by 20 per cent.
- लेनदेन की संख्या में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लेनदेन मूल्य 20 प्रतिशत बढ़ा।
- On average, UPI handled about 698 million transactions per day with a daily transaction value of ₹90,217 crore.
- औसतन, UPI ने प्रतिदिन लगभग 698 मिलियन लेनदेन संभाले, जिनका दैनिक मूल्य ₹90,217 करोड़ रहा।
- In the calendar year 2025, UPI recorded around 228 billion transactions worth nearly ₹300 lakh crore, compared to 172 billion transactions worth ₹246.82 lakh crore in 2024.
- कैलेंडर वर्ष 2025 में UPI पर लगभग 228 बिलियन लेनदेन दर्ज किए गए, जिनका मूल्य करीब ₹300 लाख करोड़ था, जबकि 2024 में 172 बिलियन लेनदेन ₹246.82 लाख करोड़ के थे।





**Ques: Who has been appointed as the new Chief Executive Officer (CEO) of Berkshire Hathaway after legendary investor Warren Buffett resigned?**

दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट के इस्तीफे के बाद बर्कशायर हैथवे के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Charlie Munger / चार्ली मंगर
- B) Ajit Jain / अजीत जैन
- C) Gregory Abel / ग्रेगरी एबल
- D) Howard Buffett / हॉवर्ड बफेट
- E) Mark Carney / मार्क कार्नी

Answer: Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- Legendary investor Warren Buffett has resigned as the Chief Executive Officer (CEO) of Berkshire Hathaway.
- दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से इस्तीफा दे दिया है।
- Warren Buffett had been leading Berkshire Hathaway since 1965, shaping it into one of the world's most successful conglomerates.
- वॉरेन बफेट 1965 से बर्कशायर हैथवे का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने इसे विश्व की सबसे सफल कंपनियों में बदल दिया।
- Gregory Abel has been appointed as the new CEO of Berkshire Hathaway following Buffett's resignation.
- वॉरेन बफेट के इस्तीफे के बाद ग्रेगरी एबल को बर्कशायर हैथवे का नया CEO नियुक्त किया गया है।
- Prior to this appointment, Gregory Abel served as Vice Chairman and was widely regarded as Buffett's successor.
- इस नियुक्ति से पहले ग्रेगरी एबल उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और उन्हें बफेट का उत्तराधिकारी माना जाता था।





**Ques: The first-ever Vande Bharat Sleeper Train will operate between which two cities?**

पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो शहरों के बीच संचालित होगी?

- A) New Delhi – Mumbai / नई दिल्ली – मुंबई
- B) Guwahati – Howrah / गुवाहाटी – हावड़ा
- C) Chennai – Bengaluru / चेन्नई – बेंगलुरु
- D) Patna – Kolkata / पटना – कोलकाता
- E) Secunderabad – Visakhapatnam / सिकंदराबाद – विशाखापट्टनम

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister for Railways, Information & Broadcasting, and Electronics & Information Technology, Shri Ashwini Vaishnaw, announced that the first-ever Vande Bharat Sleeper Train will operate between Guwahati (Assam) and Howrah (West Bengal).
- केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी (असम) और हावड़ा (पश्चिम बंगाल) के बीच चलेगी।
- The announcement was made at Rail Bhawan, New Delhi, while extending New Year greetings.
- यह घोषणा नई दिल्ली स्थित रेल भवन में नववर्ष की शुभकामनाओं के दौरान की गई।
- The Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi will flag off the train in January.
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जनवरी माह में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
- The train will consist of 16 coaches: 11 AC three-tier, 4 AC two-tier, and 1 AC first-class coach, with a total capacity of about 823 passengers.
- ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे—11 एसी थ्री-टियर, 4 एसी टू-टियर और 1 एसी फर्स्ट क्लास—जिसकी कुल यात्री क्षमता लगभग 823 होगी।
- The Vande Bharat Sleeper Train has been developed by Bharat Earth Movers Limited (BEML) using Integral Coach Factory (ICF) technology.
- वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का विकास भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) द्वारा इंटिग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) तकनीक के माध्यम से किया गया है।
- It is a semi-high-speed train with a design speed of up to 180 kmph.
- यह एक सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन है, जिसकी डिजाइन गति 180 किमी प्रति घंटा तक है।





**Ques: Which institution has partnered with Vertiv to establish the Centre for Cooling Solutions focused on AI-powered data centres?**

AI-संचालित डेटा केंद्रों के लिए कूलिंग सॉल्यूशंस सेंटर स्थापित करने हेतु Vertiv ने किस संस्थान के साथ साझेदारी की है?

- A) Indian Institute of Technology Delhi / भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
- B) Indian Institute of Technology Bombay / भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे
- C) Indian Institute of Science Bengaluru / भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु
- D) National Institute of Technology Surathkal / राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सुरथकल
- E) Indian Institute of Technology Madras / भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास

**Answer: Option B**

Explanation | व्याख्या:

- The Centre for Cooling Solutions has been established at the Indian Institute of Technology Bombay in partnership with global infrastructure solutions company Vertiv.
- सेंटर फॉर कूलिंग सॉल्यूशंस की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में वैश्विक इन्फ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस कंपनी Vertiv के सहयोग से की गई है।
- The centre focuses on developing advanced cooling technologies for Artificial Intelligence (AI)-powered data centres.
- यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डेटा केंद्रों के लिए उन्नत शीतलन तकनीकों के विकास पर केंद्रित है।
- The initiative comes amid rapid AI adoption in Indian businesses, leading to rising thermal and power challenges in data centres.
- यह पहल भारतीय व्यवसायों में AI के तेज़ी से अपनाए जाने और डेटा केंद्रों में बढ़ती तापीय व ऊर्जा चुनौतियों के संदर्भ में शुरू की गई है।
- GPU power consumption is expected to rise sharply by 2025, increasing the need for efficient cooling solutions.
- 2025 तक GPU की ऊर्जा खपत में तेज़ वृद्धि की संभावना है, जिससे प्रभावी कूलिंग समाधानों की आवश्यकता बढ़ गई है।
- The initial project involves designing a dry cooler with a 40 kilowatt liquid cooling capacity, tested at the Heat Pump Laboratory of IIT Bombay.
- प्रारंभिक परियोजना में 40 किलोवाट तरल शीतलन क्षमता वाले ड्राई कूलर का डिज़ाइन शामिल है, जिसका परीक्षण IIT बॉम्बे की हीट पंप प्रयोगशाला में किया जाएगा।
- Industry-level evaluation of the solution will be carried out at Vertiv's facility in Pune.
- उद्योग स्तर पर इस समाधान का मूल्यांकन Vertiv की पुणे स्थित सुविधा में किया जाएगा।



**Ques: The redeveloped 'Batadrava Than', inaugurated recently, is the birthplace of which Vaishnavite saint?**

पुनर्विकसित 'बटद्रवा थान' किस वैष्णव संत की जन्मस्थली है?

- A) Srimanta Sankardeva / श्रीमंत शंकरदेव
- B) Madhavdeva / माधवदेव
- C) Chaitanya Mahaprabhu / चैतन्य महाप्रभु
- D) Ramananda / रामानंद
- E) Vallabhacharya / वल्लभाचार्य

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister Amit Shah inaugurated the redeveloped Batadrava Than at Borduwa village in Nagaon district, Assam.
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नागांव जिले के बोरदुवा गांव में स्थित पुनर्विकसित बटद्रवा थान का उद्घाटन किया।
- Batadrava Than is the sacred birthplace of Vaishnavite saint Srimanta Sankardeva and is a major cultural and religious landmark of Assam.
- बटद्रवा थान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की पवित्र जन्मस्थली है और असम का एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल है।
- The site promotes Assamese literature, music, dance, and the spiritual teachings of Srimanta Sankardeva.
- यह स्थल असमिया साहित्य, संगीत, नृत्य और श्रीमंत शंकरदेव की आध्यात्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा देता है।
- Batadrava Than is an important part of Assam's Vaishnavite pilgrimage circuit, which includes Borduwa, Majuli's monastic centres, and Koch Behar.
- बटद्रवा थान असम के वैष्णव तीर्थ परिपथ का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें बोरदुवा, माजुली के मठ और कूच बिहार शामिल हैं।
- The redevelopment project, named Mahapurush Srimanta Sankardeva Abhirbhav Kshetra, was completed at a cost of over ₹222 crore.
- 'महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव अभिर्भाव क्षेत्र' नामक पुनर्विकास परियोजना ₹222 करोड़ से अधिक की लागत से पूरी की गई।
- Srimanta Sankardeva (1449–1568) founded Ekasarana (Neo-Vaishnavism) and enriched Assamese culture through Sattriya dance, Borgeet, and Ankia Naat.
- श्रीमंत शंकरदेव (1449–1568) ने एकशरण (नव-वैष्णववाद) की स्थापना की और सत्रिया नृत्य, बोरगीत तथा अंकीय नाट के माध्यम से असमिया संस्कृति को समृद्ध किया।





**Ques: Where was the 'Cyient AI Labs (CyAILS) – VijAlpatha' pilot initiative launched to promote AI, STEM and Robotics education in government schools?**

'Cyient AI Labs (CyAILS) – VijAlpatha' पायलट पहल को सरकारी स्कूलों में AI, STEM और रोबोटिक्स शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहाँ लॉन्च किया गया?

- A) Amaravati PU College, Bengaluru / अमरावती पीयू कॉलेज, बेंगलुरु
- B) Hosapete taluk, Vijayanagara, Karnataka / होसपेट तालुक, विजयनगर, कर्नाटक
- C) Kalaburagi, Karnataka / कलबुर्गी, कर्नाटक
- D) Mysuru, Karnataka / मैसूरु, कर्नाटक
- E) Hubballi, Karnataka / हुब्बल्ली, कर्नाटक

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Nirmala Sitharaman, launched the 'Cyient AI Labs (CyAILS) – VijAlpatha' pilot initiative at a girls' government school in Hosapete taluk of Vijayanagara district, Karnataka.
- केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के विजयनगर जिले के होसपेट तालुक स्थित एक बालिका सरकारी विद्यालय में 'Cyient AI Labs (CyAILS) – विजAIपथ' पायलट पहल का शुभारंभ किया।
- The initiative aims to democratise access to Artificial Intelligence, Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM), and Robotics education in government schools.
- इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (STEM) और रोबोटिक्स शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।
- VijAlpatha has been launched collaboratively by the Cyient Foundation and the Government of Karnataka.
- विजAIपथ को सायेंट फाउंडेशन और कर्नाटक सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है।
- The programme is designed as a three-year pilot with an approximate budget of ₹1 crore.
- यह कार्यक्रम लगभग ₹1 करोड़ के बजट के साथ तीन वर्षीय पायलट परियोजना के रूप में तैयार किया गया है।
- It is structured in two phases: Phase 1 involves pilot implementation in five schools, while Phase 2 focuses on national-level expansion as a benchmark model.
- यह पहल दो चरणों में संरचित है—चरण 1 में पाँच स्कूलों में पायलट कार्यान्वयन और चरण 2 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के रूप में विस्तार देना शामिल है।
- The programme benefits over 2,000 students from Classes 6 to 10, including nearly 1,200 girls at Amaravati PU College, Bengaluru.
- इस कार्यक्रम से कक्षा 6 से 10 तक के 2,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे, जिनमें बेंगलुरु के अमरावती पीयू कॉलेज की लगभग 1,200 छात्राएँ शामिल हैं।





**Ques: Which hospital achieved a historic medical milestone by performing India's first-ever 3D Flex Aqueous Angiography integrated with iStent?**

किस अस्पताल ने iStent के साथ भारत की पहली 3D फ्लेक्स एक्वियस एंजियोग्राफी कर ऐतिहासिक चिकित्सा उपलब्धि हासिल की?

- A) Army Hospital (Research & Referral), Delhi Cantt / आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल), दिल्ली कैंट  
B) All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi / अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली  
C) Safdarjung Hospital, New Delhi / सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली  
D) Command Hospital, Pune / कमांड अस्पताल, पुणे  
E) Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh / स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

Answer: Option A

**Explanation | व्याख्या:**

- The Ophthalmology Department at the Army Hospital (Research & Referral), Delhi Cantt, performed India's first-ever 3D Flex Aqueous Angiography combined with iStent surgery.
- दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) के नेत्र विज्ञान विभाग ने iStent के साथ भारत की पहली 3D फ्लेक्स एक्वियस एंजियोग्राफी सर्जरी की।
- This marks the first integration in India of 3D Flex Aqueous Angiography with the iStent, a tiny titanium implant used in glaucoma treatment.
- यह भारत में पहली बार 3D फ्लेक्स एक्वियस एंजियोग्राफी को ग्लूकोमा उपचार में प्रयुक्त छोटे टाइटेनियम इम्प्लांट iStent के साथ जोड़े जाने का उदाहरण है।
- The procedure used a stand-mounted Spectralis System, which maps the eye's drainage pathways in real time using a safe dye.
- इस प्रक्रिया में स्टैंड-माउंटेड स्पेक्ट्रलिस सिस्टम का उपयोग किया गया, जो सुरक्षित डायी की मदद से आंख के ड्रेनेज मार्गों का रीयल-टाइम मानचित्रण करता है।
- A 3D operating microscope was also employed to provide surgeons with a high-definition, magnified view of the eye's internal structures.
- सर्जनों को आंख की आंतरिक संरचनाओं का उच्च-रिज़ॉल्यूशन और विस्तृत दृश्य देने के लिए 3D ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का भी उपयोग किया गया।
- This achievement represents a major advancement in advanced ophthalmic imaging and minimally invasive glaucoma surgery in India.
- यह उपलब्धि भारत में उन्नत नेत्र इमेजिंग और न्यूनतम इनवेसिव ग्लूकोमा सर्जरी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।



**Ques: As of 31 October 2025, what was India's total installed electricity generation capacity, and what major renewable energy milestone did the country achieve in 2025?**

31 अक्टूबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी और 2025 में देश ने नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा कौन-सा प्रमुख लक्ष्य हासिल किया?

- A) 4,85,000 MW; 40% non-fossil capacity in 2025
- B) 5,05,023 MW; 50% installed electricity capacity from non-fossil sources
- C) 5,20,000 MW; 45% renewable capacity achieved
- D) 4,95,600 MW; 500 GW renewable capacity achieved
- E) 5,10,000 MW; NDC target achieved exactly on time

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- As of 31 October 2025, India's total installed electricity generation capacity stood at 5,05,023 megawatt (MW).
- 31 अक्टूबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट (MW) थी।
- Of this, 2,45,600 MW came from fossil-fuel-based sources, while 2,59,423 MW was from non-fossil fuel sources.
- इसमें 2,45,600 MW जीवाश्म ईंधन आधारित और 2,59,423 MW गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से था।
- Renewable Energy (RE) alone accounted for 2,50,643 MW of installed capacity.
- नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2,50,643 MW रही।
- India achieved a key milestone in June 2025, with 50% of its installed electricity capacity coming from non-fossil sources, more than 5 years ahead of its Nationally Determined Contributions (NDCs) target under the Paris Agreement.
- भारत ने जून 2025 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब उसकी 50% स्थापित बिजली क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से हो गई—यह पेरिस समझौते के तहत NDC लक्ष्य से 5 वर्ष से अधिक पहले है।
- India's long-term national target is to achieve 500 gigawatt (GW) non-fossil energy capacity by 2030.
- भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
- To promote renewable energy, the government has waived Inter-State Transmission System (ISTS) charges for solar and wind projects commissioned by 30 June 2025, green hydrogen projects till December 2030, and offshore wind projects till December 2032.





**Ques: PathGennie, recently in news, is related to which field?**

हाल ही में चर्चा में रहा PathGennie किस क्षेत्र से संबंधित है?

- A) Space exploration / अंतरिक्ष अन्वेषण
- B) Climate modelling / जलवायु मॉडलिंग
- C) Drug discovery / दवा खोज
- D) Cyber security / साइबर सुरक्षा
- E) Quantum computing / क्वांटम कंप्यूटिंग

**Answer: Option C**

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Science and Technology has developed a new open-source software called PathGennie.
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने PathGennie नामक नया ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है।
- PathGennie is designed to fast-track drug discovery by accurately simulating molecular processes.
- PathGennie को आणविक प्रक्रियाओं के सटीक सिमुलेशन के माध्यम से दवा खोज को तेज करने के लिए बनाया गया है।
- The software predicts how drug molecules unbind from protein targets without using artificial bias.
- यह सॉफ्टवेयर बिना किसी कृत्रिम पक्षपात के यह अनुमान लगाता है कि दवा अणु प्रोटीन टारगेट से कैसे अलग होते हैं।
- It uses direction-guided adaptive sampling to generate realistic reaction pathways within picoseconds.
- यह दिशा-निर्देशित अनुकूली सैंपलिंग तकनीक का उपयोग कर पिकोसेकंड में यथार्थवादी रिएक्शन पाथवे तैयार करता है।
- PathGennie also provides quick estimates of drug residence time and relative binding strength (koff).
- PathGennie दवाओं के रेजिडेंस टाइम और सापेक्ष बाइंडिंग स्ट्रेंथ (koff) का त्वरित अनुमान भी देता है।
- Being open-source, it promotes collaborative research and innovation in drug development.
- ओपन-सोर्स होने के कारण यह दवा विकास के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है।





**Ques: What is the full form of Mission Karmayogi launched by the Government of India?**

मिशन कर्मयोगी का पूर्ण रूप क्या है, जिसे भारत सरकार ने शुरू किया है?

- A) National Programme for Civil Services Capacity Building / राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- B) National Policy for Civil Services Capability Building / राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता नीति
- C) National Programme for Capacity Building of Bureaucracy / नौकरशाही क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम
- D) National Platform for Civil Services Training / राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण मंच
- E) New Programme for Civil Services Reforms / नई सिविल सेवा सुधार योजना

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- Mission Karmayogi is officially known as the National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB).
- मिशन कर्मयोगी का आधिकारिक नाम राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB) है।
- It was launched by the Government of India in September 2020 as a major administrative reform initiative. With a Budget of ₹510.86 crore (2020–2025)
- इसे भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में एक प्रमुख प्रशासनिक सुधार पहल के रूप में शुरू किया गया था।
- The objective of Mission Karmayogi is to build the capacity of civil servants to meet evolving citizen-centric governance needs.
- मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सिविल सेवकों की क्षमता का विकास करना है ताकि वे बदलती नागरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
- The mission follows a competency-driven, role-based approach rather than a rule-based training system.
- यह मिशन नियम-आधारित प्रशिक्षण के बजाय दक्षता-आधारित और भूमिका-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है।
- It covers Group A to Group C civil services and emphasises continuous learning and upskilling.
- यह समूह A से समूह C तक की सिविल सेवाओं को कवर करता है और निरंतर सीखने व कौशल उन्नयन पर बल देता है।
- Learning under Mission Karmayogi is enabled through a single digital platform called iGOT Karmayogi, supporting online, face-to-face and blended modes.





**Ques: Who was awarded the IFFCO Sahitya Samman 2025?**

IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया?

- A) Ankita Jain / अंकिता जैन
- B) Mridula Garg / मृदुला गर्ग
- C) Maitreyi Pushpa / मैत्रेयी पुष्पा
- D) Pratibha Ray / प्रतिभा राय
- E) Uday Prakash / उदय प्रकाश

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- IFFCO (Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited), India's leading fertiliser sector cooperative, conferred the IFFCO Sahitya Samman 2025.
- उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी सहकारी संस्था IFFCO ने IFFCO साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया।
- The award was presented to renowned Hindi fiction writer Maitreyi Pushpa for her outstanding contribution to literature.
- यह सम्मान हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया।
- At the same ceremony, the IFFCO Yuva Sahitya Samman was awarded to Ankita Jain.
- इसी समारोह में IFFCO युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को प्रदान किया गया।
- Ankita Jain was honoured for her book "Oh Re! Kisan".
- अंकिता जैन को उनकी पुस्तक "Oh Re! Kisan" के लिए सम्मानित किया गया।
- The awards were presented by IFFCO Chairman Dilip Sanghani.
- यह पुरस्कार IFFCO के चेयरमैन दिलीप संघानी द्वारा प्रदान किए गए।
- The objective of these awards is to promote contemporary Hindi literature and encourage young literary talent.
- इन पुरस्कारों का उद्देश्य समकालीन हिंदी साहित्य को बढ़ावा देना और युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना है।





**Ques: The Market Access Support (MAS) Scheme is a part of which larger government mission?**

मार्केट एक्सेस सपोर्ट (MAS) योजना किस व्यापक सरकारी मिशन का हिस्सा है?

- A) National Foreign Trade Policy Mission / राष्ट्रीय विदेशी व्यापार नीति मिशन
- B) Export Promotion Mission / निर्यात प्रोत्साहन मिशन
- C) Make in India Export Mission / मेक इन इंडिया निर्यात मिशन
- D) MSME Development Mission / एमएसएमई विकास मिशन
- E) Production Linked Incentive (PLI) Mission / उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) मिशन

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Market Access Support (MAS) Scheme aims to strengthen India's export ecosystem by improving global reach, export visibility, market access, and long-term competitiveness.
- मार्केट एक्सेस सपोर्ट (MAS) योजना का उद्देश्य भारत के निर्यात पारितंत्र को सुदृढ़ करना है, जिसमें वैश्विक पहुंच, निर्यात दृश्यता, बाजार तक पहुंच और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता शामिल है।
- The scheme has a total outlay of ₹4,531 crore and will be implemented during FY 2026–31, spanning six years.
- इस योजना का कुल परिव्यय ₹4,531 करोड़ है और इसे FY 2026–31 की अवधि (6 वर्ष) में लागू किया जाएगा।
- MAS Scheme is a component of the ₹25,060 crore Export Promotion Mission approved by the Union Cabinet in November 2025.
- MAS योजना ₹25,060 करोड़ के निर्यात प्रोत्साहन मिशन का हिस्सा है, जिसे नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई थी।
- The scheme supports activities such as international trade fairs and exhibitions, buyer-seller meets, mega reverse buyer-seller meets in India, and trade delegations to priority and emerging markets.
- यह योजना अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों, खरीदार-विक्रेता बैठकों, भारत में मेगा रिवर्स खरीदार-विक्रेता बैठकों तथा प्राथमिक और उभरते बाजारों में व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को समर्थन देती है।
- MSMEs and first-time exporters are the primary beneficiaries, with a mandatory minimum of 35% MSME participation in supported events.





**Ques: From which date did the first batch of provisions of the National Sports Governance Act (NSGA), 2025 come into force in India?**

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम (NSGA), 2025 के पहले चरण के प्रावधान भारत में किस तिथि से लागू हुए?

- A) August 18, 2025
- B) October 2, 2025
- C) December 31, 2025
- D) January 1, 2026
- E) January 26, 2026

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Central Government officially notified the commencement of select provisions of the National Sports Governance Act (NSGA), 2025, marking a major shift from executive guidelines to a statutory framework for sports administration in India.
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम (NSGA), 2025 के कुछ प्रावधानों को आधिकारिक रूप से लागू किया, जिससे भारत के खेल प्रशासन में कार्यकारी दिशानिर्देशों से वैधानिक ढांचे की ओर ऐतिहासिक बदलाव हुआ।
- The Act was originally notified in the Official Gazette on August 18, 2025.
- यह अधिनियम पहली बार 18 अगस्त 2025 को राजपत्र (Official Gazette) में अधिसूचित किया गया था।
- To ensure a smooth transition, the government decided to implement the Act in a phased manner, with the first set of critical provisions becoming operational from January 1, 2026.
- सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अधिनियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत पहले चरण के महत्वपूर्ण प्रावधान 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुए।
- Union Sports Minister Mansukh Mandaviya termed the NSGA as the “single biggest sporting reform” in India’s history.
- केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने NSGA को भारत के इतिहास का “सबसे बड़ा खेल सुधार” बताया।
- The activated provisions establish high-powered regulatory bodies and impose strict statutory requirements on sports federations to retain recognition and funding.
- लागू किए गए प्रावधान उच्च स्तरीय नियामक निकायों की स्थापना करते हैं और खेल महासंघों पर मान्यता व वित्तपोषण बनाए रखने हेतु कड़े वैधानिक नियम लागू करते हैं।





- As per the Act, the Executive Committee strength is capped at 15 members, with mandatory inclusion of at least two sportspersons of merit and four women members.
- अधिनियम के अनुसार कार्यकारी समिति के सदस्यों की संख्या अधिकतम 15 होगी, जिसमें कम से कम दो उत्कृष्ट खिलाड़ी और चार महिलाओं का होना अनिवार्य है।
- The age limit for office-bearers is generally 70 years (extendable to 75 years if permitted by international federations), and office-bearers can serve a maximum of three consecutive terms (12 years).
- पदाधिकारियों के लिए सामान्य आयु सीमा 70 वर्ष है (अंतरराष्ट्रीय महासंघ की अनुमति होने पर 75 वर्ष तक), तथा वे अधिकतम तीन लगातार कार्यकाल (12 वर्ष) तक ही सेवा दे सकते हैं।
- For the first time, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) is also expected to come under the regulatory ambit of this Act to ensure transparency and dispute resolution.
- पहली बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भी पारदर्शिता और विवाद समाधान के लिए इस अधिनियम के नियामक दायरे में लाए जाने की संभावना है।

### **National Sports Governance Act, 2025 :**

- Ministry : Ministry of Youth Affairs and Sports
- Main Objective : Align Indian sports with the Olympic and Paralympic Charters.
- Legal Status : Replaces the National Sports Development Code of India, 2011
- Tribunal Head : Must be a sitting or former Supreme Court Judge or Chief Justice of a High Court.
- Appeals : Decisions of the National Sports Tribunal can be appealed in the Supreme Court.
- Strategic Aim : Supporting India's bid to host the 2036 Summer Olympics.





**Ques: A rare Clouded Leopard was recently spotted for the first time in which reserve forest?**

हाल ही में दुर्लभ क्लाउडेड लेपर्ड पहली बार किस रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में देखा गया?

- A) Manas Reserve Forest / मानस रिज़र्व फ़ॉरेस्ट
- B) Kaziranga National Park / काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
- C) Kakoi Reserve Forest / काकोई रिज़र्व फ़ॉरेस्ट
- D) Nameri National Park / नामेरी राष्ट्रीय उद्यान
- E) Dibru-Saikhowa National Park / डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- A rare Clouded Leopard was recently spotted and captured on camera traps in Kakoi Reserve Forest, Assam.
- असम के काकोई रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में दुर्लभ क्लाउडेड लेपर्ड कैमरा ट्रैप में दर्ज किया गया।
- This marks the first-ever recorded presence of the Clouded Leopard in Kakoi Reserve Forest.
- यह काकोई रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में क्लाउडेड लेपर्ड की पहली आधिकारिक दर्ज उपस्थिति है।
- The sighting highlights the rich biodiversity and ecological significance of the forest region.
- यह दृश्य इस वन क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व को दर्शाता है।
- The Clouded Leopard (*Neofelis nebulosa*) is listed as Vulnerable on the IUCN Red List.
- क्लाउडेड लेपर्ड (*Neofelis nebulosa*) को IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है।
- The species is known for its elusive behaviour and arboreal (tree-dwelling) lifestyle.
- यह प्रजाति अपनी दुर्लभ प्रकृति और वृक्षों पर रहने की आदत के लिए जानी जाती है।
- The discovery reinforces the need for conservation and habitat protection in Assam's forests.
- यह खोज असम के वनों में संरक्षण और आवास सुरक्षा की आवश्यकता को और सुदृढ़ करती है।





**Ques: Pariksha Pe Charcha (PPC) 2026, which recorded over 3 crore registrations, is conducted through which online platform?**

परीक्षा पे चर्चा (PPC) 2026, जिसमें 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित की जाती है?

- A) National Digital Education Portal / राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा पोर्टल
- B) DIKSHA Platform / दीक्षा प्लेटफॉर्म
- C) MyGov Innovate Portal / मायगव इनोवेट पोर्टल
- D) SWAYAM Portal / स्वयं पोर्टल
- E) e-Pathshala / ई-पाठशाला

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Pariksha Pe Charcha (PPC), the flagship annual interaction led by Prime Minister Narendra Modi, achieved a historic milestone with over 3 crore registrations for its 2026 (9th) edition as of December 30, 2025.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित वार्षिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा (PPC) ने 30 दिसंबर 2025 तक अपने 9वें संस्करण (PPC 2026) के लिए 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया।
- The registrations include around 2.85 crore students from Classes 6 to 12, nearly 17 lakh teachers, and about 3.5 lakh parents.
- पंजीकरण में कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 2.85 करोड़ छात्र, करीब 17 लाख शिक्षक और लगभग 3.5 लाख अभिभावक शामिल हैं।
- The registration process opened on December 1, 2025, and is scheduled to close on January 11, 2026.
- पंजीकरण प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 को शुरू हुई और 11 जनवरी 2026 को समाप्त होगी।
- PPC 2026 is being conducted online through the MyGov Innovate portal, encouraging participatory engagement.
- PPC 2026 को मायगव इनोवेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, जिससे सहभागिता को बढ़ावा मिलता है।
- The 9th edition invites essays and questions on themes such as making exams a celebration, freedom fighters, Clean India and environment, and digital learning.



**Ques: Under which mission has India promoted large-scale recycling of coconut waste as a key component of the circular economy?**

किस मिशन के अंतर्गत भारत ने नारियल अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर पुनर्चक्रण को परिपत्र अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक बनाया है?

- A) AMRUT Mission / अमृत मिशन
- B) Jal Jeevan Mission / जल जीवन मिशन
- C) National Bio-Energy Mission / राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा मिशन
- D) Smart Cities Mission / स्मार्ट सिटीज़ मिशन
- E) Swachh Bharat Mission–Urban 2.0 / स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0

**Answer:** Option E

**Explanation | व्याख्या:**

- Under the leadership of the Ministry of Housing and Urban Affairs, coconut waste recycling is being promoted under Swachh Bharat Mission–Urban (SBM-U) 2.0 as a pillar of the circular economy.
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नेतृत्व में, स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (SBM-U) 2.0 के अंतर्गत नारियल अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को परिपत्र अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनाया गया है।
- Coconut husks account for about 3–5% of India's daily municipal wet waste (around 1.6 लाख टन), rising to 6–8% in coastal cities.
- नारियल के छिलके भारत के दैनिक नगर निकाय गीले कचरे का लगभग 3–5% हिस्सा हैं, जो तटीय शहरों में 6–8% तक पहुँच जाता है।
- India produced over 21,000 million coconuts in 2024–25, with Karnataka emerging as the largest producer, followed by Tamil Nadu, Kerala, and Andhra Pradesh.
- वर्ष 2024–25 में भारत ने 21,000 मिलियन से अधिक नारियल का उत्पादन किया, जिसमें कर्नाटक शीर्ष उत्पादक रहा, उसके बाद तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश रहे।
- India contributes over 40% of global coir production, while the global coir market is valued at USD 1.45 billion (₹12,000 करोड़) in 2025.
- भारत वैश्विक कॉयर (Coir) उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देता है, जबकि 2025 में वैश्विक कॉयर बाज़ार का मूल्य USD 1.45 बिलियन (₹12,000 करोड़) है।
- Cities like Mysuru and Madurai have achieved 100% recycling of coconut waste, setting national benchmarks.



- मैसूरु और मदुरै जैसे शहरों ने नारियल अपशिष्ट का 100% पुनर्चक्रण हासिल कर राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं।
- Bhubaneswar : The Palsuni Plant collects 5,000–6,000 coconuts daily from 189 temple vendors, earning ₹7–9 lakh monthly.
- भुवनेश्वर: पालसुनी संयंत्र प्रतिदिन 189 मंदिर विक्रेताओं से 5,000-6,000 नारियल एकत्र करता है, जिससे उसे प्रति माह 7-9 लाख रुपये की आय होती है।
- Indore : Processes 20 tonnes daily alongside its 550 TPD Bio-CNG plant; dry lines produce moisture-retaining cocopeat.
- इंदौर : यह संयंत्र अपने 550 टीपीडी बायो-सीएनजी संयंत्र के साथ-साथ प्रतिदिन 20 टन नारियल संसाधित करता है; इसकी ड्राई लाइनों से नमी बनाए रखने वाला कोकोपीट तैयार होता है।
- Chennai : A 20-year PPP model has processed 1.15 lakh metric tonnes since 2021, selling to tyre companies and nurseries.
- चेन्नई : 2021 से अब तक 20 साल के पीपीपी मॉडल के तहत 1.15 लाख मीट्रिक टन नारियल संसाधित किया गया है और इसे टायर कंपनियों और नर्सरियों को बेचा गया है।
- Kunnamkulam (Kerala) : Uses microbial cocopeat to turn husks into odor-free compost; farmers earn ₹1.25 per husk.
- कुन्नमकुलम (केरल) : यहां माइक्रोबियल कोकोपीट का उपयोग करके छिलकों को गंधहीन खाद में बदला जाता है; किसानों को प्रति छिलका 1.25 रुपये मिलते हैं।
- Religious Hubs : Puri, Varanasi, and Tirupati have dedicated MRFs to handle temple-generated coconut waste.
- धार्मिक केंद्र: पुरी, वाराणसी और तिरुपति में मंदिरों से निकलने वाले नारियल कचरे के निपटान के लिए समर्पित एमआरएफ (मल्टीपल रिफ्यूजी सेंटर) स्थापित किए गए हैं।

EXAM  
Genius





**Ques : As per RBI stress tests, what is the expected GNPA ratio of NBFCs under the baseline scenario by September 2026?**

आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट के अनुसार, सितंबर 2026 तक आधारभूत परिदृश्य में NBFC का GNPA अनुपात कितना होने का अनुमान है?

- A) 2.3%
- B) 2.5%
- C) 2.7%
- D) 2.9%
- E) 3.5%

**Answer : Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- Under the baseline scenario, RBI's stress tests project that the system-level Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio of NBFCs will rise from 2.3% in September 2024 to 2.9% by September 2026.
- आधारभूत परिदृश्य के तहत, आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट के अनुसार NBFC का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात सितंबर 2024 के 2.3% से बढ़कर सितंबर 2026 तक 2.9% होने का अनुमान है।
- This indicates a gradual deterioration in asset quality, although overall capital adequacy (CRAR) is expected to remain well above the regulatory minimum of 15%.
- यह परिसंपत्ति गुणवत्ता में धीरे-धीरे गिरावट को दर्शाता है, हालांकि समग्र पूंजी पर्याप्तता (CRAR) नियामकीय न्यूनतम 15% से काफी ऊपर बनी रहने का अनुमान है।
- RBI also highlighted uneven resilience within the NBFC sector, with 8 NBFCs potentially falling below the minimum CRAR threshold even under the baseline scenario.
- आरबीआई ने NBFC क्षेत्र में असमान लचीलापन की ओर संकेत किया, जिसमें आधारभूत परिदृश्य में ही 8 NBFCs का CRAR न्यूनतम सीमा से नीचे जाने की संभावना है।





**Ques: What key change has the Ministry of Corporate Affairs introduced regarding KYC compliance for company directors under the Companies Act, 2013?**

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी निदेशकों के लिए KYC अनुपालन को लेकर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कौन-सा प्रमुख बदलाव किया है?

- A) Mandatory monthly KYC filing / अनिवार्य मासिक KYC फाइलिंग
- B) Replacement of annual KYC with once-in-five-years filing / वार्षिक KYC को पाँच वर्ष में एक बार की फाइलिंग से बदलना
- C) Replacement of annual KYC with once-in-three-years simplified KYC / वार्षिक KYC को तीन वर्ष में एक बार सरल KYC से बदलना
- D) Complete removal of KYC requirement for directors / निदेशकों के लिए KYC आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करना
- E) KYC filing applicable only to newly appointed directors / केवल नए नियुक्त निदेशकों पर KYC फाइलिंग लागू करना

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Ministry of Corporate Affairs has eased compliance norms for company directors by replacing the mandatory annual KYC filing with a simplified KYC requirement once every three years.
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी निदेशकों के लिए अनिवार्य वार्षिक KYC फाइलिंग को हटाकर तीन वर्ष में एक बार सरल KYC की व्यवस्था लागू की है।
- This change follows a review of Rule 12A of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014, based on the recommendations of the High-Level Committee on Non-Financial Regulatory Reforms and stakeholder suggestions.
- यह बदलाव कंपनियों (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12A की समीक्षा के बाद किया गया है, जो गैर-वित्तीय विनियामक सुधारों पर उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों और हितधारकों के सुझावों पर आधारित है।
- The amended rules were notified on December 31, 2025, and will come into effect from March 31, 2026.
- संशोधित नियमों को 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया और ये 31 मार्च 2026 से प्रभावी होंगे।





- Under the revised framework, directors must submit a simplified KYC intimation once every three years instead of filing KYC annually.
- संशोधित ढांचे के तहत, निदेशकों को अब हर वर्ष के बजाय तीन वर्ष में एक बार सरल KYC सूचना देनी होगी।
- The revised KYC Form can be used for KYC compliance, updating mobile number, email address, residential address, and re-activation of Director Identification Number (DIN).
- संशोधित KYC फॉर्म का उपयोग KYC अनुपालन, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, आवासीय पता अद्यतन करने तथा DIN के पुनः सक्रियण के लिए किया जा सकता है।
- Digital signature verification by the director and certification by a professional will be mandatory only when the KYC form is submitted for updating mobile number, email address, or residential address.
- डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन और किसी पेशेवर द्वारा प्रमाणन केवल तभी अनिवार्य होगा, जब KYC फॉर्म मोबाइल नंबर, ई-मेल या आवासीय पते के अद्यतन के लिए दाखिल किया जाए।
- Directors who have already completed their KYC requirements are covered under the new provisions, and their next KYC filing will be due by June 30, 2028.
- जिन निदेशकों ने अब तक अपना KYC पूरा कर लिया है, वे नए प्रावधानों के अंतर्गत आएंगे और उनकी अगली KYC फाइलिंग 30 जून 2028 तक देय होगी।
- Directors who have not yet submitted their KYC Form can continue to get their DIN re-activated under existing provisions till March 31, 2026.
- जिन निदेशकों ने अब तक KYC फॉर्म जमा नहीं किया है, वे 31 मार्च 2026 तक मौजूदा प्रावधानों के तहत अपना DIN पुनः सक्रिय करा सकते हैं।

EXAM  
Genius





**Ques : What percentage of the FY26 Budget Estimate did India's fiscal deficit reach during April–November 2025?**

अप्रैल–नवंबर 2025 के दौरान भारत का राजकोषीय घाटा FY26 बजट अनुमान का कितना प्रतिशत रहा?

- A) 52.5%
- B) 58.4%
- C) 60.1%
- D) 62.3%
- E) 65.0%

**Answer :** Option D

**Explanation | व्याख्या:**

- According to data released by the Controller General of Accounts (CGA), India's fiscal deficit during April–November FY26 stood at ₹9.77 trillion, which is 62.3% of the Budget Estimate (BE) for the full financial year 2025–26.
- कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) के अनुसार, अप्रैल–नवंबर FY26 में भारत का राजकोषीय घाटा ₹9.77 ट्रिलियन रहा, जो पूरे वर्ष के बजट अनुमान का 62.3% है।
- In the same period last year, the fiscal deficit was ₹8.5 trillion (52.5% of BE), indicating a higher pace of spending in the current fiscal.
- पिछले वर्ष इसी अवधि में राजकोषीय घाटा ₹8.5 ट्रिलियन (BE का 52.5%) था, जिससे चालू वित्त वर्ष में व्यय की तेज़ गति स्पष्ट होती है।
- The rise in the deficit was mainly driven by a 28% year-on-year increase in capital expenditure, even as non-tax revenues remained strong, supported by higher dividends from PSUs, public sector banks, and the RBI.
- घाटे में वृद्धि का प्रमुख कारण पूंजीगत व्यय में 28% की वार्षिक वृद्धि रही, हालांकि PSU, सरकारी बैंकों और RBI से अधिक लाभांश मिलने से गैर-कर राजस्व मजबूत बना रहा।
- The Centre has targeted a fiscal deficit of 4.4% of GDP for FY26.
- केंद्र सरकार ने FY26 के लिए GDP के 4.4% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखा है।





**Ques: Which group has received in-principle approval from SEBI to act as sponsor and establish a new Mutual Fund?**

किस समूह को प्रायोजक के रूप में कार्य करने और नया म्यूचुअल फंड स्थापित करने के लिए सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है?

- A) Motilal Oswal Group / मोतीलाल ओसवाल समूह
- B) Edelweiss Group / एडलवाइस समूह
- C) Ashika Group / आशिका समूह
- D) JM Financial Group / जेएम फाइनेंशियल समूह
- E) IIFL Group / आईआईएफएल समूह

**Answer:** Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- Ashika Group has received in-principle approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to act as a sponsor and establish Ashika Mutual Fund.
- आशिका समूह को प्रायोजक के रूप में कार्य करने और आशिका म्यूचुअल फंड की स्थापना के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है।
- This approval allows the group to form an Asset Management Company (AMC) and initiate preparations for launching mutual fund schemes, subject to final registration.
- इस मंजूरी के तहत समूह को एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) गठित करने और अंतिम पंजीकरण के अधीन म्यूचुअल फंड योजनाओं की तैयारी करने की अनुमति मिली है।
- Ashika Group was established in 1994 and operates as a comprehensive financial services platform.
- आशिका समूह की स्थापना 1994 में हुई थी और यह एक वित्तीय सेवा मंच के रूप में कार्य करता है।





**Ques: Who has been given additional charge as the interim Managing Director & CEO of Canara Bank?**

केनरा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है?

- A) Satyanarayana Raju | सत्यनारायण राजू
- B) Brajesh Kumar Singh | ब्रजेश कुमार सिंह
- C) Hardeep Singh Ahluwalia | हरदीप सिंह अहलूवालिया
- D) Rajnish Kumar | रजनीश कुमार
- E) Ashok Chandra | अशोक चंद्र

**Answer : Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Canara Bank has assigned the additional charge of Managing Director & CEO to its Executive Director, Hardeep Singh Ahluwalia, with effect from January 1, 2026.
- केनरा बैंक ने 1 जनवरी 2026 से अपने कार्यकारी निदेशक हरदीप सिंह अहलूवालिया को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
- The interim appointment will remain valid for three months, or until a regular MD & CEO is appointed, or until further orders.
- यह अंतरिम नियुक्ति तीन महीनों के लिए या नियमित एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति होने तक प्रभावी रहेगी।
- The decision follows the superannuation of the incumbent MD & CEO, Satyanarayana Raju.
- यह निर्णय वर्तमान एमडी एवं सीईओ सत्यनारायण राजू के सेवानिवृत्त होने के बाद लिया गया है।
- Hardeep Singh Ahluwalia joined the banking sector in 1992 as an Agricultural Field Officer at Allahabad Bank (now Indian Bank) and has over three decades of experience across diverse banking segments.
- हरदीप सिंह अहलूवालिया ने 1992 में इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) में कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में बैंकिंग करियर शुरू किया था और उन्हें विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।
- The Financial Services Institutions Bureau (FSIB) has recommended Brajesh Kumar Singh, currently Executive Director at Indian Bank, as the next regular MD & CEO of Canara Bank.
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) ने वर्तमान में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक ब्रजेश कुमार सिंह को केनरा बैंक के अगले नियमित एमडी एवं सीईओ के रूप में सिफारिश की है।





**Ques: What major change has the Ministry of Finance introduced in the taxation of 'sin goods' such as tobacco and pan masala, effective from February 1, 2026?**

1 फरवरी 2026 से तंबाकू और पान मसाला जैसे 'सिन गुड्स' के कराधान में वित्त मंत्रालय ने कौन-सा प्रमुख बदलाव किया है?

- A) Complete removal of GST on tobacco products / तंबाकू उत्पादों पर GST को पूरी तरह समाप्त करना  
B) Reduction in GST rates on cigarettes and pan masala / सिगरेट और पान मसाला पर GST दरों में कटौती  
C) Replacement of GST with only excise duty / GST को केवल उत्पाद शुल्क से बदलना  
D) Introduction of additional excise duty and health cess replacing GST Compensation Cess / GST क्षतिपूर्ति उपकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य उपकर लागू करना  
E) Uniform 18% GST on all tobacco products / सभी तंबाकू उत्पादों पर समान 18% GST लागू करना

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Ministry of Finance has notified a revised tax framework for 'sin goods' such as tobacco, pan masala and related products, effective from February 1, 2026.
- वित्त मंत्रालय ने तंबाकू, पान मसाला और संबंधित 'सिन गुड्स' के लिए संशोधित कर ढांचा अधिसूचित किया है, जो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा।
- Under the new framework, an additional excise duty and a Health and National Security Cess will replace the existing GST Compensation Cess.
- नए ढांचे के तहत मौजूदा GST क्षतिपूर्ति उपकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा।
- Pan masala, cigarettes and other tobacco products will continue to attract 40% GST, while biris will remain taxed at 18%.
- पान मसाला, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% GST जारी रहेगा, जबकि बीड़ी पर 18% GST लागू रहेगा।
- From February 1, 2026, tobacco products will be subject to an additional excise duty, while pan masala will also attract a Health and National Security Cess over and above GST.
- 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर GST के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा।
- The additional excise duty rates include 91% on gutkha, 82% on chewing tobacco and jarda scented tobacco, and 33% on hookah tobacco.

|





- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दरें गुटखा पर 91%, चबाने वाले तंबाकू और जर्दा सुगंधित तंबाकू पर 82% तथा हुक्का तंबाकू पर 33% निर्धारित की गई हैं।
- Cigarettes will attract an excise duty ranging from ₹2,050 to ₹8,500 per 1,000 sticks, depending on length and filter type.
- सिगरेट पर लंबाई और फ़िल्टर के आधार पर प्रति 1,000 सिगरेट ₹2,050 से ₹8,500 तक का उत्पाद शुल्क लगेगा



EXAM  
Genius





**Ques: Who chaired the 50th meeting of PRAGATI, marking a decade of transformative governance in India?**

PRAGATI की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, जो परिवर्तनकारी शासन के एक दशक का प्रतीक है?

- A) Amit Shah / अमित शाह
- B) Nitin Gadkari / नितिन गडकरी
- C) Piyush Goyal / पीयूष गोयल
- D) Rajnath Singh / राजनाथ सिंह
- E) Narendra Modi / नरेंद्र मोदी

**Answer:** Option E

**Explanation | व्याख्या:**

- Prime Minister Narendra Modi chaired the 50th meeting of PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation), marking ten years of its role in accelerating governance and project implementation.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की, जो इसके परिवर्तनकारी शासन में दस वर्षों को दर्शाती है।
- During the meeting, the Prime Minister reviewed five critical infrastructure projects across key sectors such as Roads, Railways, Power, Water Resources, and Coal.
- बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला क्षेत्रों से जुड़ी पाँच महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की।
- PRAGATI has been instrumental in unlocking and fast-tracking infrastructure projects that had remained stalled for decades.
- PRAGATI मंच दशकों से अटकी हुई अवसंरचना परियोजनाओं को गति देने और उन्हें आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है।
- The Bogibeel Bridge in Assam, conceived in 1997, was completed through effective PRAGATI monitoring.
- असम का बोगीबील पुल, जिसकी परिकल्पना 1997 में की गई थी, PRAGATI की निगरानी के माध्यम से पूरा किया गया।
- The Jammu–Srinagar Rail Link, where work began in 1995, was decisively unlocked through this platform.
- जम्मू–श्रीनगर रेल लिंक परियोजना, जिसका कार्य 1995 में शुरू हुआ था, PRAGATI के माध्यम से निर्णायक रूप से आगे बढ़ी।





- Other long-pending projects unlocked include the Navi Mumbai International Airport (conceptualized in 1997), Bhilai Steel Plant Modernization (approved in 2007), and the Gadawara and LARA Thermal Power Projects (sanctioned in 2008–2009).
- अन्य लंबे समय से लंबित परियोजनाओं में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (1997), भिलाई स्टील प्लांट आधुनिकीकरण (2007) तथा गदरवाड़ा और लारा थर्मल पावर परियोजनाएँ (2008–2009) शामिल हैं।

#### Pro-Active Governance and Timely Implementation (PRAGATI) :

- Launched : March 25, 2015
- Design & Support : Designed by PMO with help from National Informatics Centre (NIC).
- Platform Type : ICT-enabled, multi-modal platform (Data, Videoconferencing, Geo-spatial)
- The "PRAGATI Day" : Meetings are held on the fourth Wednesday of every month at 3:30 PM.
- Three-Tier System Involve : 1. PMO, 2. Union Secretaries, 3. State Chief Secretaries.
- Genesis : Based on the SWAGAT (State Wide Attention on Grievances by Application of Technology) platform launched by PM Modi in Gujarat in 2003.

EXAM  
Genius





**Ques: Under the draft Rules of the four Labour Codes, what is the mandated maximum work week?**

चार श्रम संहिताओं के मसौदा नियमों के तहत अधिकतम कार्य सप्ताह कितना निर्धारित किया गया है?

- A) 40 hours
- B) 45 hours
- C) 48 hours
- D) 54 hours
- E) 60 hours

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Union Labour Ministry has pre-published draft Rules for the four Labour Codes on its official website and invited public feedback within a 45-day window.
- केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने चार श्रम संहिताओं के मसौदा नियम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पूर्व-प्रकाशित किए हैं और जनता को 45 दिनों के भीतर सुझाव देने का अवसर दिया है।
- The draft Rules comprehensively define workers, wages, types of employment, gratuity, bonus, and social security, including provisions for gig and platform workers.
- मसौदा नियमों में कर्मचारियों, वेतन, रोजगार के प्रकार, ग्रेच्युटी, बोनस और सामाजिक सुरक्षा (गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित) को विस्तार से परिभाषित किया गया है।
- As per the draft Labour Codes Rules, a uniform 48-hour work week has been mandated across establishments.
- मसौदा श्रम संहिता नियमों के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों में 48 घंटे का कार्य सप्ताह अनिवार्य किया गया है।
- Special provisions have been included for workplaces where women work night shifts, covering safety measures, consent, and transport facilities.
- रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा, सहमति और परिवहन सुविधाओं से संबंधित विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- The Code on Wages Rules subsume 18 existing rules, including Minimum Wages Rules and Equal Remuneration Rules, thereby simplifying the regulatory framework.
- वेतन संहिता नियमों में न्यूनतम वेतन नियम, समान पारिश्रमिक नियम सहित 18 मौजूदा नियमों को समाहित कर विनियामक ढांचे को सरल बनाया गया है।
- Minimum wages will be fixed based on the concept of a standard working-class family, which includes an earning worker, spouse, and two children, along with defined consumption and expenditure criteria.





**Ques: Who was awarded the Israel Prize for Peace, Israel's highest civilian honour?**

इज़राइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "इज़राइल प्राइज़ फ़ॉर पीस" किसे प्रदान किया गया?

- A) Joe Biden / जो बाइडेन
- B) Benjamin Netanyahu / बेंजामिन नेतन्याहू
- C) Volodymyr Zelenskyy / वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की
- D) Emmanuel Macron / इमैनुएल मैक्रों
- E) Donald Trump / डोनाल्ड ट्रम्प

**Answer: Option E**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Israel Prize for Peace, Israel's highest civilian honour, was conferred on US President Donald Trump.
- इज़राइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "इज़राइल प्राइज़ फ़ॉर पीस" अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को प्रदान किया गया।
- The award was presented during bilateral talks held in Florida at Donald Trump's Mar-a-Lago residence.
- यह पुरस्कार फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रम्प के मार-ए-लागो निवास पर आयोजित द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रदान किया गया।
- This marks the first time the Israel Prize has been awarded to a non-Israeli citizen. It is also the first time that the Peace category of the Israel Prize has been awarded.
- यह पहली बार है जब यह पुरस्कार किसी गैर-इज़राइली नागरिक को दिया गया है। साथ ही, यह पहला अवसर है जब इज़राइल प्राइज़ के 'शांति' वर्ग को प्रदान किया गया है।
- Notably, this recognition follows Donald Trump recently receiving the FIFA Peace Prize.
- उल्लेखनीय है कि यह सम्मान डोनाल्ड ट्रम्प को हाल ही में मिले FIFA शांति पुरस्कार के बाद प्रदान किया गया है।





**Ques: Which state has become the first in India to constitute its 8th State Pay Commission ahead of the expiry of the 7th Pay Commission?**

भारत में कौन-सा राज्य 7वें वेतन आयोग की समाप्ति से पहले 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बना है?

- A) Assam / असम
- B) Karnataka / कर्नाटक
- C) Maharashtra / महाराष्ट्र
- D) West Bengal / पश्चिम बंगाल
- E) Tamil Nadu / तमिलनाडु

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- Assam has become the first state in India to constitute its 8th State Pay Commission, taking a proactive step ahead of the scheduled expiry of the 7th Pay Commission on January 1, 2026.
- असम 1 जनवरी 2026 को 7वें वेतन आयोग की निर्धारित समाप्ति से पहले 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- The decision has drawn significant attention from state government employees and pensioners, who have been awaiting clarity on the next round of pay and pension revision.
- इस निर्णय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है, जो वेतन और पेंशन संशोधन के अगले चरण को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे।
- With this move, Assam has taken the lead over other states, even as the Union Government's 8th Pay Commission is yet to formally commence its work.
- इस कदम के साथ, असम ने अन्य राज्यों से पहले पहल की है, जबकि केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग अभी औपचारिक रूप से अपना कार्य शुरू नहीं कर पाया है।
- As per standard practice, the 8th State Pay Commission is expected to submit its recommendations within a period of around 18 months.
- सामान्य प्रथा के अनुसार, 8वां राज्य वेतन आयोग लगभग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की संभावना है।

**About Assam :**

- Capital : Dispur
- CM : Himanta Biswa Sarma
- Governor : Lakshman Acharya





**Ques: What recent decision has NHA taken regarding the Know Your Vehicle (KYV) process for FASTags in the Car/Jeep/Van category?**

कार/जीप/वैन श्रेणी के FASTag के लिए NHA ने Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया को लेकर क्या निर्णय लिया है?

- A) KYV made mandatory for all existing FASTags / सभी मौजूदा FASTag के लिए KYV अनिवार्य
- B) KYV replaced with Aadhaar-based verification / KYV को आधार-आधारित सत्यापन से बदलना
- C) KYV discontinued for new FASTags except complaint-based cases / शिकायत-आधारित मामलों को छोड़कर नए FASTag के लिए KYV समाप्त
- D) KYV mandatory only for commercial vehicles / केवल वाणिज्यिक वाहनों के लिए KYV अनिवार्य
- E) Complete removal of vehicle verification for FASTags / FASTag के लिए वाहन सत्यापन पूरी तरह समाप्त

Answer: Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- The National Highways Authority of India (NHA) has decided to discontinue the Know Your Vehicle (KYV) process for Car/Jeep/Van category FASTags.
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) ने कार/जीप/वैन श्रेणी के FASTag के लिए Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
- This change will be effective from February 1, 2026, and will apply to all new FASTag issuances for cars.
- यह बदलाव 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा और कारों के लिए जारी होने वाले सभी नए FASTag पर लागू होगा।
- KYV will now be required only in specific complaint-based cases such as loose FASTags, incorrect issuance, misuse, or disputes.
- अब KYV केवल कुछ शिकायत-आधारित मामलों में आवश्यक होगा, जैसे ढीले FASTag, गलत जारी करना, दुरुपयोग या विवाद।
- In the absence of any complaint, no KYV requirement will apply.
- यदि कोई शिकायत नहीं है, तो KYV की आवश्यकता नहीं होगी।
- FASTag activation will be allowed only after vehicle details are verified from the VAHAN database.
- FASTag को केवल VAHAN डेटाबेस से वाहन विवरण के सत्यापन के बाद ही सक्रिय किया जाएगा।
- RC-based validation will be permitted only in exceptional cases, such as when vehicle data is unavailable on VAHAN, and issuer banks will be fully accountable.





**Ques: Parvati–Arga Bird Sanctuary, recently declared an Eco-Sensitive Zone, is designated as which of the following?**

हाल ही में इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित पार्वती–अर्गा पक्षी अभयारण्य किस रूप में नामित है?

- A) Biosphere Reserve / जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र
- B) Tiger Reserve / टाइगर रिज़र्व
- C) Ramsar Site / रामसर स्थल
- D) National Park / राष्ट्रीय उद्यान
- E) Community Reserve / सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Government has declared the Parvati–Arga Bird Sanctuary in Uttar Pradesh as an Eco-Sensitive Zone (ESZ).
- सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती–अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) घोषित किया है।
- The sanctuary is a permanent freshwater ecosystem comprising two oxbow lakes—Parvati and Arga.
- यह अभयारण्य स्थायी मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें पार्वती और अर्गा नामक दो ऑक्सबो झीलें शामिल हैं।
- Parvati–Arga Bird Sanctuary is a Ramsar Site, underscoring its international importance as a wetland.
- पार्वती–अर्गा पक्षी अभयारण्य एक रामसर स्थल है, जो इसके अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि महत्व को दर्शाता है।
- Spread over 1,084 hectares, it serves as a habitat for migratory birds arriving from Central Asia and Tibet.
- 1,084 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों का आवास है।
- Eco-Sensitive Zones are notified to regulate activities around protected areas and conserve fragile ecosystems, and they may extend up to 10 km around such areas as per guidelines.
- इको-सेंसिटिव ज़ोन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास गतिविधियों को नियंत्रित करने और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए अधिसूचित किए जाते हैं, जो दिशानिर्देशों के अनुसार 10 किमी तक विस्तारित हो सकते हैं।





## Ques: Who was awarded a Damehood (DBE) in King Charles III's New Year Honours List 2026?

किंग चार्ल्स तृतीय की न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट 2026 में किसे डेमहुड (DBE) से सम्मानित किया गया?

- A) Meera Syal / मीरा स्याल
- B) Gurinder Chadha / गुरिंदर चड्ढा
- C) Parminder Nagra / परमिंदर नागरा
- D) Anita Rani / अनीता रानी
- E) Sanjeev Bhaskar / संजीव भास्कर

### Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Renowned British-Indian comedian, actress, and writer Meera Syal was awarded a Damehood (DBE) in King Charles III's New Year Honours List 2026.
- प्रसिद्ध ब्रिटिश-भारतीय कॉमेडियन, अभिनेत्री और लेखिका मीरा स्याल को किंग चार्ल्स तृतीय की न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट 2026 में डेमहुड (DBE) से सम्मानित किया गया।
- Earlier, Meera Syal had been honoured with an MBE (Member of the Order of the British Empire) in 1997 and a CBE (Commander of the Order of the British Empire) in 2015.
- इससे पहले मीरा स्याल को 1997 में MBE और 2015 में CBE से सम्मानित किया जा चुका है।
- A total of 1,157 individuals were honoured in the New Year Honours List 2026.
- न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट 2026 में कुल 1,157 लोगों को सम्मानित किया गया।
- Toby Roberts, aged 20 years, was the youngest recipient and was honoured with an MBE.
- 20 वर्षीय टोबी रॉबर्ट्स सबसे कम उम्र के सम्मानित व्यक्ति रहे, जिन्हें MBE प्रदान किया गया।
- John Hearn, aged 102 years, was the oldest recipient and received the BEM (British Empire Medal).
- 102 वर्षीय जॉन हर्न सबसे वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति रहे, जिन्हें BEM (ब्रिटिश एम्पायर मेडल) प्रदान किया गया।





**Ques: Who has been appointed as the International Event Ambassador for the 21st edition of the Tata Mumbai Marathon (TMM 2025)?**

टाटा मुंबई मैराथन (TMM 2025) के 21वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एंबेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Usain Bolt (Jamaica) / उसेन बोल्ट (जमैका)
- B) Andre De Grasse (Canada) / आंद्रे डी ग्रास (कनाडा)
- C) Wayde van Niekerk (South Africa) / वेडे वान नीकरक (दक्षिण अफ्रीका)
- D) Yohan Blake (Jamaica) / योहान ब्लेक (जमैका)
- E) Fred Kerley (USA) / फ्रेड कर्ली (यूएसए)

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- Seven-time Olympic medallist sprinter Andre De Grasse of Canada has been appointed as the International Event Ambassador for the 21st edition of the Tata Mumbai Marathon (TMM 2025).
- कनाडा के सात बार के ओलंपिक पदक विजेता धावक आंद्रे डी ग्रास को टाटा मुंबई मैराथन (TMM 2025) के 21वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एंबेसडर नियुक्त किया गया है।
- The Tata Mumbai Marathon 2025 is scheduled to be held on January 18, 2026, in Mumbai, Maharashtra.
- टाटा मुंबई मैराथन 2025 का आयोजन 18 जनवरी 2026 को मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा।
- The International Event Ambassador programme has been designed and curated by Procam International since the inception of the Tata Mumbai Marathon in 2004.
- अंतरराष्ट्रीय इवेंट एंबेसडर कार्यक्रम को 2004 में टाटा मुंबई मैराथन की शुरुआत से ही प्रोकेम इंटरनेशनल द्वारा डिज़ाइन और संचालित किया जा रहा है।





**Ques: Which country has India surpassed to become the world's fourth-largest economy?**

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ चुका है?

- A) Germany / जर्मनी
- B) China / चीन
- C) United Kingdom / यूनाइटेड किंगडम
- D) Japan / जापान
- E) France / फ्रांस

**Answer:** Option D

**Explanation | व्याख्या:**

- India has surpassed Japan to become the world's fourth-largest economy.
- भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है।
- India's Gross Domestic Product (GDP) is estimated at USD 4.18 trillion.
- भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मूल्य लगभग 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है।
- India is expected to overtake Germany by 2030 to become the third-largest economy globally.
- भारत के 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।
- India's projected GDP by 2030 is around USD 7.3 trillion.
- 2030 तक भारत की अनुमानित GDP लगभग 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है।
- Real GDP growth stood at 8.2% in Q2 of FY 2025–26, compared to 7.8% in Q1.
- वित्त वर्ष 2025–26 की दूसरी तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि 8.2% रही, जबकि पहली तिमाही में यह 7.8% थी।
- The growth momentum has been driven mainly by strong private consumption and robust domestic demand.
- इस तेज़ वृद्धि का मुख्य कारण मजबूत निजी उपभोग और घरेलू मांग रहा है।
- The United States remains the world's largest economy, followed by China at the second position.
- संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है।
- India continues to rank among the fastest-growing major economies in the world.





## Ques: Where was the 27th edition of the FIDE World Rapid and Blitz Chess Championship 2025 held?

27वाँ FIDE वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज़ शतरंज चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया?

- A) Doha, Qatar / दोहा, क़तर
- B) Moscow, Russia / मॉस्को, रूस
- C) Dubai, United Arab Emirates / दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
- D) Almaty, Kazakhstan / अल्माटी, कज़ाख़स्तान
- E) Oslo, Norway / ओस्लो, नॉर्वे

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- The 27th edition of the FIDE World Rapid and Blitz Chess Championship 2025 was held at the Sports and Events Complex, Qatar University, Doha, Qatar.
- 27वाँ FIDE वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज़ शतरंज चैंपियनशिप 2025 क़तर विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स कॉम्प्लेक्स, दोहा (क़तर) में आयोजित किया गया।
- Norwegian Grandmaster Magnus Carlsen won his sixth World Rapid Championship title in the Open category.
- नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन ने ओपन श्रेणी में अपना छठा वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप खिताब जीता।
- In the Women's Rapid category, Russian Grandmaster Aleksandra Goryachkina won her maiden FIDE Women's World Rapid Championship.
- महिला रैपिड श्रेणी में रूस की ग्रैंडमास्टर एलेक्ज़ेंड्रा गोरयाचकिना ने अपना पहला FIDE महिला वर्ल्ड रैपिड खिताब जीता।
- Magnus Carlsen also clinched his ninth World Blitz Championship title in the Open category. In the Women's Blitz category, Bibisara Assaubayeva of Kazakhstan emerged as the champion.
- मैग्नस कार्लसन ने ओपन श्रेणी में अपना नौवाँ वर्ल्ड ब्लिट्ज़ चैंपियनशिप खिताब भी जीता। महिला ब्लिट्ज़ श्रेणी में कज़ाख़स्तान की बिबिसारा अस्सौबायेवा विजेता बनीं।

**2025 FIDE World Blitz Chess Championships:**



1. Magnus Carlsen (Norway) - (Open Section), Bibisara Assaubayeva (Kazakhstan) - (Women's Section)
2. Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistan) - (Open Section), Anna Muzychuk (Ukraine) - (Women's Section)
3. Arjun Erigaisi (India) and Fabiano Caruana (USA) - (Open Section), Zhu Jiner (China) and Eline Roebers (Netherlands) - (Women's Section)

### 2025 FIDE World Rapid Chess Championships:

1. Magnus Carlsen (Norway) - (Open Section), Aleksandra Goryachkina (Russia) - (Women's Section)
2. Vladislav Artemiev (Russia) - (Open Section), Zhu Jiner (China) - (Women's Section)
3. Arjun Erigaisi (India) - (Open Section), Koneru Humpy (India) - (Women's Section)

EXAM  
Genius





**Ques: For the first time, a specially curated animal contingent of the Remount and Veterinary Corps will feature which of the following animals?**

पहली बार, रिमाउंट एवं वेटेनरी कोर की विशेष रूप से तैयार पशु टुकड़ी में निम्न में से कौन-कौन से जानवर शामिल होंगे?

- A) Horses, elephants, dolphins, and sniffer dogs / घोड़े, हाथी, डॉल्फिन और खोजी कुत्ते
- B) Bactrian camels, Zanskar ponies, raptors, and Indian breed Army dogs / बैक्ट्रियन ऊँट, ज़ांस्कर टट्टू, शिकारी पक्षी और भारतीय नस्ल के सेना कुत्ते
- C) Arabian camels, mules, eagles, and foreign breed dogs / अरब ऊँट, खच्चर, चील और विदेशी नस्ल के कुत्ते
- D) Elephants, mules, hawks, and police dogs / हाथी, खच्चर, बाज़ और पुलिस कुत्ते
- E) Horses, camels, parrots, and tracker dogs / घोड़े, ऊँट, तोते और ट्रैकर कुत्ते

**Answer:** Option B

**Explanation | व्याख्या:**

- For the first time, the Remount and Veterinary Corps is showcasing a carefully curated animal contingent.
- पहली बार, रिमाउंट एवं वेटेनरी कोर द्वारा एक विशेष रूप से तैयार पशु टुकड़ी प्रदर्शित की जा रही है।
- The contingent will feature two Bactrian camels and four Zanskar ponies.
- इस टुकड़ी में दो बैक्ट्रियन ऊँट और चार ज़ांस्कर टट्टू शामिल होंगे।
- It will also include four raptors and ten Indian breed Army dogs. Additionally, six conventional military dogs already in service will be part of the contingent.
- इसके साथ चार शिकारी पक्षी (रैप्टर्स) और दस भारतीय नस्ल के सेना कुत्ते भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, सेवा में पहले से कार्यरत छह पारंपरिक सैन्य कुत्ते भी इस टुकड़ी का हिस्सा होंगे।
- The contingent highlights the diverse and specialised role of animals in the Indian Armed Forces.
- यह टुकड़ी भारतीय सशस्त्र बलों में पशुओं की विविध और विशेष भूमिका को दर्शाती है।





**Ques: What new service was launched by BSNL across all telecom circles in India to improve connectivity in areas with weak cellular signals?**

कमजोर मोबाइल नेटवर्क वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए BSNL ने पूरे भारत में कौन-सी नई सेवा शुरू की है?

- A) 5G Standalone Service / 5G स्टैंडअलोन सेवा
- B) Satellite Calling Service / सैटेलाइट कॉलिंग सेवा
- C) Voice over WiFi (VoWiFi) or Wi-Fi Calling / वॉयस ओवर वाई-फाई (वाई-फाई कॉलिंग)
- D) National Roaming Plus / नेशनल रोमिंग प्लस
- E) VoNR (Voice over New Radio) / वॉयस ओवर न्यू रेडियो

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) launched its Voice over WiFi (VoWiFi) service, commonly known as Wi-Fi Calling, across all telecom circles in India to mark the New Year.
- भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने नए वर्ष के अवसर पर पूरे भारत के सभी टेलीकॉम सर्किलों में वॉयस ओवर वाई-फाई (VoWiFi), जिसे वाई-फाई कॉलिंग भी कहा जाता है, सेवा शुरू की।
- The service is specifically designed for locations with weak cellular network coverage, such as basements, high-rise buildings, and remote rural areas.
- यह सेवा विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए बनाई गई है जहाँ मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता है, जैसे बेसमेंट, ऊँची इमारतें और दूरदराज़ ग्रामीण क्षेत्र।
- VoWiFi is built on the IP Multimedia Subsystem (IMS) platform, enabling seamless call handover between Wi-Fi networks and mobile networks using Voice over LTE (VoLTE) without call drops.
- VoWiFi सेवा IP मल्टीमीडिया सबसिस्टम (IMS) प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जो वाई-फाई और मोबाइल नेटवर्क (VoLTE) के बीच बिना कॉल कटे सहज संक्रमण सुनिश्चित करती है।

**About BSNL :**

- Established : 15 September 2000
- HQ : New Delhi
- CMD : A. Robert J. Ravi
- Nodal Ministry : Ministry of Communications





**Ques: Which country adopted the Euro as its official currency from January 1, 2026, becoming the 21st member of the Eurozone?**

1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाकर यूरोज़ोन का 21वां सदस्य कौन-सा देश बना?

- A) Romania / रोमानिया
- B) Croatia / क्रोएशिया
- C) Bulgaria / बुल्गारिया
- D) Hungary / हंगरी
- E) Czech Republic / चेक गणराज्य

**Answer:** Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- Bulgaria adopted the Euro (EUR) as its official currency with effect from January 1, 2026, replacing the Bulgarian lev (BGN).
- बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से बल्गेरियन लेव (BGN) के स्थान पर यूरो (EUR) को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है।
- The decision followed approval by the Council of the European Union on July 8, 2025, confirming that Bulgaria met all Maastricht convergence criteria.
- यह निर्णय 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ की परिषद द्वारा अनुमोदन के बाद लिया गया, जिसमें पुष्टि की गई कि बुल्गारिया सभी मास्ट्रिख्ट अभिसरण मानदंडों पर खरा उतरा है।
- The irrevocable conversion rate was fixed at 1 EUR = 1.95583 BGN.
- अपरिवर्तनीय रूपांतरण दर 1 यूरो = 1.95583 बल्गेरियन लेव निर्धारित की गई।
- With this move, Bulgaria became the 21st member of the Eurozone, the group of European countries using the euro as their official currency.
- इस कदम के साथ, बुल्गारिया यूरोज़ोन का 21वां सदस्य बन गया, जहाँ यूरो आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है।
- Following euro adoption, the Bulgarian National Bank (BNB) joined the Eurosystem and became part of the European Central Bank (ECB) framework.
- यूरो को अपनाने के बाद, बल्गेरियन नेशनल बैंक (BNB) यूरोसिस्टम में शामिल हो गया और यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) के ढांचे का हिस्सा बन गया।





**Ques: What will be the name of Goa's third district, recently announced by the Chief Minister?**

हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित गोवा के तीसरे ज़िले का नाम क्या होगा?

- A) Kushavati / कुशावती
- B) Zuari / जुआरी
- C) Mandovi / मांडोवी
- D) Mahadayi / महादयी
- E) Kalay / कलाय

**Answer:** Option A

**Explanation | व्याख्या:**

- Goa is set to get its third district named Kushavati, marking a significant administrative reorganisation in the state.
- गोवा को कुशावती नाम का तीसरा ज़िला मिलने जा रहा है, जो राज्य में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पुनर्गठन को दर्शाता है।
- The announcement was made by Goa Chief Minister Pramod Sawant.
- इस घोषणा को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया।
- The new district has been named after the ancient Kushavati river that flows through parts of the region.
- नए ज़िले का नाम प्राचीन कुशावती नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों से होकर बहती है।
- Currently, Goa has only two districts: North Goa and South Goa.
- वर्तमान में गोवा में केवल दो ज़िले हैं—उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा।

**About Goa :**

- Capital : Panaji
- CM : Pramod Sawant
- Governor : Ashok Gajapathi Raju





**Ques: What major reform has the Department of Posts implemented regarding international mail services, effective from January 1, 2026?**

1 जनवरी 2026 से डाक विभाग ने अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं के संबंध में कौन-सा प्रमुख सुधार लागू किया है?

- A) Complete suspension of all international mail services / सभी अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं को पूरी तरह निलंबित करना
- B) Discontinuation of untracked and non-compliant international mail services / बिना ट्रैकिंग और गैर-अनुपालक अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं को बंद करना
- C) Introduction of free international parcel services / निःशुल्क अंतरराष्ट्रीय पार्सल सेवाओं की शुरुआत
- D) Restricting international mail only to government use / अंतरराष्ट्रीय डाक को केवल सरकारी उपयोग तक सीमित करना
- E) Replacement of postal services with private couriers / डाक सेवाओं को निजी कूरियर सेवाओं से बदलना

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Department of Posts has undertaken a major rationalization of its international mail services in line with Universal Postal Union (UPU) standards.
- डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) मानकों के अनुरूप अपनी अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं का व्यापक युक्तिकरण किया है।
- These reforms aim to modernize global e-commerce, improve security, and ensure 100% trackability of international shipments.
- इन सुधारों का उद्देश्य वैश्विक ई-कॉमर्स को आधुनिक बनाना, सुरक्षा बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय प्रेषणों की पूर्ण ट्रैकिंग सुनिश्चित करना है।
- Effective January 1, 2026, services lacking adequate tracking or modern customs compliance have been discontinued.
- 1 जनवरी 2026 से जिन सेवाओं में पर्याप्त ट्रैकिंग या आधुनिक सीमा शुल्क अनुपालन नहीं था, उन्हें बंद कर दिया गया है।
- Registered Small Packet Service has been restricted to document-only items.
- पंजीकृत स्मॉल पैकेट सेवा अब केवल दस्तावेजों तक सीमित कर दी गई है।
- Outward Small Packet Service for goods sent via Sea, SAL (Surface Air Lifted), or Air has been discontinued.





- समुद्र, SAL (Surface Air Lifted) या वायु मार्ग से भेजे जाने वाले वस्तुओं के लिए आउटवर्ड स्मॉल पैकेट सेवा बंद कर दी गई है।
- Traditional Surface and SAL outward international letter mail services have also been stopped.
- पारंपरिक सतही और SAL आधारित आउटवर्ड अंतरराष्ट्रीय पत्र डाक सेवाएँ भी बंद कर दी गई हैं।
- The move is driven by global security and customs norms, as many countries now mandate Electronic Advance Data (EAD), which untracked services cannot provide.
- यह कदम वैश्विक सुरक्षा और सीमा शुल्क मानकों के अनुरूप है, क्योंकि कई देश अब इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा (EAD) अनिवार्य कर चुके हैं, जो बिना ट्रैकिंग वाली सेवाएँ प्रदान नहीं कर सकतीं।
- Certain services remain unchanged, including free Blind Literature services (except air surcharge), M-Bags governed by existing UPU norms, and registration of documents sent via Air mode.
- कुछ सेवाएँ यथावत रखी गई हैं, जैसे दृष्टिबाधितों के लिए ब्लाइंड लिटरेचर (हवाई अधिभार को छोड़कर), UPU नियमों के अंतर्गत M-बैग्स, तथा एयर मोड से भेजे गए पत्र, पोस्टकार्ड, एरोग्राम और मुद्रित पत्रों का पंजीकरण।

EXAM  
Genius





**Ques: What major digital milestone did India achieve in November 2025 according to PIB data?**

PIB के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में भारत ने कौन-सा प्रमुख डिजिटल मील का पत्थर हासिल किया?

- A) Crossing 500 million internet users / 500 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पार करना
- B) Achieving 100% broadband penetration / 100% ब्रॉडबैंड कवरेज प्राप्त करना
- C) Broadband subscriber base crossing 1 billion / ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 1 अरब को पार करना
- D) Launch of nationwide 6G services / देशव्यापी 6G सेवाओं की शुरुआत
- E) Doubling broadband users within one year / एक वर्ष में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या दोगुनी होना

**Answer:** Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- India achieved a significant digital milestone in November 2025 as its broadband subscriber base crossed 1 billion (100 crore) users for the first time.
- भारत ने नवंबर 2025 में पहली बार ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 1 अरब (100 करोड़) को पार कर एक महत्वपूर्ण डिजिटल उपलब्धि हासिल की।
- According to data released by the Press Information Bureau (PIB), India had 100.37 crore broadband subscribers by the end of November 2025.
- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 के अंत तक भारत में 100.37 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे।
- This marks the first instance of the country crossing the 1 billion subscriber threshold.
- यह देश द्वारा पहली बार 1 अरब उपभोक्ता सीमा को पार करने की घटना है।
- In November 2015, broadband subscribers numbered 131.49 million (13.15 crore).
- नवंबर 2015 में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 131.49 मिलियन (13.15 करोड़) थी।
- By November 2025, the subscriber base had expanded to 100.37 crore, representing more than a six-fold increase in ten years.
- नवंबर 2025 तक यह संख्या बढ़कर 100.37 करोड़ हो गई, जो एक दशक में छह गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाती है।





**Ques: Which ministry unveiled a new institutional identity with a revamped logo and a first-of-its-kind mascot themed “Data for Development”?**

“डेटा फॉर डेवलपमेंट” थीम के तहत नया संस्थागत पहचान (रीवैण्ड लोगो और प्रथम-प्रकार के मैस्कॉट) किस मंत्रालय ने प्रस्तुत किया?

- A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- B) Ministry of Electronics & IT / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
- C) Ministry of Statistics and Programme Implementation / सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- D) Ministry of Information & Broadcasting / सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- E) NITI Aayog / नीति आयोग

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) unveiled its new institutional identity, featuring a redesigned logo and a first-of-its-kind mascot.
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने नया संस्थागत पहचान प्रस्तुत किया, जिसमें पुनः डिज़ाइन किया गया लोगो और एक अनोखा मैस्कॉट शामिल है।
- The initiative is themed “Data for Development” and aims to humanize official statistics while bridging the gap between complex data and the general public.
- यह पहल “डेटा फॉर डेवलपमेंट” थीम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक आँकड़ों को मानवीय बनाना और जटिल डेटा व आम नागरिकों के बीच की दूरी को कम करना है।
- The Ashoka Chakra in the logo symbolizes truth, transparency, and good governance in data collection.
- लोगो में अशोक चक्र डेटा संग्रह में सत्य, पारदर्शिता और सुशासन के मूल्यों का प्रतीक है।
- The Rupee symbol (₹) placed at the center highlights the importance of statistics in economic planning, national growth, and policymaking.
- केंद्र में स्थित रुपये का प्रतीक (₹) आर्थिक योजना, राष्ट्रीय विकास और नीति निर्माण में सांख्यिकी की अहम भूमिका को दर्शाता है।
- An upward growth bar represents the nation’s progress and reflects how reliable data forms the foundation of sustainable economic growth.
- ऊपर की ओर बढ़ती ग्रोथ बार देश की प्रगति और सतत आर्थिक विकास में विश्वसनीय डेटा की भूमिका को दर्शाती है।





**Ques: What decision did the Department of Economic Affairs (DEA) take regarding Small Savings Schemes (SSS) interest rates for January–March 2026?**

जनवरी–मार्च 2026 के लिए लघु बचत योजनाओं (SSS) की ब्याज दरों को लेकर आर्थिक कार्य विभाग (DEA) ने क्या निर्णय लिया?

- A) Interest rates were increased / ब्याज दरें बढ़ाई गईं
- B) Interest rates were reduced / ब्याज दरें घटाई गईं
- C) Interest rates were kept unchanged / ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी गईं
- D) Only select schemes saw a hike / केवल कुछ योजनाओं में वृद्धि हुई
- E) Quarterly revision system was discontinued / तिमाही संशोधन प्रणाली समाप्त की गई

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance kept interest rates unchanged for all Small Savings Schemes from January 01, 2026 to March 31, 2026, continuing the rates of Q3FY26.
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग ने 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक सभी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को Q3FY26 के समान अपरिवर्तित रखा।
- This is the 8th consecutive quarter with no change in SSS interest rates.
- यह लगातार आठवीं तिमाही है जब SSS की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- The interest rates were last revised in Q4FY24.
- SSS की ब्याज दरों में अंतिम संशोधन Q4FY24 में किया गया था।
- Small Savings Schemes are Government of India–backed instruments that promote household savings and provide risk-free investment options.
- लघु बचत योजनाएं भारत सरकार समर्थित साधन हैं, जिनका उद्देश्य घरेलू बचत को बढ़ावा देना और जोखिम-मुक्त निवेश विकल्प देना है।
- Since 2016, SSS interest rates have been notified quarterly by the DEA based on bond yields and market trends.
- 2016 से SSS की ब्याज दरें बॉन्ड यील्ड और बाजार रुझानों के आधार पर तिमाही रूप से DEA द्वारा अधिसूचित की जाती हैं।
- The methodology for determining SSS interest rates was recommended by the श्यामला गोपीनाथ समिति in January 2023.



- SSS की ब्याज दर तय करने की पद्धति जनवरी 2023 में श्यामला गोपीनाथ समिति द्वारा सुझाई गई थी।
- The committee recommended rates should be 25 to 100 basis points higher than government bond yields.
- समिति ने सुझाव दिया कि इन योजनाओं की ब्याज दरें सरकारी बॉन्ड यील्ड से 25 से 100 बेसिस प्वाइंट अधिक होनी चाहिए।

### Interest Rates on Small Savings Schemes for Q4FY26 (1st January, 2026 to 31st March, 2026):

- Post Office Savings Deposit : 4.0%
- 1-Year Post Office Time Deposits : 6.9%
- 2-Year Post Office Time Deposits : 7.0%
- 3-Year Post Office Time Deposits : 7.1%
- 5-Year Post Office Time Deposits : 7.5%
- 5-Year Post Office Recurring Deposits : 6.7%
  
- Kisan Vikas Patra : 7.5% (will mature in 115 months)
- Public Provident Fund : 7.1%
- Sukanya Samriddhi Yojana : 8.2%
- National Savings Certificate : 7.7%
- Senior Citizen Savings Scheme : 8.2%
- Post Office Monthly Income Scheme : 7.4%
- Mahila Samman Savings Certificate : 7.5%

EXAM  
Genius





**Ques: What is the title of the podcast series launched by the Reserve Bank of India to enhance public communication?**

सार्वजनिक संचार को मजबूत करने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला का नाम क्या है?

- A) RBI Speaks: Economy Explained / RBI स्पीक्स: इकोनॉमी एक्सप्लेंड
- B) Paisa aur Arthvyavastha / पैसा और अर्थव्यवस्था
- C) RBI Talks: Paisa to Policy / RBI टॉक्स: पैसा टू पॉलिसी
- D) Monetary Matters by RBI / RBI द्वारा मॉनेटरी मैटर्स
- E) Policy to Public / पॉलिसी टू पब्लिक

**Answer: Option C**

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India proposed adding podcasts to its communication toolkit to widely disseminate information of public interest.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाने के लिए पॉडकास्ट को अपने संचार साधनों में शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
- Accordingly, RBI launched its podcast series titled “RBI Talks: Paisa to Policy.”
- इसके तहत RBI ने “RBI Talks: Paisa to Policy” नामक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की।
- The first episode of the series is titled “Demystifying KYC.”
- इस श्रृंखला का पहला एपिसोड “Demystifying KYC” शीर्षक से जारी किया गया है।

EXAM  
Genius





**Ques: What is the key objective of RBI's NBFC (Prudential Norms on Capital Adequacy) Amendment Directions, 2026?**

RBI द्वारा जारी NBFC (पूंजी पर्याप्तता विवेकपूर्ण मानदंड) संशोधन निर्देश, 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Increasing capital requirements for all NBFC loans / सभी NBFC ऋणों के लिए पूंजी आवश्यकता बढ़ाना
- B) Providing subsidies for infrastructure projects / अवसंरचना परियोजनाओं को सब्सिडी देना
- C) Easing capital adequacy norms for NBFC lending to high-quality infrastructure projects / उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने वाले NBFC के लिए पूंजी मानदंडों में ढील देना
- D) Restricting NBFC exposure to infrastructure sector / NBFC के अवसंरचना क्षेत्र में जोखिम को सीमित करना
- E) Introducing new licensing norms for NBFCs / NBFC के लिए नए लाइसेंसिंग नियम लागू करना

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The RBI has eased capital adequacy norms for Non-Banking Finance Companies (NBFCs) lending to high-quality infrastructure projects through Amendment Directions, 2026.
- RBI ने उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने वाले NBFC के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में ढील दी है।
- Risk weight has been reduced to 75% if at least 2% of sanctioned project debt is repaid, instead of the earlier draft requirement of 5% but less than 10%.
- यदि स्वीकृत परियोजना ऋण का कम से कम 2% चुका दिया गया है, तो जोखिम भार 75% होगा।
- A lower 50% risk weight will apply if at least 5% of the sanctioned project debt is repaid, relaxed from the earlier 10% threshold.
- यदि कम से कम 5% ऋण चुका दिया गया है, तो जोखिम भार 50% होगा।
- The directions will be applicable from April 1, 2026, or earlier if adopted fully by an NBFC.
- ये निर्देश 1 अप्रैल 2026 से या NBFC द्वारा पहले अपनाने पर लागू होंगे।
- A project will be considered high-quality if it has completed one year after Commercial Operation Date (COD), has no material covenant breach, and is classified as standard.
- परियोजना को उच्च गुणवत्ता वाली माना जाएगा यदि COD के बाद एक वर्ष पूरा हो चुका हो और वह स्टैंडर्ड श्रेणी में हो।
- NBFCs may continue existing risk weights until the next review or March 31, 2027, whichever is earlier.
- NBFC अगले पुनरीक्षण या 31 मार्च 2027 तक मौजूदा जोखिम भार जारी रख सकते हैं।





**Ques: What percentage of ₹2000 banknotes in circulation as on May 19, 2023 has been returned so far?**

19 मई 2023 को प्रचलन में मौजूद ₹2000 के नोटों में से अब तक कितना प्रतिशत वापस आ चुका है?

- A) 95.20%
- B) 96.85%
- C) 97.40%
- D) 98.41%
- E) 99.10%

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- The total value of ₹2000 banknotes in circulation was ₹3.56 lakh crore on May 19, 2023, when their withdrawal was announced.
- 19 मई 2023 को ₹2000 के नोटों की कुल प्रचलित राशि ₹3.56 लाख करोड़ थी।
- This value declined sharply to ₹5,669 crore by the close of business on December 31, 2025.
- 31 दिसंबर 2025 तक यह घटकर ₹5,669 करोड़ रह गई।
- As a result, 98.41% of the ₹2000 banknotes in circulation as on May 19, 2023 have been returned.
- इस प्रकार 19 मई 2023 को प्रचलन में मौजूद ₹2000 के 98.41% नोट वापस आ चुके हैं।
- The facility for deposit and/or exchange was available at all bank branches till October 7, 2023.
- जमा या विनिमय की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी।
- Exchange of ₹2000 banknotes continues at 19 RBI Issue Offices since May 19, 2023.
- ₹2000 के नोटों के विनिमय की सुविधा 19 RBI इश्यू कार्यालयों में 19 मई 2023 से उपलब्ध है।





**Ques: What is the interest rate on the RBI Floating Rate Savings Bond, 2020 (Taxable) for the period January–June 2026?**

जनवरी–जून 2026 की अवधि के लिए RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, 2020 (करयोग्य) की ब्याज दर क्या है?

- A) 7.70%
- B) 7.85%
- C) 8.00%
- D) 8.05%
- E) 8.35%

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- The interest rate on the Floating Rate Savings Bond, 2020 (Taxable) has been announced for the period January 1, 2026 to June 30, 2026.
- फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, 2020 (करयोग्य) की ब्याज दर 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए घोषित की गई है।
- The bond carries a floating interest rate, which is reset every six months, and has a maturity period of seven years.
- इस बॉन्ड की ब्याज दर परिवर्तनीय है, जिसे हर छह महीने में रीसेट किया जाता है, और इसकी परिपक्वता अवधि सात वर्ष है।
- Interest on the bond is paid twice a year, on January 1 and July 1.
- इस बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है।
- The coupon rate is fixed at 35 basis points (0.35%) above the National Savings Certificate (NSC) rate.
- कूपन दर राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की ब्याज दर से 35 बेसिस पॉइंट (0.35%) अधिक निर्धारित की जाती है।
- For the current half-year, the NSC rate is 7.70%, making the FRSB interest rate 8.05%.
- वर्तमान अर्धवार्षिक अवधि के लिए NSC की दर 7.70% है, जिससे FRSB की ब्याज दर 8.05% बनती है।
- Interest for this period will be paid on July 1, 2026, and since the bond is taxable, the interest is added to income and taxed as per applicable slabs.
- इस अवधि का ब्याज 1 जुलाई 2026 को दिया जाएगा और यह करयोग्य होगा, जिसे आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा।





**Ques: The recent Access and Benefit Sharing (ABS) disbursement of ₹45 lakh was released by the National Biodiversity Authority to farmers of which state?**

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी ₹45 लाख की एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) राशि किसानों को किस राज्य में दी गई?

- A) Tamil Nadu / तमिलनाडु
- B) Karnataka / कर्नाटक
- C) Maharashtra / महाराष्ट्र
- D) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
- E) Odisha / ओडिशा

**Answer:** Option D

**Explanation | व्याख्या:**

- The National Biodiversity Authority released ₹45 lakh (USD 50,000) to farmers of Andhra Pradesh through the Andhra Pradesh State Biodiversity Board.
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से आंध्र प्रदेश के किसानों को ₹45 लाख जारी किए।
- With this release, India's cumulative ABS disbursement has crossed ₹143.5 crore (USD 16 million).
- इस जारी राशि के साथ भारत का कुल ABS वितरण ₹143.5 करोड़ से अधिक हो गया है।
- So far, over ₹104 crore has been released to Andhra Pradesh for Red Sanders conservation and benefit claimers.
- अब तक रेड सैंडर्स संरक्षण और लाभार्थियों के लिए आंध्र प्रदेश को ₹104 करोड़ से अधिक दिए गए हैं।
- More than ₹15 crore has been disbursed to other states including Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Odisha and Telangana.
- तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना सहित अन्य राज्यों को ₹15 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है।





**Ques: Who has been appointed as the chief coach of the Indian women's hockey team by Hockey India?**

हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Graham Reid / ग्राहम रीड
- B) Roelant Oltmans / रोलेट ओल्टमन्स
- C) Harendra Singh / हरेंद्र सिंह
- D) Janneke Schopman / जान्नेके स्कोपमैन
- E) Sjoerd Marijne / स्जोर्ड मारिज्ने

**Answer:** Option E

**Explanation | व्याख्या:**

- Hockey India has appointed Sjoerd Marijne as the chief coach of the Indian women's hockey team.
- हॉकी इंडिया ने स्जोर्ड मारिज्ने को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है।
- He is a Dutch hockey coach with strong international experience.
- वह अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले डच हॉकी कोच हैं।
- He earlier guided the Indian women's team to a historic fourth-place finish at the Tokyo 2020 Olympics.
- उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय महिला टीम को ऐतिहासिक चौथा स्थान दिलाया था।
- Marijne was first appointed as head coach of the Indian women's hockey team in 2017.
- उन्हें पहली बार 2017 में भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया था।
- His first major assignment will be the FIH Hockey Women's World Cup Qualifiers in Hyderabad from 8 to 14 March.
- उनका पहला प्रमुख कार्य 8 से 14 मार्च तक हैदराबाद में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालीफायर होंगे।





**Ques: Where was the first Gen Z Post Office in Jammu and Kashmir inaugurated?**

जम्मू और कश्मीर में पहला Gen Z पोस्ट ऑफिस कहाँ उद्घाटित किया गया?

- A) AIIMS Vijaypur / एम्स विजयपुर
- B) Sher-i-Kashmir Institute of Medical Sciences / शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान
- C) University of Jammu / जम्मू विश्वविद्यालय
- D) Lal Chowk, Srinagar / लाल चौक, श्रीनगर
- E) Government Medical College, Anantnag / सरकारी मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग

**Answer:** Option A

**Explanation | व्याख्या:**

- The first Gen Z Post Office in Jammu and Kashmir has been inaugurated at AIIMS Vijaypur.
- जम्मू और कश्मीर में पहला Gen Z पोस्ट ऑफिस एम्स विजयपुर में उद्घाटित किया गया है।
- It is implemented by the Department of Posts under the campus post office modernisation initiative.
- इसे डाक विभाग द्वारा कैंपस पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण पहल के तहत लागू किया गया है।
- The initiative aims to make postal services youth-centric and technology-enabled.
- इस पहल का उद्देश्य डाक सेवाओं को युवा-केंद्रित और तकनीक-सक्षम बनाना है।

EXAM  
Genius





**Ques: NTPC Limited signed an MoA with Gujarat Cancer & Research Institute for which purpose?**

NTPC लिमिटेड ने गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ किस उद्देश्य से समझौता किया?

- A) Establishment of a new medical college / नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना
- B) Upgradation of radiotherapy services / रेडियोथेरेपी सेवाओं का उन्नयन
- C) Free cancer screening programme / निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम
- D) Research on herbal cancer medicines / हर्बल कैंसर दवाओं पर शोध
- E) Training of oncology doctors / ऑन्कोलॉजी डॉक्टरों का प्रशिक्षण

**Answer:** Option B

**Explanation | व्याख्या:**

- NTPC Limited – Western Region–I signed an MoA with Gujarat Cancer & Research Institute for upgradation of radiotherapy services under its CSR initiative.
- NTPC लिमिटेड – वेस्टर्न रीजन–I ने अपनी CSR पहल के तहत रेडियोथेरेपी सेवाओं के उन्नयन के लिए गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया।
- NTPC has sanctioned ₹23.16 crore for the Siddhpur Satellite Centre of GCRI, Ahmedabad.
- NTPC ने अहमदाबाद स्थित GCRI के सिद्धपुर सैटेलाइट सेंटर के लिए ₹23.16 करोड़ स्वीकृत किए हैं।
- The support will be used for procurement and installation of a high-energy Linear Accelerator (LINAC).
- यह सहायता उच्च-ऊर्जा लिनियर एक्सेलेरेटर (LINAC) की खरीद और स्थापना के लिए उपयोग की जाएगी।
- The project will enhance advanced cancer treatment and improve access to quality radiotherapy in the region.
- इससे उन्नत कैंसर उपचार क्षमताएं बढ़ेंगी और क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण रेडियोथेरेपी तक पहुंच में सुधार होगा।

**About NTPC Limited :**

- Established :1975
- HQ : New Delhi
- Chairman : Gurdeep Singh





**Ques: How many new proposals were approved by MeitY under the Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS)?**

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत MeitY ने कितने नए प्रस्तावों को मंजूरी दी?

- A) 22
- B) 20
- C) 18
- D) 24
- E) 26

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) approved 22 new proposals under Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS).
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ECMS के तहत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- These projects involve an investment of ₹41,863 crore with estimated production of ₹2.58 lakh crore.
- इन परियोजनाओं में ₹41,863 करोड़ का निवेश और ₹2.58 लाख करोड़ का अनुमानित उत्पादन शामिल है।
- Total approvals under ECMS have now reached 46 projects with cumulative investment of ₹56,567 crore.
- ECMS के तहत कुल स्वीकृत परियोजनाएं बढ़कर 46 हो गई हैं, जिनमें कुल निवेश ₹56,567 करोड़ है।
- The projects are spread across eight states including Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Rajasthan.
- ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैली हुई हैं।
- ECMS has an outlay of ₹22,919 crore with a tenure of six years and one year gestation period.
- ECMS का कुल परिव्यय ₹22,919 करोड़ है और इसकी अवधि छह वर्ष है।
- The scheme targets investment of ₹59,350 crore and production of ₹4,56,500 crore.
- इस योजना का लक्ष्य ₹59,350 करोड़ का निवेश और ₹4,56,500 करोड़ का उत्पादन है।





**Ques: Technology Development Board signed an agreement with Vijai Marine Services Private Limited for which project?**

टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने विजई मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ किस परियोजना के लिए समझौता किया है?

- A) Smart River Navigation Project / स्मार्ट नदी नेविगेशन परियोजना
- B) Smart Sea Project by VACE / VACE द्वारा स्मार्ट सी परियोजना
- C) Green Ferry Mission / ग्रीन फेरी मिशन
- D) Electric Coastal Transport Scheme / इलेक्ट्रिक तटीय परिवहन योजना
- E) Autonomous Shipping Initiative / स्वायत्त शिपिंग पहल

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- Technology Development Board signed an agreement with Vijai Marine Services Private Limited (VMSPL), Goa, for the Smart Sea Project by Vijai Autonomous Craft for Environment (VACE).
- टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने गोवा की विजई मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ विजई ऑटोनॉमस क्राफ्ट फॉर एनवायरनमेंट (VACE) की स्मार्ट सी परियोजना के लिए समझौता किया।
- The project is supported under the Indo-Canada Collaborative Industrial Research and Development Programme of DST, National Research Council Canada, and Global Affairs Canada.
- यह परियोजना DST, नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा और ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की इंडो-कनाडा सहयोगी औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत समर्थित है।
- It aims to develop and demonstrate a 20-passenger electric boat to promote clean waterways, reduced fossil fuel use, and sustainable tourism.
- इसका उद्देश्य स्वच्छ जलमार्ग, जीवाश्म ईंधन के कम उपयोग और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 20 यात्री क्षमता वाली इलेक्ट्रिक नाव विकसित करना है।





**Ques: What has the Indian Army declared the year 2026 as under its official vision?**

भारतीय सेना ने अपनी आधिकारिक दृष्टि के तहत वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है?

- A) Year of Digital Warfare / डिजिटल युद्ध का वर्ष
- B) Year of Cyber Security / साइबर सुरक्षा का वर्ष
- C) Year of Networking & Data Centricity / नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष
- D) Year of Defence Reforms / रक्षा सुधारों का वर्ष
- E) Year of Indigenous Innovation / स्वदेशी नवाचार का वर्ष

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Indian Army, under the leadership of Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi, has declared 2026 as the 'Year of Networking & Data Centricity'.
- भारतीय सेना ने थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में वर्ष 2026 को 'नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष' घोषित किया है।
- This declaration is part of the Indian Army's official vision for 2026.
- यह घोषणा भारतीय सेना की 2026 की आधिकारिक दृष्टि का हिस्सा है।
- It builds upon the 2024–25 'Year of Technology Absorption' by operationalising the technologies already absorbed.
- यह 2024–25 के 'प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष' पर आधारित है, जिसमें आत्मसात की गई तकनीकों को व्यवहार में लाया जाएगा।





**Ques: At which meeting was the BRICS Presidency formally handed over from Brazil to India?**

ब्राज़ील से भारत को BRICS अध्यक्षता औपचारिक रूप से किस बैठक में सौंपी गई?

- A) BRICS Leaders' Summit / BRICS शिखर सम्मेलन
- B) BRICS Foreign Ministers' Meeting / BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक
- C) 4th BRICS Sherpas Meeting / चौथी BRICS शेरपा बैठक
- D) BRICS Business Forum / BRICS बिज़नेस फ़ोरम
- E) BRICS Parliamentary Forum / BRICS संसदीय फ़ोरम

**Answer:** Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- The BRICS Presidency was handed over from Brazil to India at the concluding session of the 4th BRICS Sherpas Meeting.
- चौथी BRICS शेरपा बैठक के समापन सत्र में ब्राज़ील से भारत को BRICS अध्यक्षता सौंपी गई।
- BRICS is a grouping of major emerging economies of the Global South: Brazil, Russia, India, China and South Africa.
- BRICS वैश्विक दक्षिण की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।
- The grouping focuses on development, trade, finance and reforms in global governance, with the presidency rotating annually.
- इसका फोकस विकास, व्यापार, वित्त और वैश्विक शासन सुधारों पर है तथा अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है।
- Brazil is the outgoing President, while India will assume the BRICS Presidency in 2026.
- ब्राज़ील निवर्तमान अध्यक्ष है, जबकि भारत 2026 में BRICS की अध्यक्षता करेगा।
- The handover was symbolised by the ceremonial BRICS Gavel, exchanged between Brazil Sherpa Mauricio Lyrio and India Sherpa Sudhakar Dalela.
- यह हस्तांतरण ब्राज़ील के शेरपा मौरिसियो लिरियो और भारत के शेरपा सुधाकर दलेला के बीच औपचारिक BRICS गवेल के माध्यम से हुआ।
- The gavel, made from repurposed Amazon rainforest wood (Itaúba and Pau Rainha), symbolises sustainability, climate cooperation and continuity among BRICS nations.
- अमेज़न वर्षावन की पुनः उपयोग की गई लकड़ी (इटाउबा और पाउ रैनहा) से बना यह गवेल स्थिरता, जलवायु सहयोग और BRICS देशों के बीच निरंतर सहयोग का प्रतीक है।





**Ques: Where was the indigenous Kavach 4.0 system officially commissioned by Indian Railways?**

भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी कवच 4.0 प्रणाली को कहाँ आधिकारिक रूप से चालू किया गया?

- A) Mumbai–Pune section / मुंबई–पुणे खंड
- B) Delhi–Agra section / दिल्ली–आगरा खंड
- C) Bajwa (Vadodara)–Ahmedabad section / बाजवा (वडोदरा)–अहमदाबाद खंड
- D) Chennai–Bengaluru section / चेन्नई–बेंगलुरु खंड
- E) Howrah–Patna section / हावड़ा–पटना खंड

**Answer:** Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- Vadodara division of Western Railways commissioned the indigenous Kavach 4.0 system on the 96 km Bajwa (Vadodara)–Ahmedabad section covering 17 stations in Gujarat.
- पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने गुजरात में 17 स्टेशनों वाले 96 किमी लंबे बाजवा (वडोदरा)–अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी कवच 4.0 प्रणाली को चालू किया।
- Sankalp Fast became the first Kavach-enabled train on this route.
- संकल्प फास्ट इस मार्ग पर पहली कवच-सक्षम ट्रेन बनी।
- Kavach is an indigenously developed Automatic Train Protection system of Indian Railways that prevents signal passing at danger, controls overspeeding, and avoids head-on and rear-end collisions.
- कवच भारतीय रेलवे की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जो सिग्नल उल्लंघन, अधिक गति और आमने-सामने व पीछे से टकराव को रोकती है।
- It uses RFID tags and ultra high frequency radio communication for real-time data exchange between tracks, signals, and locomotives.
- इसमें ट्रेक, सिग्नल और इंजनों के बीच वास्तविक समय डेटा आदान-प्रदान के लिए RFID टैग और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो का उपयोग होता है।
- Indian Railways has implemented Kavach on more than 2,200 route kilometers so far.
- अब तक भारतीय रेलवे द्वारा 2,200 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच लागू किया जा चुका है।
- Kavach 4.0 received formal approval from RDSO in July 2024.
- कवच 4.0 को जुलाई 2024 में RDSO से औपचारिक मंजूरी मिली।
- The upgraded system offers better location accuracy, improved signal detection, seamless interlocking, and optical fibre–based connectivity.
- उन्नत कवच प्रणाली में बेहतर लोकेशन सटीकता, उन्नत सिग्नल पहचान, इंटरलॉकिंग एकीकरण और ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्टिविटी है।





**Ques: Who has been appointed as the Director General (DG) of the Directorate General of Foreign Trade (DGFT)?**

निदेशालय सामान्य विदेशी व्यापार (DGFT) के महानिदेशक (DG) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Ajay Bhadoo / अजय भादू
- B) Ashutosh Agnihotri / आशुतोष अग्निहोत्री
- C) Rabindra Kumar Agarwal / रबींद्र कुमार अग्रवाल
- D) Lav Aggarwal / लव अग्रवाल
- E) Pankaj Jain / पंकज जैन

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Appointments Committee of the Cabinet appointed Lav Aggarwal as Director General of the Directorate General of Foreign Trade.
- नियुक्ति समिति ने लव अग्रवाल को महानिदेशालय सामान्य विदेशी व्यापार का महानिदेशक नियुक्त किया।
- Lav Aggarwal has succeeded Ajay Bhadoo as DG of DGFT.
- लव अग्रवाल ने अजय भादू का स्थान लिया है।
- The committee also appointed Rabindra Kumar Agarwal as Chairman and Managing Director of the Food Corporation of India.
- इसी के साथ रबींद्र कुमार अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।
- Rabindra Kumar Agarwal replaced Ashutosh Agnihotri, who is now Additional Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- रबींद्र कुमार अग्रवाल ने आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान लिया, जिन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।





**Ques: What is the objective of the 'Viksit Bharat Mumbai Marina' project approved at Mumbai Harbour?**

‘विकसित भारत मुंबई मरीना’ परियोजना का उद्देश्य क्या है?

- A) Development of inland waterways cargo hub / अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो हब का विकास
- B) Creation of global-standard maritime tourism infrastructure / वैश्विक स्तर के समुद्री पर्यटन अवसंरचना का निर्माण
- C) Expansion of naval dockyard facilities / नौसैनिक डॉकयार्ड सुविधाओं का विस्तार
- D) Establishment of a fishing export zone / मत्स्य निर्यात क्षेत्र की स्थापना
- E) Development of offshore oil terminals / अपतटीय तेल टर्मिनलों का विकास

**Answer:** Option B

**Explanation | व्याख्या:**

- Viksit Bharat Mumbai Marina project will be developed at Mumbai Harbour with an estimated cost of ₹887 crore.
- विकसित भारत मुंबई मरीना परियोजना मुंबई हार्बर में ₹887 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित की जाएगी।
- The project has been approved by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
- इस परियोजना को बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई है।
- It aligns with the vision of Prime Minister Narendra Modi and aims to create global-standard maritime tourism infrastructure.
- यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप है और वैश्विक स्तर की समुद्री पर्यटन अवसंरचना विकसित करने का लक्ष्य रखती है।
- The project supports India's maritime economy and blue economy goals.
- यह भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था और ब्लू इकोनॉमी लक्ष्यों को समर्थन देती है।
- It will be developed under a hybrid model, with Mumbai Port Authority investing ₹470 crore under EPC for core infrastructure.
- इसे हाइब्रिड मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें मुंबई पोर्ट अथॉरिटी EPC के अंतर्गत ₹470 करोड़ निवेश करेगी।
- Private players will invest ₹417 crore for onshore facilities; tenders have been floated with bid closure on 29 December 2025.
- निजी क्षेत्र द्वारा ऑनशोर सुविधाओं के लिए ₹417 करोड़ का निवेश किया जाएगा; निविदा जारी हो चुकी है और बोली की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2025 है।
- The marina will cover about 12 hectares of water area with berthing capacity for 424 yachts up to 30 metres in length.
- मरीना लगभग 12 हेक्टेयर जल क्षेत्र में फैला होगा और 30 मीटर तक की 424 यॉट्स के ठहराव की क्षमता रखेगा।



## Ques: What is the purpose of the newly introduced e-Production Investment Business Visa (e-B-4 Visa)?

नए शुरू किए गए ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा (e-B-4 Visa) का उद्देश्य क्या है?

- A) Facilitating tourist travel to India / भारत में पर्यटन यात्रा को आसान बनाना
- B) Enabling long-term academic research / दीर्घकालिक शैक्षणिक शोध को सक्षम बनाना
- C) Simplifying entry of foreign professionals for production-related investments / उत्पादन से जुड़े निवेशों हेतु विदेशी पेशेवरों के प्रवेश को सरल बनाना
- D) Allowing foreign citizens to seek employment / विदेशी नागरिकों को रोजगार खोजने की अनुमति देना
- E) Promoting medical tourism in India / भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना

Answer: Option C

### Explanation | व्याख्या:

- The Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of Commerce and Industry has simplified the e-Visa process for foreign professionals.
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT ने विदेशी पेशेवरों के लिए ई-वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाया है।
- A new visa category called e-Production Investment Business Visa (e-B-4 Visa) has been introduced under the Business Visa regime.
- बिजनेस वीज़ा व्यवस्था के तहत e-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा (e-B-4) की नई श्रेणी शुरू की गई है।
- It is issued as a fully online e-Visa through the Visa portal.
- यह वीज़ा पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन जारी किया जाता है।
- The visa allows invitation of foreign professionals for installation and commissioning of machinery, quality checks, essential maintenance, and production or IT ramp-up.
- यह वीज़ा मशीनरी की स्थापना, गुणवत्ता जांच, आवश्यक रखरखाव तथा उत्पादन व IT रैम्प-अप हेतु विदेशी पेशेवरों को आमंत्रित करने की अनुमति देता है।
- It also covers training of staff, plant design and bring-up, supply chain development, vendor empanelment, and senior management visits related to production investment.
- इसमें स्टाफ प्रशिक्षण, प्लांट डिज़ाइन, सप्लाय चैन विकास, वेंडर एम्पैनलमेंट और उत्पादन निवेश से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन दौड़ों को भी शामिल किया गया है।





**Ques: Who won the 'Best International Military Student' Award at the Command and General Staff College in the Philippines?**

फिलीपींस के कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में 'बेस्ट इंटरनेशनल मिलिट्री स्टूडेंट' पुरस्कार किसने जीता?

- A) Commander Akhil Nair / कमांडर अखिल नायर
- B) Commander Abhinav Singh / कमांडर अभिनव सिंह
- C) Commander Ravi Kumar / कमांडर रवि कुमार
- D) Captain Arjun Mehta / कैप्टन अर्जुन मेहता
- E) Commander Suresh Iyer / कमांडर सुरेश अय्यर

**Answer:** Option A

**Explanation | व्याख्या:**

- Commander Akhil Nair won the 'Best International Military Student' Award.
- कमांडर अखिल नायर ने 'बेस्ट इंटरनेशनल मिलिट्री स्टूडेंट' पुरस्कार जीता।
- The award was conferred at the Command and General Staff College in Quezon City, Philippines.
- यह पुरस्कार फिलीपींस के क्यूज़ोन सिटी स्थित कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में प्रदान किया गया।
- He completed his studies with distinction and secured second overall rank.
- उन्होंने विशिष्टता के साथ अध्ययन पूरा किया और कुल मिलाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया।
- A total of 197 officers from various countries participated in the course.
- इस पाठ्यक्रम में विभिन्न देशों के कुल 197 अधिकारियों ने भाग लिया।

Genius





**Ques: Air India has signed a unilateral codeshare agreement with which airline to enhance connectivity between India and the Baltic region?**

एयर इंडिया ने भारत और बाल्टिक क्षेत्र के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए किस एयरलाइन के साथ एकतरफा कोडशेयर समझौता किया है?

- A) Finnair / फिनएयर
- B) airBaltic / एयर बाल्टिक
- C) LOT Polish Airlines / एलओटी पोलिश एयरलाइंस
- D) Lufthansa / लुफ्थांसा
- E) SAS Scandinavian Airlines / एसएस स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस

**Answer: Option B**

Explanation | व्याख्या:

- Air India and airBaltic, Latvia's national airline, signed a unilateral codeshare agreement to improve connectivity between India and the Baltic region via European hubs.
- एयर इंडिया और लातविया की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर बाल्टिक ने यूरोपीय हब के माध्यम से भारत और बाल्टिक क्षेत्र के बीच संपर्क बढ़ाने हेतु एकतरफा कोडशेयर समझौता किया।
- A codeshare allows one airline to sell tickets on flights operated by another airline using its own flight code.
- कोडशेयर व्यवस्था में एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन द्वारा संचालित उड़ानों पर अपने कोड से टिकट बेच सकती है।
- The Baltic region includes Estonia, Latvia, and Lithuania, located along the eastern coast of the Baltic Sea.
- बाल्टिक क्षेत्र में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं, जो बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित हैं।





**Ques: Who has been appointed as the Interim President of Venezuela?**

वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Delcy Rodríguez / डेलसी रोड्रिगेज
- B) Juan Guaidó / जुआन गुआइदो
- C) Nicolás Maduro / निकोलस मादुरो
- D) Diosdado Cabello / डियोसदादो कैबेलो
- E) Jorge Rodríguez / जॉर्ज रोड्रिगेज

**Answer: Option A**

Explanation | व्याख्या:

- Delcy Rodríguez has been appointed as the Interim President of Venezuela by the Supreme Court.
- डेलसी रोड्रिगेज को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है।
- She replaced Nicolás Maduro and was earlier serving as Vice President since 2018.
- उन्होंने निकोलस मादुरो का स्थान लिया और इससे पहले 2018 से उपराष्ट्रपति थीं।
- Capital of Venezuela is Caracas and the currency is Bolívar.
- वेनेजुएला की राजधानी काराकास है और मुद्रा बोलीवार है।

EXAM  
Genius





**Ques: Which day is observed as National Bird Day in India?**

भारत में नेशनल बर्ड डे किस दिन मनाया जाता है?

- A) 1 January / 1 जनवरी
- B) 5 January / 5 जनवरी
- C) 8 March / 8 मार्च
- D) 22 April / 22 अप्रैल
- E) 12 October / 12 अक्टूबर

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- National Bird Day is observed on 5 January every year.
- नेशनल बर्ड डे हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है।
- It was started in 2002 by the Avian Welfare Coalition.
- यह पहल 2002 में एवियन वेलफेयर कोलिशन द्वारा शुरू की गई थी।
- The day honors Salim Ali, popularly known as the Birdman of India.
- इस दिन का उद्देश्य भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, को सम्मानित करना है।

EXAM  
Genius





Ques: Asian Development Bank (ADB) provided ₹4,100 crore assistance to which state for Musi Riverfront Development Project Phase-I?

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने मुसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना चरण-I के लिए किस राज्य को ₹4,100 करोड़ की सहायता दी?

- A) Telangana / तेलंगाना
- B) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
- C) Tamil Nadu / तमिलनाडु
- D) Karnataka / कर्नाटक
- E) Maharashtra / महाराष्ट्र

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Asian Development Bank provided ₹4,100 crore (USD 500 million) to the Government of Telangana.
- एशियाई विकास बैंक ने तेलंगाना सरकार को ₹4,100 करोड़ (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) प्रदान किए।
- The amount was given to the Minister for Industries and Commerce, Government of Telangana.
- यह राशि तेलंगाना सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री को दी गई।
- The assistance is for Phase-I of the Musi Riverfront Development Project.
- यह सहायता मुसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना के प्रथम चरण के लिए है।
- The project aims to rejuvenate and restore the Musi River.
- इस परियोजना का उद्देश्य मुसी नदी का पुनर्जीवन करना है।





Ques: Who chaired the first meeting of the Payments Regulatory Board (PRB)?  
पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की?

- A) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- B) S Krishnan / एस. कृष्णन
- C) T Rabi Sankar / टी. रबी शंकर
- D) Aruna Sundararajan / अरुणा सुंदरराजन
- E) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The first meeting of the Payments Regulatory Board (PRB) was held in Mumbai under the chairmanship of RBI Governor Sanjay Malhotra.
- पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (PRB) की पहली बैठक मुंबई में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई।
- The Board reviewed the functioning of the Department of Payment and Settlement Systems and domestic and global payment systems.
- बोर्ड ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग तथा घरेलू और वैश्विक भुगतान प्रणालियों की समीक्षा की।
- The draft Payments Vision 2028 was presented for strategic guidance.
- ड्राफ्ट पेमेंट्स विजन 2028 प्रस्तुत किया गया।
- PRB was constituted after amendment to the Payment and Settlement Systems Act, 2007, effective from 9 May 2025.
- PRB का गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में 9 मई 2025 से प्रभावी संशोधन के बाद किया गया।
- PRB replaced the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS).
- PRB ने भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) का स्थान लिया।
- Members present included S Krishnan, Nagaraju Maddirala, Aruna Sundararajan, T Rabi Sankar, and Vivek Deep.
- बैठक में एस. कृष्णन, नागराजू मड्डीराला, अरुणा सुंदरराजन, टी. रबी शंकर और विवेक दीप उपस्थित थे।





**Ques: Who has been appointed as the Chairman of ESAF Small Finance Bank?**

ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) R. P. Ramakrishnan / आर. पी. रामकृष्णन
- B) Karthikeyan Manickam / कार्तिकेयन मणिक्कम
- C) K. Paul Thomas / के. पॉल थॉमस
- D) Rajnish Kumar / रजनीश कुमार
- E) Shyam Srinivasan / श्याम श्रीनिवासन

Answer: Option B

**Explanation | व्याख्या:**

- Karthikeyan Manickam, former Executive Director (ED) of Bank of India, has been appointed as the Chairman of ESAF Small Finance Bank (ESAF SFB).
- बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक (ED) कार्तिकेयन मणिक्कम को ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- He replaced R. P. Ramakrishnan in this position.
- उन्होंने इस पद पर आर. पी. रामकृष्णन का स्थान लिया है।
- ESAF Small Finance Bank was established on 10 March 2017.
- ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 10 मार्च 2017 को हुई थी।
- The headquarters of ESAF Small Finance Bank is located in Thrissur, Kerala.
- ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय त्रिशूर, केरल में स्थित है।
- Shri K. Paul Thomas is the Managing Director and CEO of the bank.
- श्री के. पॉल थॉमस बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं।





**Ques: What major milestone was announced in the Mumbai–Ahmedabad High Speed Rail (MAHSR) project in Maharashtra?**

मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) परियोजना में महाराष्ट्र में कौन सा प्रमुख मील का पत्थर घोषित किया गया?

- A) Completion of the longest underground tunnel in Gujarat / गुजरात में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग का निर्माण
- B) Breakthrough of the second mountain tunnel in Palghar / पालघर में दूसरी पर्वतीय सुरंग का ब्रेकथ्रू
- C) Inauguration of Virar bullet train station / विरार बुलेट ट्रेन स्टेशन का उद्घाटन
- D) Completion of the entire tunnel network / पूरे सुरंग नेटवर्क का पूरा होना
- E) Start of commercial operations of bullet train / बुलेट ट्रेन का वाणिज्यिक संचालन शुरू

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister Shri Ashwini Vaishnaw announced the breakthrough of the second tunnel in Palghar, Maharashtra, marking the first mountain tunnel of the Bullet Train Project in the state.
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के पालघर में दूसरी सुरंग के ब्रेकथ्रू की घोषणा की, जो राज्य की पहली पर्वतीय सुरंग है।
- The breakthrough was achieved in the 1.5 km long mountain tunnel MT-5 between Virar and Boisar bullet train stations.
- यह उपलब्धि विरार और बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशनों के बीच 1.5 किमी लंबी पर्वतीय सुरंग MT-5 में हासिल की गई।
- Earlier, a 5 km underground tunnel between Thane and BKC was completed in September 2025.
- इससे पहले ठाणे और बीकेसी के बीच 5 किमी लंबी भूमिगत सुरंग सितंबर 2025 में पूरी हुई थी।
- The Mumbai–Ahmedabad High Speed Rail (MAHSR) project is 508 km long with a total tunnel length of 27.4 km, including 21 km underground and 6.4 km surface tunnels.
- MAHSR परियोजना की कुल लंबाई 508 किमी है, जिसमें 27.4 किमी सुरंगें शामिल हैं।
- The project includes eight mountain tunnels and connects major cities from Sabarmati to Mumbai across Gujarat, Dadra & Nagar Haveli, and Maharashtra.
- इस परियोजना में आठ पर्वतीय सुरंगें हैं और यह गुजरात, दादरा व नगर हवेली तथा महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों को जोड़ती है।
- The MAHSR spans approximately 508 kilometres, covering 352 km in Gujarat and Dadra & Nagar Haveli, and 156 km in Maharashtra





- महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजमार्ग (एमएचएसआर) लगभग 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 352 किलोमीटर गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली में तथा 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में स्थित है।

### About Maharashtra :

- Capital : Mumbai
- CM : Devendra Fadnavis
- Governor : Acharya Devvrat



EXAM  
Genius





**Ques: Who is set to become the oldest woman to play at the Australian Open after receiving a wildcard entry?**

वाइल्डकार्ड एंट्री मिलने के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने वाली सबसे उम्रदराज़ महिला कौन बनने जा रही हैं?

- A) Serena Williams / सेरेना विलियम्स
- B) Kimiko Date / किमिको डेट
- C) Venus Williams / वीनस विलियम्स
- D) Martina Navratilova / मार्टिना नवरातिलोवा
- E) Victoria Azarenka / विक्टोरिया अजारेंका

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Venus Williams (45) has been awarded a wildcard entry to the Australian Open.
- 45 वर्षीय वीनस विलियम्स को ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वाइल्डकार्ड एंट्री दी गई है।
- She will become the oldest woman ever to compete at the Australian Open.
- वह ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने वाली अब तक की सबसे उम्रदराज़ महिला खिलाड़ी बनेंगी।
- The Australian Open is the season-opening Grand Slam tournament.
- ऑस्ट्रेलियन ओपन सीजन की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है।
- Venus will play in the main draw for the first time since 2021.
- वीनस 2021 के बाद पहली बार मेन ड्रॉ में खेलेंगी।
- She is a seven-time Grand Slam singles champion and one of the greatest players in tennis history.
- वह 7 बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन और टेनिस इतिहास की महान खिलाड़ियों में से एक हैं।
- Venus Williams expressed excitement about returning to Australia and competing again.
- वीनस विलियम्स ने ऑस्ट्रेलिया लौटकर फिर से प्रतिस्पर्धा करने को लेकर उत्साह व्यक्त किया है।





**Ques: India and Pakistan exchanged the list of Nuclear Installations and Facilities for which consecutive time?**

भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं की सूची कितनीवीं बार लगातार आदान-प्रदान की?

- A) 33rd time
- B) 34th time
- C) 35th time
- D) 36th time
- E) 37th time

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- India and Pakistan exchanged the list of Nuclear Installations and Facilities simultaneously through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad.
- भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में कूटनीतिक माध्यमों से एक साथ परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया।
- This marked the 35th consecutive exchange of such lists between the two countries.
- यह दोनों देशों के बीच इस प्रकार की सूची का 35वां लगातार आदान-प्रदान था।
- The agreement was signed on 31 December 1988 and came into force on 27 January 1991.
- यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित हुआ और 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ।
- The two countries also exchanged the list of prisoners under the Consular Access Agreement signed on 21 May 2008.
- दोनों देशों ने 21 मई 2008 को हस्ताक्षरित कांसुलर एक्सेस समझौते के तहत कैदियों की सूची का भी आदान-प्रदान किया।
- Pakistan handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians.
- पाकिस्तान ने 257 भारतीय कैदियों की सूची सौंपी, जिनमें 199 मछुआरे और 58 अन्य नागरिक शामिल हैं।
- As per the agreement, the exchange of prisoner lists is mandatory twice a year, in January and July.
- समझौते के अनुसार, कैदियों की सूची का आदान-प्रदान वर्ष में दो बार, जनवरी और जुलाई में अनिवार्य है।





**Ques: What is the main objective of the Lakhpati Didi Initiative under DAY–NRLM?**

DAY–NRLM के तहत लाखपति दीदी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Strengthening SHGs as institutions / SHG को संस्थागत रूप से मजबूत करना
- B) Providing subsidies to rural enterprises / ग्रामीण उद्यमों को सब्सिडी देना
- C) Enabling SHG women to earn ₹1 lakh or more annually on a sustainable basis / SHG महिलाओं को स्थायी रूप से ₹1 लाख या अधिक वार्षिक आय सक्षम बनाना
- D) Promoting urban self-employment / शहरी स्वरोजगार को बढ़ावा देना
- E) Creating rural industrial clusters / ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टर बनाना

**Answer:** Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- Lakhpati Didi Initiative is an outcome of the Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission, a centrally sponsored scheme of the Ministry of Rural Development.
- लाखपति दीदी पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू करता है।
- It focuses on individual SHG women and aims to enable them to earn at least ₹1,00,000 per year or ₹10,000 per month on a sustainable basis.
- इसका उद्देश्य SHG की व्यक्तिगत महिलाओं को स्थायी रूप से कम से कम ₹1,00,000 वार्षिक या ₹10,000 मासिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है।
- Income must be sustained for a minimum of four agricultural seasons or business cycles.
- यह आय न्यूनतम चार कृषि सत्रों या व्यवसाय चक्रों तक बनी रहनी चाहिए।
- There is no separate budget; all activities are funded under DAY–NRLM through training, capacity building, financial assistance and bank linkage.
- इसके लिए अलग बजट नहीं है और सभी गतिविधियाँ DAY–NRLM के तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, वित्तीय सहायता और बैंक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित होती हैं।





**Ques: Under which programme did President Droupadi Murmu launch the #SkillTheNation Challenge to promote AI education in India?**

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में एआई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए #SkillTheNation Challenge किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया?

- A) Digital India Mission / डिजिटल इंडिया मिशन
- B) Skill India Mission – SOAR Programme / स्किल इंडिया मिशन – SOAR कार्यक्रम
- C) National AI Strategy / राष्ट्रीय एआई रणनीति
- D) PM Kaushal Vikas Yojana / प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- E) Samagra Shiksha Abhiyan / समग्र शिक्षा अभियान

**Answer:** Option B

**Explanation | व्याख्या:**

- President of India Droupadi Murmu launched multiple initiatives under the Skilling for AI Readiness (SOAR) programme, which is a key component of the Skill India Mission.
- भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्किलिंग फॉर एआई रेडिनेस (SOAR) कार्यक्रम के तहत कई पहलें शुरू कीं, जो स्किल इंडिया मिशन का हिस्सा है।
- She launched the #SkillTheNation Challenge and virtually inaugurated the IGNOU centre at Rairangpur, Odisha, at an event held at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi.
- उन्होंने #SkillTheNation Challenge की शुरुआत की और ओडिशा के रायरंगपुर में इग्नू केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया।
- The IGNOU centre aims to expand higher education and skill development in tribal-dominated regions of northern Odisha.
- यह इग्नू केंद्र उत्तरी ओडिशा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देगा।
- Under SOAR, AI learning is integrated into school education and teacher training for students of classes 6 to 12 and educators nationwide.
- SOAR के तहत कक्षा 6 से 12 के छात्रों और शिक्षकों के लिए एआई शिक्षा को स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण से जोड़ा गया है।
- Students complete three 15-hour modules, while teachers undergo a 45-hour module covering AI, machine learning, data literacy, and ethical use of technology.
- छात्र तीन 15-घंटे के मॉड्यूल करते हैं, जबकि शिक्षक 45-घंटे का मॉड्यूल पूरा करते हैं, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साक्षरता और नैतिक तकनीक उपयोग शामिल है।





**Ques: MOI-1 mini-satellite, developed by Hyderabad start-ups, is being launched as a co-passenger payload on which ISRO mission?**

हैदराबाद के स्टार्ट-अप्स द्वारा विकसित MOI-1 मिनी-सैटेलाइट को ISRO के किस मिशन में सह-यात्री पेलोड के रूप में लॉन्च किया जा रहा है?

- A) PSLV-C54
- B) Gaganyaan-G1
- C) PSLV-C62
- D) SSLV-D3
- E) LVM3-M4

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Two Hyderabad-based space-tech start-ups, TakeMe2Space and EON Space Labs, have developed and integrated a 14-kg Earth observation mini-satellite named MOI-1.
- हैदराबाद स्थित स्पेस-टेक स्टार्ट-अप्स TakeMe2Space और EON Space Labs ने MOI-1 नामक 14 किलोग्राम का अर्थ ऑब्ज़र्वेशन मिनी-सैटेलाइट विकसित और एकीकृत किया है।
- The satellite has been shipped to Sriharikota for launch as a co-passenger payload on ISRO's PSLV-C62 mission.
- यह उपग्रह ISRO के PSLV-C62 मिशन में सह-यात्री पेलोड के रूप में लॉन्च के लिए श्रीहरिकोटा भेजा गया है।
- MOI-1 will operate in Low Earth Orbit at an altitude of about 500 km and has an expected lifespan of 3–5 years.
- MOI-1 लगभग 500 किमी ऊँचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में कार्य करेगा और इसकी अनुमानित आयु 3–5 वर्ष है।
- Built in just six months, the satellite weighs only 14 kg and is 40–70% cheaper than comparable global satellites.
- केवल 6 महीनों में तैयार किया गया यह उपग्रह 14 किलोग्राम का है और समान वैश्विक उपग्रहों की तुलना में 40–70% सस्ता है।
- It carries a multispectral camera with 9 colour bands, 9.2-metre spatial resolution, and an 18.7-km swath.
- इसमें 9 रंग बैंड वाला मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा, 9.2 मीटर रिज़ॉल्यूशन और 18.7 किमी स्वाथ मौजूद है।
- MOI-1 supports in-orbit computing and AI-based data processing using an onboard NVIDIA GPU, reducing raw data transmission costs.
- MOI-1 इन-ऑर्बिट कंप्यूटिंग और NVIDIA GPU के माध्यम से AI-आधारित डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन लागत घटती है।





**Ques: Defence Laboratory Jodhpur (DLJ) of DRDO developed which portable water purification system?**

डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर (DLJ) ने कौन सा पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित किया है?

- A) SeaWater Desalination System (SWaDeS) / सीवॉटर डीसैलेनेशन सिस्टम (SWaDeS)
- B) AquaMarine Purifier / एक्वामरीन प्यूरिफायर
- C) Portable Reverse Osmosis Unit / पोर्टेबल रिवर्स ऑस्मोसिस यूनिट
- D) Marine Water Filtration Device / मरीन वॉटर फिल्ट्रेशन डिवाइस
- E) Saline Water Conversion Kit / खारे पानी रूपांतरण किट

**Answer:** Option A

**Explanation | व्याख्या:**

- Defence Laboratory Jodhpur (DLJ) under DRDO developed a portable water purification system called SeaWater Desalination System (SWaDeS), available in manual-operated and engine-driven variants.
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के तहत डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर (DLJ) ने सीवॉटर डीसैलेनेशन सिस्टम (SWaDeS) नामक पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है, जो मैनुअल और इंजन-चालित दोनों प्रकार में उपलब्ध है।
- The engine-operated variant can desalinate seawater with TDS up to ~35,000 mg/L to below 500 mg/L for 20–25 soldiers, while the manual unit supports 10–12 personnel.
- इंजन-चालित संस्करण 20–25 सैनिकों के लिए लगभग 35,000 मिलीग्राम प्रति लीटर (mg/L) तक के TDS वाले समुद्री पानी को 500 mg/L से नीचे शुद्ध कर सकता है, जबकि मैनुअल यूनिट 10–12 लोगों के लिए पोर्टेबल है।
- Engine-operated systems can be set up within 2–3 minutes, and manual units are suitable for remote or power-scarce areas.
- इंजन-चालित प्रणाली 2–3 मिनट में स्थापित की जा सकती है, और मैनुअल यूनिट दूरदराज या बिजली-संकट वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त है।
- Applications include naval operations, coastal installations, inland saline lakes like Pangong Tso, and long-range patrols.
- इसका उपयोग नौसेना अभियानों, तटीय प्रतिष्ठानों, अंतर्देशीय खारे झीलों जैसे पांगोंग त्सो और लंबी दूरी की गश्ती में किया जा सकता है।





**Ques: Who became the youngest Indian and the second-youngest woman in the world to ski to the South Pole?**

दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला कौन बनीं?

- A) Kaamya Karthikeyan / काम्या कार्तिकेयन
- B) Malavath Purna / मालावथ पूर्णा
- C) Arunima Sinha / अरुणिमा सिन्हा
- D) Anshu Jamsenpa / अंशु जम्सेनपा
- E) Premlata Agarwal / प्रेमलता अग्रवाल

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- Eighteen-year-old Kaamya Karthikeyan, a skier from Mumbai, became the youngest Indian and the second-youngest woman globally to ski to the South Pole at an elevation of 2,385 metres.
- मुंबई की 18 वर्षीय स्कीयर काम्या कार्तिकेयन 2,385 मीटर ऊँचाई पर स्थित दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनीं।
- She started from 89° South and covered 60 nautical miles (115 km) in 11 days in temperatures of  $-30^{\circ}\text{C}$  across Antarctic ice.
- उन्होंने 89° दक्षिण से यात्रा शुरू कर  $-30^{\circ}\text{C}$  तापमान में 11 दिनों में 60 नौटिकल मील (115 किमी) की दूरी तय की।
- In 2019, she became the youngest girl to scale Mount Aconcagua (6,962 m), the highest peak in South America.
- 2019 में वह माउंट एकोकागुआ (6,962 मीटर), दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी, फतह करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनीं।
- In 2023, she became the youngest Indian to summit Mount Everest from the Nepal side.
- 2023 में वह नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनीं।
- In 2024–25, she completed the Seven Summits challenge, finishing with Mount Vinson in Antarctica.
- 2024–25 में उन्होंने अंटार्कटिका के माउंट विन्सन के साथ सेवन समिट्स चुनौती पूरी की।





**Ques: What is the Minimum Export Price (MEP) on natural honey extended by the Government till March 2026?**

सरकार द्वारा मार्च 2026 तक बढ़ाया गया प्राकृतिक शहद का न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) कितना है?

- A) \$2,000 per tonne
- B) \$1,800 per tonne
- C) \$1,600 per tonne
- D) \$1,400 per tonne
- E) \$1,200 per tonne

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Government of India has extended the Minimum Export Price (MEP) of \$1,400 per tonne on natural honey till March 31, 2026, as notified by the DGFT.
- भारत सरकार ने DGFT की अधिसूचना के अनुसार प्राकृतिक शहद पर \$1,400 प्रति टन का MEP 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया है।
- Earlier, the MEP was reduced from \$2,000 to \$1,400 per tonne in August to boost India's honey export competitiveness.
- इससे पहले अगस्त में भारत के शहद निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए MEP को \$2,000 से घटाकर \$1,400 प्रति टन किया गया था।
- Honey exports between April–October stood at 60,002 tonnes valued at \$117.97 million, with FY 2024–25 exports crossing 1 lakh tonnes worth \$206.47 million.
- अप्रैल–अक्टूबर के बीच शहद निर्यात 60,002 टन रहा, जिसका मूल्य \$117.97 मिलियन था। वित्त वर्ष 2024–25 में शहद निर्यात 1 लाख टन से अधिक रहा, जिसका मूल्य \$206.47 मिलियन था।
- Major export markets include the US, UAE, Saudi Arabia, and Qatar. India exports varieties like mustard, eucalyptus, litchi, and sunflower honey.
- प्रमुख निर्यात बाजारों में अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और कतर शामिल हैं। भारत सरसों, नीलगिरी, लीची और सूरजमुखी शहद जैसी किस्मों का निर्यात करता है।
- Uttar Pradesh is the largest honey-producing state (17%), followed by West Bengal (16%) and Punjab (14%).
- उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य है (17%), इसके बाद पश्चिम बंगाल (16%) और पंजाब (14%) हैं।





**Ques: India's traditional medical systems (AYUSH) were formally recognised in which international trade agreements?**

भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों (AYUSH) को किन अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता दी गई है?

- A) India–UAE CEPA and India–UK FTA / भारत–यूएई CEPA और भारत–यूके FTA
- B) India–Japan CEPA and India–Australia ECTA / भारत–जापान CEPA और भारत–ऑस्ट्रेलिया ECTA
- C) India–Oman CEPA and India–New Zealand FTA / भारत–ओमान CEPA और भारत–न्यूज़ीलैंड FTA
- D) India–ASEAN FTA and India–Sri Lanka FTA / भारत–आसियान FTA और भारत–श्रीलंका FTA
- E) India–EU FTA and India–Canada CEPA / भारत–ईयू FTA और भारत–कनाडा CEPA

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Ministry of Commerce & Industry announced that India's traditional medical systems under AYUSH have been formally recognised in bilateral trade agreements.
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत की AYUSH के अंतर्गत पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में औपचारिक मान्यता दी गई है।
- These include the India–Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) and the India–New Zealand Free Trade Agreement (FTA).
- इनमें भारत–ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) और भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) शामिल हैं।
- The announcement was made during the 4th establishment anniversary celebrations of AYUSH Export Promotion Council (AYUSHEXCIL) in New Delhi.
- यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित AYUSH निर्यात संवर्धन परिषद (AYUSHEXCIL) के चौथे स्थापना दिवस समारोह के दौरान की गई।
- AYUSHEXCIL was registered on 4 January 2022 as a Section 8 company with the Registrar of Companies, Delhi.
- AYUSHEXCIL का पंजीकरण 4 जनवरी 2022 को दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में किया गया था।





## Ques: Why did India and Bangladesh begin joint water measurement on the Ganga-Padma rivers?

भारत और बांग्लादेश ने गंगा-पद्मा नदियों पर संयुक्त जल मापन क्यों शुरू किया?

- A) Due to floods in Bangladesh / बांग्लादेश में बाढ़ के कारण
- B) To start a new river treaty / नई नदी संधि शुरू करने के लिए
- C) As the Ganges Water Sharing Treaty entered its final year / क्योंकि गंगा जल बंटवारा संधि अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुकी है
- D) For hydropower generation / विद्युत उत्पादन के लिए
- E) To resolve border disputes / सीमा विवाद हल करने के लिए

**Answer:** Option C

### Explanation | व्याख्या:

- India and Bangladesh initiated joint water measurement on the Ganga and Padma rivers as the 30-year Ganges Water Sharing Treaty entered its final year.
- भारत और बांग्लादेश ने गंगा और पद्मा नदियों पर संयुक्त जल मापन शुरू किया, क्योंकि 30 वर्षीय गंगा जल बंटवारा संधि अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुकी है।
- The measurements are being conducted 3,500 feet upstream of the Hardinge Bridge on the Padma River in Bangladesh and simultaneously at the Farakka point on the Ganga River in India.
- जल मापन बांग्लादेश में पद्मा नदी पर हार्डिंग ब्रिज से 3,500 फीट ऊपर और भारत में गंगा नदी पर फरक्का बिंदु पर समानांतर रूप से किया जा रहा है।
- The joint exercise aims to ensure accurate data sharing and transparency between the two countries.
- संयुक्त मापन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सटीक डेटा साझा करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
- The Ganges Water Sharing Treaty governs the distribution of dry-season flows of the Ganga between India and Bangladesh.
- गंगा जल बंटवारा संधि भारत और बांग्लादेश के बीच शुष्क मौसम में गंगा जल के वितरण को नियंत्रित करती है।





**Ques: "Azadi: Freedom. Fascism. Fiction" is written by which author?**

“आज़ादी: फ़्रीडम • फ़ासिज़्म • फ़िक्शन” पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है?

- A) Aravind Adiga / अरविंद अडिगा
- B) Amitav Ghosh / अमिताव घोष
- C) Arundhati Roy / अरुंधति रॉय
- D) Jhumpa Lahiri / झुम्पा लाहिरी
- E) Kiran Desai / किरण देसाई

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- “Azadi: Freedom. Fascism. Fiction” is a non-fiction book written by renowned Indian author Arundhati Roy.
- “आज़ादी: फ़्रीडम • फ़ासिज़्म • फ़िक्शन” प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय द्वारा लिखित एक नॉन-फिक्शन पुस्तक है।
- The book is a collection of essays written between 2018 and 2020.
- यह पुस्तक 2018 से 2020 के बीच लिखे गए निबंधों (Essays) का संग्रह है।
- It critically examines themes such as freedom, democracy, nationalism, fascism, and dissent in contemporary India.
- यह समकालीन भारत में स्वतंत्रता, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, फासीवाद और असहमति जैसे विषयों की आलोचनात्मक समीक्षा करती है।
- The title ‘Azadi’ symbolizes the idea of freedom, resistance, and civil liberties.
- ‘आज़ादी’ शीर्षक स्वतंत्रता, प्रतिरोध और नागरिक अधिकारों के विचार का प्रतीक है।
- The book reflects Arundhati Roy’s strong views on political power, state policies, minorities, and civil freedoms.
- यह पुस्तक राजनीतिक सत्ता, सरकारी नीतियों, अल्पसंख्यकों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर अरुंधति रॉय के सशक्त विचार प्रस्तुत करती है।
- The updated edition of the book is published by Penguin Random House India.
- पुस्तक का अपडेटेड संस्करण पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है।





**Ques: Why did the Government of India impose a safeguard duty on non-alloy and alloy steel flat products?**

भारत सरकार ने नॉन-अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट उत्पादों पर सेफगार्ड ड्यूटी क्यों लगाई?

- A) To increase export competitiveness / निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए
- B) To control domestic steel prices / घरेलू स्टील कीमतों को नियंत्रित करने के लिए
- C) To protect domestic industry from sudden import surge / घरेलू उद्योग को अचानक आयात वृद्धि से बचाने के लिए
- D) To comply with WTO penalty norms / WTO दंड मानदंडों का पालन करने के लिए
- E) To promote foreign steel imports / विदेशी स्टील आयात को बढ़ावा देने के लिए

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Government of India imposed a final safeguard duty on imports of non-alloy and alloy steel flat products following a DGTR investigation confirming a sudden surge in imports.
- DGTR जांच में अचानक आयात वृद्धि की पुष्टि के बाद भारत सरकार ने नॉन-अलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट उत्पादों के आयात पर अंतिम सेफगार्ड ड्यूटी लगाई।
- The provisional safeguard duty has been converted into a definitive measure for three years with immediate effect.
- अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी को तुरंत प्रभाव से तीन वर्षों के लिए अंतिम ड्यूटी में बदला गया है।
- The duty rates are 12% from April 21, 2025 to April 20, 2026, 11.5% from April 21, 2026 to April 20, 2027, and 11% from April 21, 2027 to April 20, 2028.
- ड्यूटी दरें 21 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2026 तक 12%, 21 अप्रैल 2026 से 20 अप्रैल 2027 तक 11.5% और 21 अप्रैल 2027 से 20 अप्रैल 2028 तक 11% निर्धारित की गई हैं।





**Ques: Who has taken charge as the Vice Chief of the Air Staff of India?**

भारत के वायुसेना उपप्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है?

- A) Air Marshal Vivek Ram Chaudhari / एयर मार्शल विवेक राम चौधरी
- B) Air Marshal Narmadeshwar Tiwari / एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी
- C) Air Marshal Nagesh Kapoor / एयर मार्शल नागेश कपूर
- D) Air Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria / एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया
- E) Air Marshal Sandeep Singh / एयर मार्शल संदीप सिंह

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Air Marshal Nagesh Kapoor has assumed charge as the Vice Chief of the Air Staff (VCAS) of the Indian Air Force.
- एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उपप्रमुख (VCAS) के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- He succeeded Air Marshal Narmadeshwar Tiwari, who superannuated after 40 years of service.
- उन्होंने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया, जो 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए।
- Air Marshal Kapoor is an alumnus of NDA, DSSC, and NDC, and is a skilled fighter pilot with over 3,400 flying hours on MiG-21 and MiG-29 aircraft.
- एयर मार्शल कपूर एनडीए, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और मिग-21 व मिग-29 विमानों पर 3,400 से अधिक उड़ान घंटे का अनुभव रखने वाले कुशल लड़ाकू पायलट हैं।
- He has held key command, operational, instructional, and staff appointments, including AOC-in-C of Training Command and South Western Air Command, and has received multiple gallantry and distinguished service awards.
- उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमांड, ऑपरेशनल, प्रशिक्षण और स्टाफ पदों पर कार्य किया है, जिनमें ट्रेनिंग कमांड और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एओसी-इन-सी पद शामिल हैं, और उन्हें कई वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्राप्त हैं।





**Ques: The Employees' State Insurance Corporation (ESIC) extended SPREE 2025 till which date, allowing voluntary registration without past liabilities?**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने SPREE 2025 को बिना पिछली देनदारियों के स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए किस तिथि तक बढ़ाया है?

- A) 31 December 2025
- B) 15 January 2026
- C) 31 January 2026
- D) 28 February 2026
- E) 31 March 2026

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Employees' State Insurance Corporation (ESIC) announced a one-month extension of SPREE 2025, allowing employers and employees to register voluntarily without past liabilities until 31 January 2026.
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने SPREE 2025 को एक महीने के लिए बढ़ाते हुए 31 जनवरी 2026 तक बिना पिछली देनदारियों के स्वैच्छिक पंजीकरण की अनुमति दी।
- SPREE 2025 is implemented under the Employees' State Insurance Act, 1948 and was originally valid from 1 July 2025 to 31 December 2025.
- SPREE 2025 को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत लागू किया गया था और यह पहले 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक मान्य था।
- The scheme aims to expand social security coverage by promoting simplified and hassle-free registration of unregistered establishments and employees.
- इस योजना का उद्देश्य अपंजीकृत प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के लिए सरल और सुगम पंजीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है।
- It covers factories and establishments with 10 or more employees in ESI-notified areas, including shops, hotels, transport services, medical and educational institutions, municipal bodies, and workers earning up to ₹21,000 per month (₹25,000 for persons with disabilities).
- यह योजना ESI अधिसूचित क्षेत्रों में 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होती है, जिसमें दुकानें, होटल, परिवहन सेवाएँ, चिकित्सा व शैक्षणिक संस्थान, नगर निकाय तथा ₹21,000 (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ₹25,000) तक वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल हैं।



**Ques: Which country became the first in the world to officially end physical letter delivery?**

भौतिक पत्र वितरण आधिकारिक रूप से समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना?

- A) Sweden / स्वीडन
- B) Norway / नॉर्वे
- C) Denmark / डेनमार्क
- D) Finland / फिनलैंड
- E) Netherlands / नीदरलैंड

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Denmark's state-run postal service PostNord delivered its last physical letter, ending over 400 years of traditional mail delivery.
- डेनमार्क की सरकारी डाक सेवा PostNord ने अपना अंतिम भौतिक पत्र वितरित किया, जिससे 400 वर्ष पुरानी डाक परंपरा समाप्त हो गई।
- Denmark became the first country in the world to officially stop physical letter delivery in the digital age.
- डिजिटल युग में भौतिक पत्र वितरण समाप्त करने वाला डेनमार्क दुनिया का पहला देश बन गया।
- The decision reflects a sharp decline in letter usage due to digital communication, with PostNord delivering over 90% fewer letters in 2024 than in 2000.
- यह निर्णय डिजिटल संचार के कारण पत्रों के उपयोग में तेज गिरावट को दर्शाता है; 2024 में PostNord ने 2000 की तुलना में 90% से अधिक कम पत्र वितरित किए।
- Parcel delivery services will continue, driven by growth in e-commerce, and Denmark remains among the most digitally advanced countries with most government services online.
- ई-कॉमर्स की वृद्धि के कारण पार्सल डिलीवरी सेवाएं जारी रहेंगी, और डेनमार्क दुनिया के सबसे डिजिटल रूप से उन्नत देशों में शामिल है, जहां अधिकांश सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हैं।





**Ques: PM-KUSUM 2.0, which the Union Government plans to roll out ahead of Union Budget 2026–27, is primarily aimed at what objective?**

केंद्र सरकार द्वारा बजट 2026–27 से पहले शुरू किए जाने वाले PM-KUSUM 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Large thermal power plants / बड़े ताप विद्युत संयंत्र
- B) Nuclear energy in rural areas / ग्रामीण क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा
- C) Decentralised solar energy in agriculture / कृषि क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा
- D) Wind energy in coastal states / तटीय राज्यों में पवन ऊर्जा
- E) Hydropower irrigation projects / जलविद्युत सिंचाई परियोजनाएं

**Answer:** Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- Ahead of the Union Budget 2026–27, the Union Government is preparing to roll out PM-KUSUM 2.0, the next phase of the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM).
- केंद्रीय बजट 2026–27 से पहले केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के अगले चरण PM-KUSUM 2.0 को शुरू करने की तैयारी कर रही है।
- PM-KUSUM 2.0 reflects a renewed push towards decentralised solar energy solutions in the agriculture sector.
- PM-KUSUM 2.0 का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा समाधानों को और मजबूत करना है।
- The original PM-KUSUM scheme was launched in March 2019.
- मूल PM-KUSUM योजना मार्च 2019 में शुरू की गई थी।
- The current phase of PM-KUSUM is valid till March 2026 with a total outlay of ₹34,422 crore.
- PM-KUSUM का मौजूदा चरण मार्च 2026 तक लागू है, जिसका कुल परिव्यय ₹34,422 करोड़ है।
- The scheme aims to add around 34,800 MW of solar capacity across the country.
- इस योजना के तहत देश में लगभग 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है।
- Solar capacity addition will be achieved through decentralised grid-connected solar power plants, standalone solar pumps, and solarisation of existing grid-connected agricultural pumps.
- सौर क्षमता में वृद्धि विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों, स्टैंडअलोन सोलर पंपों और ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण के माध्यम से की जाएगी।





**Ques: Which state hosted the Regional Artificial Intelligence Impact Conference held in December 2025?**

दिसंबर 2025 में आयोजित क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस राज्य ने की?

- A) Odisha / ओडिशा
- B) Telangana / तेलंगाना
- C) Maharashtra / महाराष्ट्र
- D) Karnataka / कर्नाटक
- E) Gujarat / गुजरात

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- Odisha hosted the Regional Artificial Intelligence Impact Conference on 19–20 December 2025.
- 19–20 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी ओडिशा ने की।
- The conference focused on AI in governance, AI-enabled public service delivery, and responsible, scalable and inclusive AI adoption.
- सम्मेलन का फोकस शासन में AI, AI-सक्षम सार्वजनिक सेवा वितरण और जिम्मेदार, विस्तारयोग्य व समावेशी AI अपनाने पर रहा।
- The event aligned with the Odisha AI Policy 2025 and supporting policies in FinTech, Global Capability Centres and Advanced Electronics.
- यह आयोजन ओडिशा AI नीति 2025 तथा फिनटेक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी नीतियों के अनुरूप था।
- The guiding principle of the conference was the Three Ps framework: Planet, People and Progress.
- सम्मेलन का मार्गदर्शक सिद्धांत श्री पी फ्रेमवर्क रहा: प्लैनेट, पीपल और प्रोग्रेस।





**LQues: Which Indian city, known as the “Diamond City,” is set to become the country’s first slum-free city?**

‘डायमंड सिटी’ के नाम से प्रसिद्ध कौन-सा भारतीय शहर देश का पहला स्लम-फ्री शहर बनने जा रहा है?

- A) Ahmedabad / अहमदाबाद
- B) Mumbai / मुंबई
- C) Surat / सूरत
- D) Jaipur / जयपुर
- E) Indore / इंदौर

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Surat, Gujarat’s second-largest city, is set to become India’s first slum-free city.
- गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर सूरत, भारत का पहला स्लम-फ्री शहर बनने जा रहा है।
- Surat is known as the “Diamond City” as it processes nearly 90% of the world’s diamonds.
- सूरत को “डायमंड सिटी” कहा जाता है क्योंकि यहां दुनिया के लगभग 90% हीरों की कटिंग-पॉलिशिंग होती है।
- It is also called the “Silk City” due to its large textile industry.
- विशाल वस्त्र उद्योग के कारण इसे “सिल्क सिटी” भी कहा जाता है।
- Surat is also known as “Suryapur” and “Green City” for its cleanliness and urban management.
- स्वच्छता और शहरी प्रबंधन के कारण सूरत को “सूर्यपुर” और “ग्रीन सिटी” भी कहा जाता है।
- The city is located on the left bank of the Tapi (Tapti) River.
- यह शहर ताप्ती (तापी) नदी के बाएं तट पर स्थित है।
- Historically, Surat was a major port and trading centre of western India.
- ऐतिहासिक रूप से सूरत पश्चिमी भारत का एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक नगर रहा है।





**Ques: What is the main focus of the NIRYAT PROTSAHAN sub-scheme under the Export Promotion Mission?**

निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत NIRYAT PROTSAHAN उप-योजना का मुख्य फोकस क्या है?

- A) Export subsidies for large exporters / बड़े निर्यातकों को निर्यात सब्सिडी
- B) Market branding and trade intelligence / बाजार ब्रांडिंग और व्यापार खुफिया
- C) Access to affordable trade finance for MSMEs / MSME के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच
- D) Logistics infrastructure development / लॉजिस्टिक्स अवसंरचना विकास
- E) Regulation of export pricing / निर्यात मूल्य निर्धारण का विनियमन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Under the Export Promotion Mission, two interventions have been launched under the NIRYAT PROTSAHAN sub-scheme to strengthen MSME exports.
- निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत MSME निर्यात को मजबूत करने के लिए NIRYAT PROTSAHAN में दो हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं।
- The government announced a ₹7,295-crore export support package, comprising a ₹5,181-crore interest subvention scheme and ₹2,114-crore collateral support, aimed at easing credit constraints for exporters, especially MSMEs, under the Export Promotion Mission framework.
- सरकार ने ₹7,295 करोड़ का निर्यात समर्थन पैकेज घोषित किया है, जिसमें ₹5,181 करोड़ की ब्याज सहायता योजना और ₹2,114 करोड़ का कोलेटरल समर्थन शामिल है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए ऋण उपलब्धता को आसान बनाना है।
- The first intervention provides interest subvention on pre- and post-shipment rupee export credit to reduce borrowing costs and ease working-capital constraints.
- पहला हस्तक्षेप प्री और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करता है।
- A base interest subvention of 2.75% is applicable, with additional incentives for exports to notified emerging or under-represented markets.
- 2.75% की आधार ब्याज सहायता दी जाएगी तथा उभरते बाजारों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है।
- Benefits apply only to exports under a notified positive list covering about 75% of tariff lines, with an exporter-wise cap of ₹50 lakh per IEC in FY 2025-26.



**Ques: The Ministry of Textiles extended the deadline for submission of fresh applications under which scheme till March 31, 2026?**

वस्त्र मंत्रालय ने किस योजना के तहत नए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई है?

- A) Technology Upgradation Fund Scheme / प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना
- B) Production Linked Incentive Scheme for Textiles / वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना
- C) National Technical Textiles Mission / राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन
- D) Integrated Textile Parks Scheme / एकीकृत वस्त्र पार्क योजना
- E) Amended Technology Upgradation Scheme / संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Ministry of Textiles extended the deadline for submission of fresh applications under the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles to March 31, 2026, from December 31, 2025.
- वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत नए आवेदनों की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है।
- As on September 9, 2025, 91 companies have been selected under the PLI scheme for textiles.
- 9 सितंबर 2025 तक वस्त्र PLI योजना के अंतर्गत 91 कंपनियों का चयन किया गया है।
- These companies account for investments of ₹7,731 crore, exports of ₹733 crore and turnover of ₹7,290 crore.
- इन कंपनियों द्वारा ₹7,731 करोड़ का निवेश, ₹733 करोड़ का निर्यात और ₹7,290 करोड़ का कारोबार दर्ज किया गया है।

**About PLI Scheme:**

- Launched : September 2021
- Tenure : 5 years from Financial Year 2021-22 (FY22) to FY26
- Outlay : Rs.10,683 crores
- Aim : To promote manufacturing, global competitiveness, and exports in selected segments of the textile industry





**Ques: What is the Aadhaar-like unique identification proposed by the Transport Ministry for Electric Vehicle (EV) batteries?**

परिवहन मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों के लिए प्रस्तावित आधार-जैसी यूनिक पहचान क्या है?

- A) EVIN / ईवीआईएन
- B) Battery UID / बैटरी यूआईडी
- C) BPAN / बीपीएएन
- D) Green Battery ID / ग्रीन बैटरी आईडी
- E) e-Battery Aadhaar / ई- बैटरी आधार

**Answer:** Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- The Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) has proposed assigning an Aadhaar-like unique identification number to EV batteries.
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने EV बैटरियों के लिए आधार-जैसी यूनिक पहचान संख्या देने का प्रस्ताव रखा है।
- As per draft guidelines, battery manufacturers or importers will assign a 21-character Battery Pack Aadhaar Number (BPAN) to each EV battery.
- ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, बैटरी निर्माता या आयातक प्रत्येक EV बैटरी को 21-अक्षरों वाला बैटरी पैक आधार नंबर (BPAN) देंगे।
- The objective is to ensure end-to-end traceability of EV batteries across their entire lifecycle—from manufacturing or import to end-of-life recycling.
- इसका उद्देश्य बैटरियों की निर्माण/आयात से लेकर जीवन के अंत में रीसाइक्लिंग तक पूरी ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना है।
- The framework will promote efficient recycling and environmentally sound disposal of used batteries.
- यह ढांचा प्रयुक्त बैटरियों के कुशल रीसाइक्लिंग और सुरक्षित निपटान को बढ़ावा देगा।
- The move aligns with India's goals of clean mobility and development of a circular economy.
- यह पहल स्वच्छ गतिशीलता और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।





**Ques: Which bank launched the Zero-Forex Diamond Reserve Credit Card offering zero foreign exchange markup for frequent international travellers?**

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए शून्य विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) मार्कअप वाला ज़ीरो-फॉरेक्स डायमंड रिज़र्व क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- D) IDFC FIRST Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
- E) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- IDFC FIRST Bank launched the Zero-Forex Diamond Reserve Credit Card as a premium offering for frequent international travellers.
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रीमियम ज़ीरो-फॉरेक्स डायमंड रिज़र्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
- The card provides zero foreign exchange (forex) markup along with travel and lifestyle rewards.
- यह कार्ड शून्य विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) मार्कअप के साथ यात्रा और लाइफस्टाइल रिवॉईस प्रदान करता है।
- The annual fee is ₹3,000 plus GST, which is waived from the second year on annual spends of ₹6 lakh.
- इसका वार्षिक शुल्क ₹3,000 प्लस जीएसटी है, जो ₹6 लाख के वार्षिक खर्च पर दूसरे वर्ष से माफ कर दिया जाता है।





**Ques: What time lag has SEBI proposed for sharing and using price data in investor education and awareness programmes?**

निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में मूल्य डेटा के साझा करने और उपयोग के लिए सेबी ने कितने समय के अंतराल (टाइम लैग) का प्रस्ताव किया है?

- A) 1 day
- B) 7 days
- C) 15 days
- D) 30 days
- E) 90 days

**Answer: Option D**

**Explanation | व्याख्या:**

- SEBI has proposed a uniform 30-day time lag for sharing and using price data in investor education and awareness programmes.
- सेबी ने निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में मूल्य डेटा के उपयोग के लिए 30 दिनों के समान समय अंतराल का प्रस्ताव किया है।
- The proposal aims to prevent misuse of sensitive market data while ensuring educational content remains relevant and timely for investors.
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य संवेदनशील बाजार डेटा के दुरुपयोग को रोकते हुए निवेशकों के लिए शैक्षिक सामग्री को प्रासंगिक बनाए रखना है।
- This move replaces the earlier system where exchanges shared data with a one-day lag while educators could use only data that was at least three months old.
- यह कदम पुराने तंत्र की जगह लेता है, जिसमें एक्सचेंज एक दिन की देरी से डेटा साझा करते थे जबकि शिक्षकों को कम से कम तीन महीने पुराने डेटा का उपयोग करना पड़ता था।





**Ques: With which institution did the Delhi Government sign an MoU to bring its finances under a complete banking, cash management, and debt management framework for the first time?**

दिल्ली सरकार ने पहली बार अपनी बैंकिंग, नकद प्रबंधन और ऋण प्रबंधन व्यवस्था को किस संस्था के अंतर्गत लाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए?

- A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) NITI Aayog / नीति आयोग
- E) Comptroller and Auditor General / नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Delhi Government signed a Memorandum of Understanding with the Reserve Bank of India to operate under RBI's complete banking, cash management, and debt management framework for the first time.
- दिल्ली सरकार ने पहली बार भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण बैंकिंग, नकद प्रबंधन और ऋण प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत कार्य करने के लिए RBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- This move aligns Delhi's financial governance with nationally accepted fiscal practices.
- यह कदम दिल्ली की वित्तीय व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत राजकोषीय प्रथाओं के अनुरूप बनाता है।
- The Reserve Bank of India traditionally acts as banker and debt manager for state governments.
- भारतीय रिज़र्व बैंक परंपरागत रूप से राज्य सरकारों के लिए बैंकर और ऋण प्रबंधक की भूमिका निभाता है।
- RBI manages state governments' borrowings, cash balances, and debt instruments under frameworks approved by the Centre.
- RBI केंद्र द्वारा स्वीकृत ढांचे के तहत राज्यों की उधारी, नकद शेष और ऋण साधनों का प्रबंधन करता है।





**Ques: Which bank will facilitate bilateral trade settlements between India and Israel in Indian rupees through a Special Rupee Vostro Account?**

भारत और इज़राइल के बीच भारतीय रुपये में द्विपक्षीय व्यापार निपटान को विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते के माध्यम से कौन सा बैंक सुगम बनाएगा?

- A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- India's largest lender, the State Bank of India, will facilitate bilateral trade settlements between India and Israel in Indian rupees.
- भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक, भारत और इज़राइल के बीच रुपये में द्विपक्षीय व्यापार निपटान को सुगम बनाएगा।
- The move is aligned with ongoing discussions between the two countries towards a comprehensive Free Trade Agreement.
- यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में चल रही चर्चाओं से जुड़ा है।
- Under the mechanism, Israeli exporters and importers will make and receive payments in rupees through a Special Rupee Vostro Account linked to trade invoices.
- इस व्यवस्था के तहत इज़राइली निर्यातक और आयातक व्यापार चालानों से जुड़े विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते के माध्यम से रुपये में भुगतान करेंगे।
- SBI's Tel Aviv branch has obtained all regulatory approvals to operationalise the arrangement and is promoting awareness among stakeholders.
- एसबीआई की तेल अवीव शाखा ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी नियामक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली हैं और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ा रही है।





**Ques: Which company became the first payments firm in India, the Middle East, APAC, and South Africa to receive the ISO/IEC 42001 certification for Artificial Intelligence Management Systems?**

भारत, मध्य पूर्व, एशिया-प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में ISO/IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन बनी?

- A) Paytm / पेटीएम
- B) Razorpay / रेज़रपे
- C) PhonePe / फोनपे
- D) NPCI / एनपीसीआई
- E) Financial Software and Systems (FSS) / फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स

**Answer: Option E**

Explanation | व्याख्या:

- Financial Software and Systems (FSS) became the first payments company across India, the Middle East, APAC, and South Africa to earn the ISO/IEC 42001 certification.
- फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स (FSS) भारत, मध्य पूर्व, एशिया-प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में ISO/IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी बनी।
- ISO/IEC 42001 is the world's first international standard for Artificial Intelligence Management Systems (AIMS).
- ISO/IEC 42001 कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रबंधन प्रणाली (AIMS) के लिए दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय मानक है।
- The certification recognises organisations that demonstrate responsible, ethical, and trustworthy use of artificial intelligence.
- यह प्रमाणन एआई के जिम्मेदार, नैतिक और विश्वसनीय उपयोग को प्रदर्शित करने वाले संगठनों को मान्यता देता है।





**Ques: By how much has India's solar module manufacturing capacity increased year-on-year in 2025, as stated by Union Minister Pralhad Joshi?**

केंद्रय मंत्री प्रल्हाद जोशी के अनुसार 2025 में भारत की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता में साल-दर-साल कितनी वृद्धि हुई है?

- A) 75% to 100 GW
- B) 100% to 120 GW
- C) 150% to 160 GW
- D) 128.6% to 144 GW
- E) 62 times to 200 GW

**Answer:** Option D

**Explanation | व्याख्या:**

- India's solar module manufacturing capacity increased by 128.6% year-on-year to 144 GW in 2025, according to Union Minister for New and Renewable Energy Pralhad Joshi.
- केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी के अनुसार 2025 में भारत की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 128.6% की वार्षिक वृद्धि के साथ 144 गीगावाट हो गई।
- India added 81 GW capacity in the previous year, rising from 63 GW to 144 GW.
- भारत ने पिछले वर्ष 63 गीगावाट से बढ़कर 144 गीगावाट तक 81 गीगावाट क्षमता जोड़ी।
- Since 2014, India's solar manufacturing capacity has increased more than 62 times from 2.3 GW.
- वर्ष 2014 से भारत की सोलर विनिर्माण क्षमता 2.3 गीगावाट से बढ़कर 62 गुना से अधिक हो चुकी है।

Genius





**Ques: What is SAMPANN, the system recently implemented for DoT pensioners, designed to provide online pension management and digital grievance redressal?**  
DoT के पेंशनभोगियों के लिए हाल ही में लागू किए गए ऑनलाइन पेंशन प्रबंधन और डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली SAMPANN क्या है?

- A) System for Automated Monitoring of Pension / पेंशन के स्वचालित निगरानी प्रणाली
- B) System for Accounting and Management of Pension / पेंशन लेखा और प्रबंधन प्रणाली
- C) Simplified Administrative Management of Pension / पेंशन का सरलीकृत प्रशासनिक प्रबंधन
- D) Secure Access for Pensioners' Digital Records / पेंशनभोगियों के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित पहुँच
- E) Standardized Application for Monthly Pension / मासिक पेंशन के लिए मानकीकृत आवेदन

**Answer:** Option B

**Explanation | व्याख्या:**

- SAMPANN (System for Accounting and Management of Pension) is an integrated online pension management system for DoT pensioners that processes, sanctions, and disburses pension directly to their bank accounts.
- SAMPANN (सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ़ पेंशन) DoT पेंशनभोगियों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पेंशन प्रबंधन प्रणाली है, जो पेंशन को सीधे उनके बैंक खातों में प्रोसेस, स्वीकृत और वितरित करती है।
- The system also provides online grievance redressal, digital profile management, and transaction records, improving transparency and efficiency for telecom retirees.
- यह प्रणाली ऑनलाइन शिकायत निवारण, डिजिटल प्रोफ़ाइल प्रबंधन और लेनदेन रिकॉर्ड भी प्रदान करती है, जिससे दूरसंचार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ती है।
- Key pension-related documents such as Gratuity Payment Orders, Pension Certificates/ePPOs, Pension Commutation Orders, and Form 16 are now accessible via DigiLocker, enabling secure digital storage and retrieval.
- मुख्य पेंशन संबंधी दस्तावेज़ जैसे ग्रेच्युटी भुगतान आदेश, पेंशन प्रमाणपत्र/ePPO, पेंशन कम्यूटेशन आदेश और फॉर्म 16 अब DigiLocker के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल भंडारण और पुनःप्राप्ति के लिए उपलब्ध हैं।
- SAMPANN stands for “सम्पन्न जीवन, निश्चित जीवन,” reflecting a vision of convenient and worry-free post-retirement life.
- SAMPANN का अर्थ है “सम्पन्न जीवन, निश्चित जीवन,” जो सेवानिवृत्ति के बाद सुविधाजनक और निश्चित जीवन के दृष्टिकोण को दर्शाता है।





**Ques: Under which mission were indigenously developed 3D-printed Automatic Weather Stations (AWS) created by Indian scientists led by IITM, Pune?**

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा आईआईटीएम, पुणे के नेतृत्व में स्वदेशी 3डी-प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) किस मिशन के तहत विकसित किए गए?

- A) Mission Mausam / मिशन मौसम
- B) National Monsoon Mission / राष्ट्रीय मानसून मिशन
- C) Digital India Mission / डिजिटल इंडिया मिशन
- D) National Climate Action Plan / राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना
- E) Atal Innovation Mission / अटल नवाचार मिशन

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- Indian scientists led by IITM, Pune, under the Ministry of Earth Sciences developed indigenously manufactured 3D-printed Automatic Weather Stations under Mission Mausam.
- भारतीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आईआईटीएम, पुणे के नेतृत्व में मिशन मौसम के तहत स्वदेशी 3डी-प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन विकसित किए।
- The first batch of these advanced AWS will be deployed in Delhi from February 2026.
- इन उन्नत AWS की पहली खेप फरवरी 2026 से दिल्ली में तैनात की जाएगी।
- After Delhi, the stations will be deployed in Mumbai, Kolkata, and Chennai over a period of six months.
- दिल्ली के बाद छह महीनों की अवधि में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इन स्टेशनों की तैनाती की जाएगी।
- A total of 50 Automatic Weather Stations (AWS) units have been produced initially, with 80 additional units planned for production.
- प्रारंभिक रूप से 50 AWS इकाइयाँ तैयार की गई हैं और 80 अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन की योजना है।

**About Mission Mausam:**

- Outlay : Rs. 2,000 crore for 2024–2026
- Aim : To upgrade meteorological infrastructure, fill observation gaps in urban and climate-sensitive regions, and enable accurate hyper-local weather forecasts across India
- Leadership : IMD and the National Centre for Medium-Range Weather Forecasting (NCMRWF)





**Ques: Who released the 10th edition of the Indian Pharmacopoeia (IP 2026), the official compendium of drug standards of India?**

भारत के औषधि मानकों की आधिकारिक संहिता इंडियन फार्माकोपिया (IP 2026) का 10वां संस्करण किसने जारी किया?

- A) Mansukh Mandaviya / मनसुख मांडविया
- B) Jagat Prakash Nadda / जगत प्रकाश नड्डा
- C) Dharmendra Pradhan / धर्मेन्द्र प्रधान
- D) Anupriya Patel / अनुप्रिया पटेल
- E) Jitendra Singh / जितेंद्र सिंह

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister Jagat Prakash Nadda released the 10th edition of the Indian Pharmacopoeia, which is the official compendium of drug standards in India.
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया का 10वां संस्करण जारी किया, जो भारत के औषधि मानकों की आधिकारिक संहिता है।
- IP 2026 added 121 new monographs, increasing the total to 3,340 and strengthening standards for anti-TB, anti-diabetic, anti-cancer drugs and micronutrient supplements.
- IP 2026 में 121 नए मोनोग्राफ जोड़े गए, जिससे कुल संख्या 3,340 हो गई और टीबी, मधुमेह, कैंसर दवाओं व सूक्ष्म पोषक तत्वों के मानक मजबूत हुए।
- Indian Pharmacopoeia is legally enforceable under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and is published by the Indian Pharmacopoeia Commission under MoHFW.
- इंडियन फार्माकोपिया औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है और इसे MoHFW के अंतर्गत IPC प्रकाशित करता है।
- IP 2026 aligns with international best practices, collaborates with US, European and Japanese Pharmacopoeias, and is recognised in 19 Global South countries.
- IP 2026 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है, अमेरिका, यूरोप और जापान की फार्माकोपिया के साथ सहयोग करता है और 19 ग्लोबल साउथ देशों में मान्यता प्राप्त है।
- Under the Pharmacovigilance Programme of India, India's ranking in WHO's pharmacovigilance database improved from 123rd to 8th by 2025.
- फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के तहत WHO डेटाबेस में भारत की रैंकिंग 123वें से सुधरकर 2025 में 8वें स्थान पर पहुंच गई।





**Ques: Who inaugurated India's first commercial-scale tropical RAS-based Rainbow Trout Aquaculture Farm and Research Institute in Telangana?**

तेलंगाना में भारत के पहले वाणिज्यिक स्तर के उष्णकटिबंधीय RAS-आधारित रेनबो ट्राउट एक्वाकल्चर फार्म एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया?

- A) Narendra Singh Tomar / नरेंद्र सिंह तोमर
- B) Giriraj Singh / गिरिराज सिंह
- C) Rajiv Ranjan Singh (Lalan Singh) / राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह)
- D) Pashupati Kumar Paras / पशुपति कुमार पारस
- E) Mansukh Mandaviya / मनसुख मांडविया

**Answer:** Option C

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister Rajiv Ranjan Singh (Lalan Singh) inaugurated the Smart Green Aquaculture Farm and India's first commercial-scale tropical RAS-based Rainbow Trout Aquaculture Farm and Research Institute in Kandukur Mandal, Ranga Reddy district, Telangana.
- केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के कंदुकुर मंडल में स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म और भारत के पहले वाणिज्यिक स्तर के उष्णकटिबंधीय RAS-आधारित रेनबो ट्राउट एक्वाकल्चर फार्म एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया।
- The facility enables high-value cold-water fish farming in tropical conditions using climate-controlled, water-efficient Recirculating Aquaculture System (RAS) technology.
- यह सुविधा जलवायु-नियंत्रित और जल-कुशल RAS तकनीक के माध्यम से उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में उच्च मूल्य वाली ठंडे पानी की मछलियों का पालन संभव बनाती है।
- The project demonstrated that species like Rainbow Trout can be farmed year-round in tropical climates, establishing technology rather than climate as the key determinant of aquaculture viability.
- इस परियोजना ने यह सिद्ध किया कि रेनबो ट्राउट जैसी प्रजातियों का उष्णकटिबंधीय जलवायु में वर्षभर पालन संभव है, जिससे यह स्थापित हुआ कि जलवायु नहीं बल्कि तकनीक एक्वाकल्चर की व्यवहार्यता का मुख्य निर्धारक है।
- RAS technology recycles 90–99% water, filters fish waste mechanically and biologically, precisely controls water quality, and requires very little fresh water.
- RAS तकनीक में 90–99% पानी का पुनर्चक्रण होता है, मछली अपशिष्ट का यांत्रिक एवं जैविक निस्पंदन किया जाता है, जल गुणवत्ता का सटीक नियंत्रण होता है और बहुत कम ताजे पानी की आवश्यकता होती है।





## About Telangana :

- Capital : Hyderabad
- CM : Anumula Revanth Reddy
- Governor : Jishnu Dev Varma



EXAM  
Genius





**Ques: Which country has India overtaken to become the world's largest rice producer, as announced during the release of 184 new crop varieties by ICAR?**

आईसीएआर द्वारा विकसित 184 नई फसल किस्मों के विमोचन के दौरान घोषित अनुसार, भारत ने विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ा?

- A) China / चीन
- B) Vietnam / वियतनाम
- C) Thailand / थाईलैंड
- D) Indonesia / इंडोनेशिया
- E) Bangladesh / बांग्लादेश

**Answer:** Option A

**Explanation | व्याख्या:**

- India has overtaken China to become the world's largest rice producer.
- भारत ने चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने की उपलब्धि हासिल की है।
- India's rice production reached 150.18 million tonnes, surpassing China's output of 145.28 million tonnes.
- भारत का चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो चीन के 145.28 मिलियन टन उत्पादन से अधिक है।
- Indian rice is now being supplied extensively to overseas markets, strengthening India's position in global agricultural trade.
- भारतीय चावल अब व्यापक रूप से विदेशी बाजारों में आपूर्ति किया जा रहा है, जिससे वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।
- The announcement was made during the release of 184 new crop varieties developed by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR).
- यह घोषणा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित 184 नई फसल किस्मों के विमोचन के दौरान की गई।





**Ques: Who released the Urdu book “Khutbat-e-Modi: Lal Qila Ki Faseel Se”, a compilation of Prime Minister Narendra Modi’s Independence Day speeches from 2014 to 2025?**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से 2025 तक के स्वतंत्रता दिवस भाषणों के संकलन “खुत्बात-ए-मोदी: लाल क़िला की फ़सील से” पुस्तक को किसने जारी किया?

- A) Dharmendra Pradhan / धर्मेंद्र प्रधान
- B) Amit Shah / अमित शाह
- C) Narendra Modi / नरेंद्र मोदी
- D) Jagat Prakash Nadda / जगत प्रकाश नड्डा
- E) Smriti Irani / स्मृति ईरानी

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister for Education Shri Dharmendra Pradhan released the book “Khutbat-e-Modi: Lal Qila Ki Faseel Se” in New Delhi.
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में “खुत्बात-ए-मोदी: लाल क़िला की फ़सील से” पुस्तक का विमोचन किया।
- The book compiles Independence Day addresses delivered by Prime Minister Narendra Modi from the Red Fort between 2014 and 2025.
- यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 से 2025 के बीच लाल क़िले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस भाषणों का संकलन है।
- Published in Urdu, the book has been brought out by the National Council for Promotion of Urdu Language (NCPUL) under the Ministry of Education.
- उर्दू भाषा में प्रकाशित यह पुस्तक शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (NCPUL) द्वारा प्रकाशित की गई है।





**Ques: Who launched the 'IITM Global Research Foundation' at IIT Madras to mark its ambition of becoming the world's first multinational university?**

आईआईटी मद्रास को विश्व का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में 'IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन' का शुभारंभ किसने किया?

- A) Narendra Modi / नरेंद्र मोदी
- B) Dharmendra Pradhan / धर्मेंद्र प्रधान
- C) Nirmala Sitharaman / निर्मला सीतारमण
- D) Rajnath Singh / राजनाथ सिंह
- E) Dr. S. Jaishankar / डॉ. एस. जयशंकर

**Answer: Option E**

**Explanation | व्याख्या:**

- Union Minister for External Affairs Dr. S. Jaishankar launched the IITM Global Research Foundation at the Indian Institute of Technology Madras.
- केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ किया।
- The initiative reflects IIT Madras' ambition to emerge as the world's first multinational university.
- यह पहल आईआईटी मद्रास की विश्व का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
- IITM Global is based on four pillars: technology transfer to global markets, joint international research projects, overseas business opportunities for IIT-M startups, and attracting foreign investment.
- IITM ग्लोबल चार स्तंभों पर आधारित है: वैश्विक बाजारों में तकनीक हस्तांतरण, संयुक्त अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजनाएँ, आईआईटी-एम स्टार्टअप्स के लिए विदेशी व्यावसायिक अवसर और विदेशी निवेश आकर्षित करना।
- IIT Madras signed multiple MoUs with global partners across the USA, UK, Germany, Dubai, Asia-Pacific region, and under the India-for-Global initiative.
- आईआईटी मद्रास ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, दुबई, एशिया-प्रशांत क्षेत्र और 'इंडिया-फॉर-ग्लोबल' पहल के तहत कई वैश्विक भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- In the initial phase, IITM Global will be set up in the USA, UAE, Malaysia, and Germany.
- प्रारंभिक चरण में IITM ग्लोबल की स्थापना अमेरिका, यूएई, मलेशिया और जर्मनी में की जाएगी।





**Ques: Which leaders are expected to attend India's Republic Day celebrations on 26 January 2026 as chief guests, highlighting strong diplomatic ties with the European Union?**

26 जनवरी 2026 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंधों को दर्शाते हुए मुख्य अतिथि के रूप में किन नेताओं के शामिल होने की संभावना है?

- A) Emmanuel Macron and Olaf Scholz / इमैनुएल मैक्रों और ओलाफ शोलज़
- B) Ursula von der Leyen and António Costa / उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंतोनियो कोस्टा
- C) Charles Michel and Josep Borrell / चार्ल्स मिशेल और जोसेप बोरेल
- D) Roberta Metsola and Kaja Kallas / रोबर्टा मेटसोला और काजा कालास
- E) Ursula von der Leyen and Roberta Metsola / उर्सुला वॉन डेर लेयेन और रोबर्टा मेटसोला

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- India's Republic Day celebrations on 26 January 2026 are expected to have strong diplomatic significance, with European Union leaders attending as chief guests.
- 26 जनवरी 2026 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का कूटनीतिक महत्व विशेष होने की संभावना है, जिसमें यूरोपीय संघ के नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं।
- The expected chief guests are Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and António Costa, President of the European Council.
- संभावित मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा हैं।
- The proposed India–EU Free Trade Agreement is strategically important for both partners.
- प्रस्तावित भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों भागीदारों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- Indonesia's President H.E. Prabowo Subianto was the Chief Guest at India's 76th Republic Day in January 2025.
- जनवरी 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति एच.ई. प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे।





**Ques: What are the sacred ancient Buddha-linked gems that were unveiled in India for the first time since their colonial-era removal and displayed at an exhibition opened by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi?**

औपनिवेशिक काल में हटाए जाने के बाद भारत में पहली बार प्रदर्शित किए गए और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित प्रदर्शनी में दिखाए गए बुद्ध से जुड़े पवित्र प्राचीन रत्न कौन से हैं?

- A) Piprahwa Relics / पिपरहवा अवशेष
- B) Bodh Gaya Relics / बोधगया अवशेष
- C) Sanchi Relics / सांची अवशेष
- D) Nalanda Relics / नालंदा अवशेष
- E) Kushinagar Relics / कुशीनगर अवशेष

**Answer: Option A**

**Explanation | व्याख्या:**

- Sacred Piprahwa Relics titled “The Light & the Lotus: Relics of the Awakened One” were unveiled in India for the first time since their colonial-era removal.
- “द लाइट एंड द लोटस: रिलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन” नामक पवित्र पिपरहवा अवशेष औपनिवेशिक काल के बाद पहली बार भारत में प्रदर्शित किए गए।
- The Piprahwa gems consist of over 300 precious stones and ornaments believed to have been buried with the relics of the Buddha at a stupa site in present-day Uttar Pradesh.
- पिपरहवा रत्नों में 300 से अधिक बहुमूल्य पत्थर और आभूषण शामिल हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश स्थित एक स्तूप में बुद्ध के अवशेषों के साथ दफन माना जाता है।
- Prime Minister Narendra Modi inaugurated the exhibition where these relics were formally displayed in New Delhi.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इन अवशेषों की औपचारिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- The gems, dating back to around 200 BC, were discovered in 1898 by British colonial engineer William Claxton Peppe.
- लगभग 200 ईसा पूर्व के माने जाने वाले इन रत्नों की खोज 1898 में ब्रिटिश औपनिवेशिक इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने की थी।
- In May 2025, the gems were listed for auction by Sotheby’s in Hong Kong after being put up for sale by Peppe’s great-grandson Chris Peppe.
- मई 2025 में पेप्पे के परपोते क्रिस पेप्पे द्वारा बिक्री के लिए रखे जाने के बाद इन रत्नों को हांगकांग में सोथबीज़ द्वारा नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया गया।





**Ques: Which countries have been elected as non-permanent members of the United Nations Security Council (UNSC) for a two-year term?**

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य के रूप में दो वर्ष के कार्यकाल के लिए किन देशों को चुना गया है?

- A) Algeria, Guyana, Republic of Korea, Sierra Leone, Slovenia / अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया
- B) Denmark, Greece, Pakistan, Panama, Somalia / डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया
- C) Bahrain, Colombia, Democratic Republic of Congo, Latvia, Liberia / बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया, लाइबेरिया
- D) China, France, Russia, United Kingdom, United States / चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका
- E) India, Brazil, Germany, Japan, South Africa / भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका

**Answer: Option C**

**Explanation | व्याख्या:**

- Bahrain, Colombia, the Democratic Republic of Congo, Latvia and Liberia have been elected as non-permanent members of the UNSC for a two-year term.
- बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया को UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में दो वर्ष के लिए चुना गया है।
- These countries replaced Algeria, Guyana, the Republic of Korea, Sierra Leone and Slovenia, whose terms ended recently.
- इन देशों ने अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ।
- They will serve alongside Denmark, Greece, Pakistan, Panama and Somalia till the end of 2026, and the five permanent members.
- ये देश 2026 के अंत तक डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया तथा पाँच स्थायी सदस्यों के साथ कार्य करेंगे।
- India has served as a non-permanent member of the UNSC eight times, most recently during 2021–22.
- भारत आठ बार UNSC का अस्थायी सदस्य रह चुका है, जिसमें सबसे हालिया कार्यकाल 2021–22 था।





## About the United Nations Security Council :

- Established : 1945
- HQ : New York City, U.S.
- Presidency : Somalia (January 2026)



EXAM  
Genius





**Ques: What is the name of the first community radio station launched along the Line of Control (LoC) in Jammu and Kashmir to improve communication with border communities?**

सीमा से सटे समुदायों के साथ संचार और सूचना पहुंच बढ़ाने के लिए जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास शुरू किए गए पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है?

- A) Radio Udaan / रेडियो उड़ान
- B) Radio Sangam / रेडियो संगम
- C) Radio Seema / रेडियो सीमा
- D) Radio Kashmir / रेडियो कश्मीर
- E) Radio LoC / रेडियो एलओसी

**Answer: Option B**

**Explanation | व्याख्या:**

- The Indian Army, in collaboration with the civil administration and local residents, launched "Radio Sangam," a community radio station at Keri village in the Doongi block of Rajouri district, Jammu and Kashmir.
- भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन और स्थानीय निवासियों के सहयोग से जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के डूंगी ब्लॉक स्थित केरी गांव में "रेडियो संगम" सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया।
- It is the first community radio station established along the Line of Control to enhance information outreach and communication with border communities.
- यह नियंत्रण रेखा के पास स्थापित पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जिसका उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में सूचना और संचार को सुदृढ़ करना है।
- Radio Sangam broadcasts on 88.8 FM frequency from Keri village.
- रेडियो संगम केरी गांव से 88.8 एफएम फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है।





**Ques: The 9th National Siddha Day observed on 6 January commemorates the birth anniversary of which ancient sage?**

6 जनवरी को मनाया गया 9वां राष्ट्रीय सिद्ध दिवस किस प्राचीन ऋषि की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है?

- A) Sage Charaka / ऋषि चरक
- B) Sage Sushruta / ऋषि सुश्रुत
- C) Sage Patanjali / ऋषि पतंजलि
- D) Sage Dhanvantari / ऋषि धन्वंतरि
- E) Sage Agathiyar / ऋषि अगस्त्य

**Answer: Option E**

**Explanation | व्याख्या:**

- The 9th National Siddha Day was observed on 6 January to commemorate the birth anniversary of Sage Agathiyar, who is regarded as the father of the Siddha system of medicine.
- 9वां राष्ट्रीय सिद्ध दिवस 6 जनवरी को ऋषि अगस्त्य की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया, जिन्हें सिद्ध चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है।
- The theme of National Siddha Day 2026 was “Siddha for Global Health.”
- राष्ट्रीय सिद्ध दिवस 2026 का विषय “वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध” था।
- The Vice President of India, C. P. Radhakrishnan, inaugurated the 9th Siddha Day celebrations at Kalaivanar Arangam in Chennai, Tamil Nadu.
- भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के चेन्नई स्थित कलैवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन किया।

